असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

05 मार्च, 2021

सप्तदश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 05 मार्च, 2021 ई0
द्वितीय सत्र — 14 फाल्गुन, 1942(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । श्रीमती संगीता कुमारी । मंत्री स्वास्थ्य विभाग ।

प्रश्नोत्तर-काल

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आसन से बार-बार निदेश होता है तो माननीय मंत्री जी का ऑनलाइन जवाब आया है और नहीं आया है तो आसन से कड़ा निदेश दीजिए, स्थगित करा दीजिए, दूसरे दिन आयेगा । महोदय, आसन के निदेश का पालन मंत्री लोग नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको आप देख लें कि आपके विभाग से ऑनलाइन जवाब आये- 50 परसेंट ऑनलाइन जवाब आया, 50 परसेंट नहीं आया है, आगे से आप अपने यहां देखवा लें । आप पढ़ें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आसन का निदेश बार-बार होता है तो आसन से यह नियमन जाय कि.....

अध्यक्ष : आपको जानकारी होनी चाहिए कि 6 में 4 आ गया है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं । जब प्रश्न का जवाब विभाग से आता है तो मंत्री उसकी समीक्षा करते हैं और कहीं-कहीं त्रुटि रहती है तो उसमें सुधार होता है, इसमें समय लगता है । इसमें माननीय सदस्य को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए ।

श्री ललित कुमार यादव : सरकार भी पुरानी है तो सरकार को भी सीखना चाहिए कि आसन का जो निदेश होता है उसका पालन होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अरे, आपका पूरा जवाब तैयार करके लाये हैं, सुनियेगा न ।

श्री सतीश कुमार : जिनका जवाब ऑनलाइन नहीं आ पाता है उनका ऑनलाइन जवाब आने की उम्मीद है कि नहीं ?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : आयेगा ।

अध्यक्ष : सभी का जवाब आयेगा ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-31(श्रीमती संगीता कुमारी)क्षेत्र सं0-204 मोहनियां

श्री मंगल पण्डेय, मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है ।

2 एवं 3- वस्तुस्थिति यह है कि विभाग द्वारा इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 625 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं 77 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों एवं 183 दंत चिकित्सकों का पदस्थापन किया गया है । विगत वर्ष कुल 6293 ए0एन0एम0 की नियुक्ति विभिन्न जिलों में की गयी । सिविल सर्जन द्वारा आवश्यकतानुसार 202 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इनका पदस्थापन किया गया है । राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त 2632 सामान्य चिकित्सा पदाधिकरी एवं 3706 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है । 1772 प्रयोगशाला प्रावैद्यिकी पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन की कार्रवाई की जा रही है ।

श्रीमती संगीता कुमारी : महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहती हूँ कि मोहनियां विधान सभा में अनुमंडल हास्पीटल है वहां डाक्टर्स की कमी है और आयेदिन गर्भवती महिलाएं मर जाती है । आप देख लेंगे वहां सिर्फ 5 डाक्टर ही हैं और मैंने जब बात की कि वहां कितने होने चाहिए तो वहां के हास्पीटल ने कहा.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, क्या पूरक है ?

श्रीमती संगीता कुमारी : महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ कि डाक्टर्स की कमी है और एक भी स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, वह काम जी0एन0एम0 और ए0एन0एम0 करती हैं महिलाओं को हैंडिल करती हैं । चाहे वह न्यूरो का हो, गायनी का हो, नर्सिंग स्टाफ को हो सबकी हास्पीटल में कमी है ।

अध्यक्ष : जवाब तो दे ही दिये, बता दिये ।

श्रीमती संगीता कुमारी : कब तक यह रिक्ति पूरी होगी ?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग से नाम चयनित होकर आयेगा, बहाली कर दी जायेगी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि तकनीकी सेवा आयोग को कब अनुरोध किया गया, कितना विलंब हुआ और विलंब होने का कारण क्या है ? ये समय सीमा बतावें कि कब तक ये कर देंगे ?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जनवरी के अंतिम सप्ताह में और फरवरी के प्रथम सप्ताह में दो बार अधियाचना भेजी गयी है सामान्य चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए और सामान्यतः तकनीकी सेवा आयोग ने जैसे पिछली बार किया था, कुल लगभग 5-6 महीने में प्रकिया पूर्ण होती है उनको चयन करने में, उनका चयन होकर सूची आयेगा, चूंकि वे हमसे नियंत्रित नहीं है । चयनित होकर आयेगा तो हम नियुक्ति कर देंगे ।

श्री सुधाकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 2012 की योजना है जो 202 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन 2015 में बनकर तैयार हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर दिया, स्वास्थ्य मंत्रालय 2015 से.....

अध्यक्ष : आप अलग विषय पर चले गये ।

श्री सुधाकर सिंह : महोदय, इसी पर है, 2015 से बना हुआ है यह और 2015 से लेकर अब तक किसकी लापरवाही से अब तक नियुक्ति नहीं हुई यह हम जानना चाहते हैं । यह तो जवाब आता ही है कि कर देंगे, कर देंगे ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य बढ़िया और बेहतर तरीके से अध्यन करेंगे तो अच्छा होगा । मेरा आग्रह होगा कि जब हम जवाब दें तो थोड़ा मन से सुनें भी मैंने शुरू में ही कहा कि विभाग द्वारा इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 625 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं 77 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों एवं 183 दंत चिकित्सकों का पदस्थापन किया गया है । विगत वर्ष कुल 6293 ए0एन0एम0 की नियुक्ति विभिन्न जिलों में की गयी है और सिविल सर्जन के द्वारा आवश्यकतानुसार उन 202 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इनका पदस्थापन किया गया । यह तो मैंने स्पष्ट बताया है ।

श्री नीतीश मिश्रा : महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग इनके अधीन नहीं है, प्रायः 5 से 6 महीने लगते हैं तो क्या इनके स्तर से कोई ऐसा समन्वय स्थापित करके व्यवस्था की जा सकती है कि पूरा प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो क्योंकि एक तरफ हास्पीटल भवन बनते जा रहे हैं, लेकिन समय के अंदर नियुक्ति नहीं होने के कारण वह हास्पीटल एक तरह से निष्फल व्यय हो जाता है ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पहले बिहार लोक सेवा आयोग से चिकित्सकों की नियुक्ति होती थी जिसमें सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि

कई-कई वर्ष लग जाते थे । इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर बिहार तकनीकी चयन आयोग की स्थापना दो साल पहले की गयी ताकि इन नियुक्तियों को हम शीघ्रताशीघ्र कर सकें और चयन की प्रक्रिया जल्द की जा सके । इसीलिए बिहार तकनीकी चयन आयोग बना और बिहार तकनीकी चयन आयोग के साथ स्वास्थ्य विभाग का संपर्क निरंतर बना रहता है और हम भी, हमारे जो अधिकारी हैं वहां के जो सचिव हैं उनके साथ संपर्क बनाये रखते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि शीघ्रताशीघ्र चयन की प्रक्रिया पूरी की जाय ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-32(श्री ललित कुमार यादव)क्षेत्र सं0-82 दरभंगा ग्रामीण

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : ठीक से सुनियेगा ललित जी ।

श्री ललित कुमार यादव : आप जवाब ठीक से दीजियेगा तो ठीक से सुनेंगे ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : 1-अंशतः स्वीकारात्मक है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में निबंधित एलोपैथिक चिकित्सकों की संख्या लगभग 40100 के करीब, आयुष चिकित्सा के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या लगभग 33922, होमियोपैथी चिकित्सक की संख्या 34257, युनानी चिकित्सकों की संख्या 5203, दंत चिकित्सकों की कुल संख्या 6130 तथा नर्स की संख्या 31414 है । राज्य में मानक के अनुरूप चिकित्सक, नर्स एवं अन्य मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 11 नये मेडिकल कॉलेज, 23 नये जी0एन0एम0 स्कूल, 54 नये नर्सिंग स्कूल तथा 28 नये पारा मेडिकल संस्थान खोले जा रहे हैं । यह प्रयास किया जा रहा है कि मानक के अनुरूप चिकित्सक, नर्स एवं पारा मेडिकल मानव संसाधन उपलब्ध हो जाय । नये संस्थानों को खोले जाने से आनेवाले समय में इनकी संख्या में वृद्धि होगी । राज्य सरकार द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2020 में माह जुलाई से सितम्बर तक कुल 929 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी एवं 3186 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति कर आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया है । वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात कुल 6338 पद रिक्त हैं । उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी । राज्य में स्टाफ नर्स ग्रेड ए के

कुल 14198 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 10165 स्टाफ नर्स ग्रेड ए कार्यरत हैं । 9130 स्टाफ नर्स ग्रेड ए की अधियाचना बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गयी थी उसमें से 5097 की अनुशंसा अभी तक प्राप्त हो चुकी है जिनका पदस्थापन भी किया जा चुका है । शेष की अनुशंसा प्राप्त होते ही पदस्थापित किया जायेगा । विदित हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदागत पदों पर चयन नियोजन की कार्रवाई की जा रही है । राज्य में चिकित्सक तथा नर्सों के स्वीकृत पद बल के विरूद्ध उपलब्धता तथा अद्यतन कार्रवाई के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है । विशेषज्ञ चिकित्सक स्वीकृत 814 उपलब्ध 113 रिक्ति 701, रिक्त पदों पर रोस्टर का निर्धारण कर, रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । सामान्य चिकित्सक 915 उपलब्ध बल 289 रिक्ति 626, 234 मेडिकल अफसर ए0पी0एच0सी0 तथा 103 मेडिकल अफसर पार्ट टाइम के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है ।

क्रमशः

टर्न-2/ज्योति/05-03-2021

क्रमशः

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : नियोजन की कार्रवाई की जा रही है । दंत चिकित्सक स्वीकृत 9 उपलब्ध 7 रिक्ति 2, रिक्त पदों पर रोस्टर का निर्धारण कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । स्टाफ नर्स 5236, 421 कार्यरत, 4815 रिक्ति, 4102 पदों के लिए विज्ञापन किया गया है । नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । शेष रिक्त पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई चल रही है । आबादी के बढ़त के अनुरुप राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है जिसमें मानक के अनुरुप मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने हेतु सरकार सतत् प्रयासरत एवं कृतसंकल्पित है ।

अध्यक्ष : अब चलिए इतना विस्तृत आंसर आ गया ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इतना विस्तृत जवाब तो आया लेकिन प्रश्न को देखा जाय महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा कि आपका डब्लू.एच.ओ. का जो गाईडलाईन्स है कितना डॉक्टर्स, कितना नर्स जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए तो माननीय मंत्री जी ने उसके संबंध में कोई जवाब नहीं दिया जो प्रश्न के मूल में है, वह देखा जाय । मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि आपके मानक के अनुरुप जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टर एवं नर्स की बहाली आप कब तक करियेगा ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने विस्तार से जानकारी दी माननीय सदस्य को, आपके माध्यम से और सदन को वह इसीलिए दिया कि मानक के अनुरुप कितने चिकित्सक हमारे राज्य

में है उसकी पूरी जानकारी सदन के माध्यम से राज्य को होना चाहिए । जो बिहार कौन्सिल औफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन का हमारे पास अधिकृत पत्र है उसके अनुसार 40,149 चिकित्सक अभी है । उसके अलावे जो होमियोपैथिक कौन्सिल से प्राप्त सूची है उसके अनुसार 34,257 डौक्टर हैं और जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो 33,922 डौक्टर हैं, यूनानी चिकित्साक 5203 हैं , दंत चिकित्सक भी है, ये सुने तो, कुल संख्या जो होती है महोदय, यह चिकित्सकों की संख्या लगभग 1 लाख 19 हजार होती है और मेरा पूरा सुन लिया जाय और डब्लू.एच.ओ. का जो मानक है जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने भी किया है और डब्लू.एच.ओ. का पत्र भी लाया हूँ तो जो मानक है उसके अनुसार 1 हजार पर एक चिकित्सक होना चाहिए । हमारे राज्य की आबादी लगभग 12 करोड़ है उसके अनुसार हमारे राज्य के अंदर 1 लाख 20 हजार चिकित्सक होने चाहिए और आज एक लाख 19 हजार चिकित्सक है और उसके बाद से संख्या बढ़ाने के लिए हम मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा रहे हैं उसकी जानकारी हमने दी है । और यह एक सतत प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत हम लगातार काम कर रहे हैं हमने पूरी जानकारी दी और आगे जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसके बारे में भी बताया ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, ये हमको अनुपात भी बताये ।

अध्यक्ष : बता तो दिए जितना मानक है उससे ज्यादा चिकित्सक है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, वह कहाँ बता रहे हैं डब्लू.एच.ओ. का क्या गाईडलाईन्स है?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट बताया । अनुपात सुन लीजिये ।

अध्यक्ष : अब दूसरा प्रश्न होने दीजिये, बैठ जाईये । श्री समीर कुमार महासेठ ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-33 श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36, मधुबनी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1- अस्वीकारात्मक है । मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार योजनाओं के चयन के सिद्धांत के अनुसार प्रति विधान मंडल सदस्य प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये की सीमा तक योजनाओं की अनुशंसा करने का प्रावधान था परन्तु विभागीय संकल्प संख्या 3924, दिनाँक 10 अगस्त, 2018 के द्वारा इस कार्यक्रम के तहत प्रति विधान मंडल सदस्य वित्तीय वर्ष 2018-19 से तीन करोड़ रुपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशंसा का प्रावधान किया गया है ।

2- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या 3210, दिनाँक 22 जून, 2016 की कंडिका 6 'क' में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत प्रतिबंधित कार्यों

की दृष्टांत सूची वर्णित है, जिसमें व्यक्ति विशेष, अंशदान, अनुदान एवं ऋण सम्मिलित है।

यहॉ उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का शुभारम्भ वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से किया गया था । इस कार्यक्रम के तहत विधान मंडल के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर विकास से संबंधित योजनओं का कार्यान्वयन करने का प्रावधान है । इस कार्यक्रम के तहत किसी गरीब व्यक्ति को चिकित्सा अथवा शैक्षणिक फीस के लिए प्रावधान नहीं किया जा सकता है और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है क्योंकि इस तरह का प्रावधान करना इस योजना के मूलभूत उद्देश्य के प्रतिकूल होगा ।

3- उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, प्रश्न पूछिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूं कि 2016 से अबतक इस मार्गदर्शिका में कितने संशोधन हुए हैं और कंडिका-6 में वर्णित प्रतिबंधित सूची में से कितने को बाहर किया गया है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कोई औचित्य नहीं है । मुख्यमंत्री विधायकों के लिए क्षेत्रीय विकास योजना है इसमें अनुदान या ऋण का किसी और चीज का इन्कलुजन नहीं है । क्षेत्रीय विकास के लिए पहले यह फंड 2 करोड़ था 18-19 में इसको 3 करोड़ किया गया है, अन्य इसमें कोई तरह की चीजें नहीं है जो आपने प्रश्न किया है उसमें लिखा हुआ है कि अभी कोई प्रावधान नहीं है और आगे भी नहीं होगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, जब इतनी बार संशोधन हुए और माननीय मंत्री जी नहीं बता पाए कि कितनी बार संशोधन हुए तो क्या एक बार माननीय सदस्यों के हित में सरकार संशोधन नहीं करना चाहती हैं, तो क्यों, जनता के लिए भी चूँकि होता क्या है आप बहुत करें तो सरकारी हौस्पिटल फिक्स कर दें, बच्चों के लिए कर दें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : क्षेत्रीय विकास में जो संशोधन आप कहियेगा, दीर्जियेगा उसमें विचार किया जायेगा उसमें और योजना जोड़ी जायेगी लेकिन व्यक्ति को देने के लिए कोई योजना नहीं है इसका नाम नहीं है ।

अध्यक्ष : चलिए, आगे विचार किया जायेगा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या 34 श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21, ढाका)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति व्यक्ति 4 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान का भुगतान किए जाने का प्रावधान है ।

सामूहिक सड़क दुर्घटना में घायलों के संबंध में निम्न प्रकार से अनुदान का भुगतान किया जाता है :-

1-हाथ, पैर या आंखों की क्षति होने पर अनुग्रह का भुगतान -

(i) रु0 59,100 प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 40 से 60 प्रतिशत के बीच हो)

(ii) रु0 2.00 लाख प्रति व्यहिक्त (जब विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो ।

2. गंभीर चोट जिसके चलते हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े:-

i- रु0 12,700 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से अधिक हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर)

पप- रु0 4,300 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से कम हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर)

2-ऐसी कोई घटना विभाग के संज्ञान में नहीं है ।

3- आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या 1418, दिनॉक 17 अप्रील, 2015 के अनुसार मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्राकृतिक आपदा के रुप में अधिसूचित करते हुए दिनॉक 20 मार्च, 2015 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान देय है ।

इस प्रकार उक्त दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति के प्रभावित होने पर अनुग्रह अनुदान देय नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक शॉर्ट में पूछिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, उत्तर पढ़ चुके हैं और पूरक ही पूछ रहे हैं तो यह जो दुर्घटना होती है तो उसमें घायल और मृत लोगों की कहीं आपस में पहचान नहीं होती है, मेरा प्रश्न यह है कि मृत व्यक्ति के साथ अगर घायल व्यक्ति की पहचान नहीं होने से कहीं प्राथमिकी दर्ज होती है तो मृतक का परिवार केवल मृतक का नाम देकर छोड़ देते हैं और घायल का नाम तो दूसरी जगह दर्ज कराता नहीं है ।

अध्यक्ष : आप भूमिका नहीं सीधे पूरक पूछिये, बहुत से क्वेश्चन हैं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब के बारे में मेरा यह कहना है कि दूसरे प्रश्न में जो माननीय मंत्री जी का जवाब है उसके बारे में मेरे पास एक नाम है नाम - मुरारी

सिंह, ग्राम- स्वरुपा, पंचायत- बड़हरवा लखनसेन प्रखंड -ढाका, जिला- पूर्वी चंपारण ये 18-3-2020 को इनकी दुर्घटना हुई थी ढाका थाना काण्ड संख्या ..

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, प्रश्न हम उसी पर पूछ रहे हैं कि इनका कहना है कि

अध्यक्ष : क्या पूरक है ? सभी के पास उत्तर मुद्रित है और वे पढ़े हुए हैं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, दूसरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है । अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में हैं तो हम इस चीज को नहीं बतायेंगे । फिर मंत्री जी के..

अध्यक्ष : आप एक बार डिटेल में मंत्री जी ले लीजियेगा ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : बहुत कष्ट के बाद मेरा अल्पसूचित आया है । इसलिए मेरा आग्रह है कि मुझे संरक्षण दियाा जाय ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : पवन जी आप बैठ जाईये हम डिटेल में बतला देते हैं । ये नियम ऑलरेडी पहले से भी आया हुआ है । आपदा विभाग का है कि कोई भी सामूहिक दुर्घटना में यथा सड़क दुर्घटना, वायुययान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, और गैस रिसाव जैसी दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्राकृति4क आपदा के रुप में अधिसूचित करते हुए दिनॉक 20 मार्च, 2015 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रकिक्रया एवं मानदर के सदृश्य अनुदान/अन्य अनुदान देय है । इसमें क्या है कि अगर सामूहिक दुर्घटनार होती है तो होता कया है एक आदमी की मृत्यु हो गयी उसको हम पैसा दे देते हैं लेकिन जिसका एक्सीडेंट होता है उसका पूरा क्लियर नहीं रहता है उसको अगर पेपर का कटिंग होता है तो उसको लेकर अपने स्थानीय डी.एम. को दीजिये और डी.एम. वहॉ से डिमान्ड करेगा जिसिमें लिखा हुआ है उसमें अलग अलग क्षेत्र में है जैसे हर व्यक्ति जिसिके बारे में आप लिखते हैं कि हाथ कट गया, पैर कट गया, अगर कोई क्षति हो गयी तो उसमें अनुदान राशि में देय है कि प्रति व्यक्ति अगर विकलांगताअगर हो गयी 40 से 60 प्रतिशत हो गयी तो उसमें इसतरह का किया जाता है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, उत्तर हम पढ़े हैं मेरा यह कहना है कि दूसरा के जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है मेरा यह कहना है कि मुरारी सिंह की मृत्यु हो गयी सड़क दुर्घटना में 18-3-2020 को ढाका थाना में 381/2020 दर्ज हुआ जो घायल व्यक्ति था जब बाद में पता चला कि उसमें घायल है तो थाना में आवेदन देता है कि हम घायल थे और हमरा नाम शामिल किया जाय अभी तक शामिल नहीं हो पाया इसके चलते मृतक के परिजनों को चार लाख मिला नहीं यह त्रुटि

मेरा यह कहना है । अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी, आवेदन देने वाले लोगों का नाम सूची में शामिल करना चाहते हैं कि नहीं है। घटना के दो दिन चार दिन बाद यह संज्ञान में आता है तो वैसे लोगों के आवेदनल देने पर उनरका नाम सम्मिलित होगा कि नहीं, चूँकि सम्मिलित नहीं होने पर मृतक के परिजनों को पैसा नहीं मिलता ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसी अगर घटना होती है और अगर उसके साथ किसी की दुर्घटना हुई है उसका नाम अगर पेपर के माध्यम से आप निकालेंगे उसके एक महीने के बाद डी.एम. के द्वारा लिखित आयेगा तो उसके बाद उसको पैसा मिलेगा ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, कहीं भी आपदा प्रबंधन विभाग के नियम में दो मृत्यु या दो घटना की चर्चा नहीं है । सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु परमौत पर अनुदान देने का प्रावधान है । सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर अनुदान देने का प्रावधान है । कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि दो मृत्यु होना चाहिए या दो आदमी को घायल होना चाहिए । एकल मृत्यु

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये कि कहना क्या चाहते हैं ?

श्री चन्द्रशेखर : जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि नियमानुसार अगर सामूहिक सड़क दुर्घटना में एकल मृत्यु की चर्चा नहीं है मने नियम में यानी आपदा प्रबंधन के नियम में तो क्या सरकार एकल मृत्यु पर सामूहिक दुर्घटना में अनुदान देने की कृपा करेगी ?

टर्न-3/पुलकित-अभिनीत/05.03.2021

अध्यक्ष: आप पूछ ही लिये हैं तो अब क्या पूछेंगे ? आप बोलिये, एक बार बोलेंगे तब मंत्रीजी बोलेंगे, क्योंकि सबका सामूहिक भाव है ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, सरकार इतनी क्रूर क्यों है ?

अध्यक्ष: आप भूमिका मत बनाइये । पहले आप पूरक पूछिये, क्रूरता का निर्णय आप नहीं लीजियेगा, पहले आप पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, यह सरासर मानवता का मामला है । अगर किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, जब हमलोग जाते हैं तो हम लोग यह कह दें कि एक और घायल हो जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिये, समय नहीं है । माननीय सदस्यगण, सुन लीजिये, जो भी भूमिका बनायेंगे उनको हम अवसर नहीं देंगे । आप पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूं, नियम यह है कि सामूहिक दुर्घटना, विधान सभा में नियम हमलोगों को पता है । क्या यह सामूहिक शब्द हटाना चाहती है सरकार ? अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और पूरक है, मेरा अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष: आप बोलिये, सत्यदेव राम जी ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, सामूहिक सड़क दुर्घटना की चर्चा है किंतु सामूहिक चर्चा कहीं नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, वही मैं बोल रहा हूँ और ऐसी स्थिति बनती है कि एक मर गया और एक घायल हो गया ये सामूहिक शब्द हटाकर....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप सभी का भाव एक ही है ।

श्री संजय सरावगी: क्या सरकार नियम में परिवर्तन करके.....

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम: महोदय, जो सामूहिक सड़क दुर्घटना होती है तो एक व्यक्ति पर भी मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया जाय ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । बैठ जाइये पहले, हम कुछ नहीं सुनेंगे, जब तक आप सभी नहीं बैठेंगे । सभी माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये और जिनको आसन अनुमति देगा वही बोलेंगे । आपकी भावना से सरकार अवगत हो चुकी है, एक आदमी बोलेंगे तो माननीय मंत्रीजी सुनेंगे । आप बार-बार हाथ मत उठाइये ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, इतनी देर से माननीया उप मुख्यमंत्री जी बैठी हुई हैं, समझ गयी होंगी कि सारे सदस्यगण क्यों उठ रहे हैं ?

अध्यक्ष: हां, सुरेन्द्र जी । माननीय सदस्यगण उठ गये, अब माननीय मंत्रीजी । अब जो सदस्य बोल चुके हैं, वे बार-बार न उठें । आप बताइये सत्यदेव जी, एक लाईन में ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मुझे एक लाईन में कहना है कि एकल मृत्यु पर भी मुआवजा मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष: सभी का भाव यही है, माननीय मंत्रीजी आप बताइये ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री: महोदय, अभी तक जो नियम है, जो सामूहिक दुर्घटना होती है उस दुर्घटना में अगर किसी की मौत हुई और कुछ लोग घायल हुए तो उन्हें पैसा मिलता है

लेकिन एकल अगर मृत्यु हुई तो उसमें पैसा देय नहीं है । माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप उठेंगे तो माननीया मंत्रीजी कैसे आवाज सुनेंगी । शांति बनाये रखिये । सुनिये ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री: माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए हमलोग उस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है । सरकार विचार करेगी आपकी भावनाओं पर । गंभीरता से संज्ञान में लिया है ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-35 (श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र सं0- 166, जमालपुर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि कोविड-19 बीमारी की जांच के लिए रेपिड एंटीजन किट से जांच की जा रही है । यह जांच आई0सी0एम0आर0 के द्वारा सेन्सिटीवी एवं सेपेस्पिक के परीक्षण एवं वैलिडेशन के बाद अनुशंसित किया गया । आई0सी0एम0आर0 से अनुशंसित निर्माताओं के द्वारा तैयार रेपिड एंटीजन टेस्ट किट का ही क्रय देश के अन्य राज्यों की भांति इस राज्य में भी किया गया है, जिसकी अधिप्राप्ति से संबंधित विवरणी निगम की वेबसाईट www.bmsicl.gov.in पर पारदर्शिता हेतु प्रकाशित है । प्रश्न में वर्णित त्रुटि का कोई दृष्टांत प्रकाश में नहीं आया है ।

अध्यक्ष: ठीक है, अब समय समाप्त हो गया, आप लोग एक ही प्रश्न पर काफी समय ले चुके हैं । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य, श्री नीतीश मिश्रा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-439 'अ' (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र संख्या- 38, झंझारपुर)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2019 में कमला नदी का बांध टूटने से नरूआर पंचायत के उसराहा टोल में 46 परिवार तथा ओझौल के पास बांध टूटने से गोपलखा में दो परिवारों के घर कट गये थे । प्रभावित परिवारों को निम्न प्रकार से सहायता राशि का भुगतान किया गया है:-

गृह क्षति अनुदान- 48 परिवार, 95100 रुपया । दूसरा है अनुग्रह राशि अनुदान -48 परिवारों को 6 हजार रुपया करके राशि दिया गया है । बाढ़ में कटे 46 परिवारों को 5 डिसमिल जमीन की दर से 2 एकड़ 30 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया है । ओझौल के दो परिवारों को बाढ़ से कटी जमीन पर जल संसाधन विभाग द्वारा मिट्टी भराई का कार्य किया गया है ।

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्रीजी को यह जानकारी भी देना चाहूंगा और यह पूछना भी चाहूंगा कि लगभग 51 परिवार नरूआर में जल संसाधन विभाग का जो निरीक्षण भवन है वहां पर विगत डेढ़ वर्षों से रह रहे हैं । जितनी बातें इन्होंने कही हैं, उनको सहायता मिली है लेकिन जो जमीन उनको दी गयी है उस जमीन में दो कठिनाई है । एक तो उसमें बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसके कारण वे जा नहीं सकते हैं और दूसरा वह जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं है । जमीन देने के बाद भी मेरा मूल प्रश्न यही है कि नरूआर के 51 परिवार जो विस्थापित है, जमीन भले दी गयी है लेकिन व्यावहारिक रूप से वह उनके उपयोग में नहीं है । डेढ़ वर्ष बीत गये हैं महोदय, एक समय-सीमा के अंदर वो जमीन....

अध्यक्ष: आपका पूरक है, समय-सीमा ।

श्री नीतीश मिश्रा: जी, समय-सीमा के अंदर वो जमीन में बस सकें, मेरा बस इतना ही आग्रह, निवेदन और प्रश्न है ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री: इसमें हमारे पास जो गृह क्षति अनुदान था वो भी हम दे दिए हैं और जो बाढ़ से जमीन कटी थी, जल संसाधन विभाग ने उस जमीन में मिट्टी भरवायी है अगर उसमें कमी है, माननीय सदस्य के द्वारा तो निश्चित रूप से हम उन्हें फिर लिखित भेज देंगे और वहां पर जो काम हैं वे हो जायेंगे । बाकी सारे अनुदान उनके पूरे हो गये हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1078 (श्री विद्या सागर केशरी, क्षेत्र संख्या- 48, फारबिसगंज)

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है, आप पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री विद्या सागर केशरी: अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल के चारों ओर पूरा गड्ढ़ा है और मनरेगा के माध्यम से..

अध्यक्ष: उत्तर दे दिया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में कार्रवाई की जायेगी ।

श्री विद्या सागर केशरी: महोदय, उत्तर हमलोगों को नहीं मिला है ।

अध्यक्ष: ऑनलाईन जब उत्तर जब हम डलवा रहे हैं इतनी सख्ती के साथ तो आपको देखना पड़ेगा। पढ़ दीजिये, माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

2 एवं 3- स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 649(10), दिनांक 03.03.2021 द्वारा बी0एम0एस0आई0सी0एल0 को स्थल निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया है । प्रतिवेदन

के आलोक में मिट्टी भराई अथवा नये भवन के निर्माण पर विचार करते हुए अगले वित्तीय वर्ष में कार्रवाई की जायेगी ।

श्री विद्या सागर केशरी: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: अब हो गया, उत्तर तो स्पष्ट है ।

श्री विद्या सागर केशरी: महोदय, हमलोगों ने चहारदीवारी की भी मांग की है । चहारदीवारी कब तक कराने का विचार रखती है ।

अध्यक्ष: ठीक है । संज्ञान में ले लिए हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1079 (श्री सतीश कुमार, क्षेत्र संख्या- 218, मखदुमपुर)

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है, पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री सतीश कुमार: महोदय, हमने देखा है इसका उत्तर ऑनलाईन नहीं आया हुआ है ।

अध्यक्ष: हमलोगों के पास इसका जवाब आया हुआ है । पढ़ दिया जाय माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी से प्रभावित बच्चे चिकित्सा संस्थानों में कभी-कभी आते हैं ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह यह है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी का कोई सटीक इलाज अब तक उपलब्ध नहीं है । यह एक जन्मजात एवं अनुवांशिक बीमारी है । इस बीमारी से प्रभावित बच्चों का जीवन-काल लगभग 12 से 15 वर्ष का होता है । कुछ उपलब्ध दवाओं के द्वारा उक्त बीमारी को रोकने का प्रयास किया जाता है । उक्त बीमारी में कुछ हद तक फिजिओथेरपी चिकित्सा से भी लाभ होता है, जिसकी सुविधा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में उपलब्ध है । उक्त बीमारी के उपचार के संबंध में स्टेम सेल थेरपी पर शोध कार्य चल रहा है । इस संबंध में शोध को गति देने व इसके परिणामों, अनुंशासाओं से अवगत कराने हेतु व्यक्तिगत रूप से माननीय केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से भी आग्रह किया गया है ।

3- मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी के इलाज के संबंध में विस्तृत शोध संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

टर्न-4/हेमन्त-धिरेन्द्र/05.03.2021

श्री सतीश कुमार : महोदय,...

अध्यक्ष : अब तो इतना विस्तृत उत्तर दे दिया गया है, सारा क्लीयर है ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, कुछ भी क्लीयर नहीं है ।

अध्यक्ष : अच्छा, आप क्लीयर करिये, बताइये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, दो हजार में से एक बच्चे को यह बीमारी हो रही है और उसमें चलने-फिरने से वह लाचार हो जाते हैं, उसका विकलांग प्रमाण-पत्र....

अध्यक्ष : पूरक क्या है, वह पूछिये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, विकलांग प्रमाण-पत्र बनेगा या नहीं बनेगा, एक सुई 16 लाख रुपये की आती है । महोदय, तो उस सुई की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में सरकार करेगी या नहीं करेगी ? यही सवाल है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि यह बीमारी एक गंभीर प्रकार की बीमारी है । जिसके संबंध में संपूर्ण दुनिया में शोध चल रहा है और इस बीमारी....

अध्यक्ष : विकलांगता सर्टिफिकेट बनेगा कि नहीं बनेगा, यह इनका पूछना है ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : विकलांगता सर्टिफिकेट के संबंध में मैं एक बार जानकारी प्राप्त करूंगा....

अध्यक्ष : ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं । डॉ0 सत्येन्द्र यादव ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : और जानकारी प्राप्त करके सदन को बताऊंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वह जानकारी प्राप्त कर लेंगे, आपको बता देंगे ।

(व्यवधान)

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : अभी तक कोई भी निश्चित दवा इस बीमारी के लिए नहीं बनी है, मैंने जवाब में भी बताया शोध कार्य चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है । मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से बात की है, निश्चित रूप से गंभीर है, मैंने तभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में बात की है ।

अध्यक्ष : ठीक है । डॉ0 सत्येन्द्र यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1080(डॉ0 सत्येन्द्र यादव, क्षेत्र सं0-114, माँझी)</u>

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : उत्तर मुद्रित नहीं है ।

अध्यक्ष : आप तो डॉ0 सत्येन्द्र यादव हैं, ऑनलाईन क्यों नहीं देखते हैं ?

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : ऑनलाईन नहीं है ।

अध्यक्ष : ऑनलाईन निकला हुआ जवाब यहां पर है ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : जी मैंने देखा नहीं है ।

अध्यक्ष : बता दीजिए, माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ललित जी को आरोप वापस लेना चाहिए । ऑनलाईन आ गया है और माननीय सदस्य पढ़ते नहीं हैं ।

(व्यवधान)

बैठिये, बैठिये । अब आप, चलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : ऑनलाईन में कहीं एरर आता है, कहीं कुछ आता है ।

अध्यक्ष : अभी डेढ़ सौ, दो सौ का जवाब, सबको लगाया जायेगा । ऑनलाईन देखने की आदत बनायें, सभी को पी0ए0 मिला हुआ है ।

(व्यवधान)

163 में 113 का ऑनलाईन जवाब आया हुआ है, लगभग 70 परसेंट ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आपका आदेश है । सारण जिला के अंतर्गत....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सारण जिला के अंतर्गत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाईजी एवं मीटर रीडर के द्वारा स्पॉट बिलिंग के माध्यम से विद्युत विपत्र निर्गत किया जाता है । उपभोक्ता का परिसर बंद रहने या अन्य किसी कारणवश विपत्रीकरण नहीं हो पाने की स्थिति में, अगले माह उसका विद्युत विपत्र निर्गत किया जाता है । विदित है कि वर्तमान में सभी उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है । इसके उपरान्त भविष्य में इस तरह की शिकायतों की संख्या कम हो जाएगी।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा सवाल है कि मीटर रीडिंग करने का काम गांवों में फ्रेंचाईजी कम्पनी करती है और फ्रेंचाईजी अपने कर्मचारी को उपभोक्ता के घर नहीं भेजती है । चार-चार महीने, पांच-पांच महीने के बाद बिल जाता है और बिल में चक्रव्रद्धि ब्याज जोड़ दिया जाता है और इसके चलते उपभोक्ता को कठिनाई होती है । इसलिए मंत्री महोदय से मेरा साफ कहना है कि गलती फ्रेंचाईजी और डिपार्टमेंट की है, चक्रव्रद्धि ब्याज उपभोक्ता क्यों देगा ? इसलिए इस चक्रव्रद्धि ब्याज की प्रक्रिया को समाप्त किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाये जा रहे हैं, एक लाख के करीब लग भी चुके हैं । अगले डेढ़-दो साल के भीतर का टारगेट है । जैसे मोबाईल में

पैसा जमा कीजिए, मोबाईल चलेगा । 24 घंटे पहले सूचना जायेगी कि आपका बिल समाप्त हो गया, वह ऑटोमेटिक होगा । ये समस्याएं दूर हो जायेंगी ।

अध्यक्ष : लेकिन जब तक नहीं लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के संदर्भ में सुधार की प्रक्रिया क्या है?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जो ऐसे उपभोक्ता हैं, वह लोक शिकायत में चले जायं या हमको आवेदन भेज दें, उसकी जांच करायी जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इन्होंने बता दिया कि इनके पास भी संज्ञान में आयेगा, ये गंभीरता से उस पर कार्रवाई करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है, वह सही नहीं है, चूंकि उसमें इतनी तरह की गड़बड़ियां हैं कि हमलोग तबाह-तबाह हो गये हैं और एक ही कन्ज्यूमर को दो-दो बिल आ रहे हैं ।

अध्यक्ष : अभी तो मंत्री जी ने कहा है कि प्रीपेड मीटर बहुत तेजी से लगा रहे हैं, तो तबाही खत्म हो जायेगी ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इसको कब तक पूरा करेंगे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठिये । माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1081 (श्री अखतरूल ईमान, क्षेत्र सं0-56, अमौर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अर्जुन भिट्टा खाता टोली में कुल 12 परिवार नदी के कटाव से प्रभावित हुये थे, जिसमें से 6 परिवार भूमिहीन श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । जिनका मुआवजा भुगतान एवं पुनर्वास की कार्रवाई एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी ।

वैशाघाट में विभिन्न जगहों से आये कुल 25 परिवार नदी के कटाव से प्रभावित हुये थे, जिसमें से 20 परिवार भूमिहीन श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । जिनका मुआवजा भुगतान एवं पुनर्वास की कार्रवाई एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । पूरक पूछिये ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूँ । मैंने सवाल किया था कि अर्जुन भिट्टा, खाता टोली के 12 परिवार और वैशाघाट के 70 परिवार विस्थापित हैं । माननीय मंत्री जी ने आंशिक तौर पर यह माना है कि वैशाघाट के 25 और अर्जुट भिट्टा, खाता

टोली के 6 परिवार विस्थापित हैं, जो लोग भूमिहीन हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ जो लोग भूमिहीन हैं, उन्हीं को मुआवजा देंगे या मुआवजा की कोई नियमावली है, जिस नियमावली के अनुसार, जिनका कच्चा-पक्का मकान कट गया है, सारे विस्थापितों को मुआवजा देना है । महोदय, यह मामला सिर्फ उन्हीं का नहीं है ....

अध्यक्ष : आप डायरेक्ट पूरक पूछते । आप लंबा करेंगे, तो और लंबा होगा ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, तमाम जो मेचांद टोला, काशीबाड़ी, गरैया, सिमलबाड़ी, लंगड़ा टोली, हरिया, लाल टोली सब लोग तो कटाव में हैं । क्या नियमावली के अनुसार सबके घर के कटाव का पैसा देने का इरादा रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रश्न का साफ उत्तर दिया है कि जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अर्जुन भिट्टा खाता टोली में कुल 12 परिवार नदी में कटाव, इन्होंने लिखा था 70 परिवार लेकिन जो रिपोर्ट आयी है, उसमें मात्र 12 परिवार नदी में कटाव से प्रभावित हुए थे, जिसमें से 6 परिवार भूमिहीन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनका मुआवजा भुगतान एवं पुनर्वास की कार्रवाई एक माह के अंदर कर ली जायेगी और वैशाघाट में भी विभिन्न जगहों से आये कुल 25 परिवार नदी के कटाव से प्रभावित हुए थे, जिसमें 20 परिवार भूमिहीन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं । जिनका मुआवजा भुगतान एवं पुनर्वास की कार्रवाई एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी । कहने का मतलब है कि जो भूमिहीन हैं उनको ही भूमि दी जायेगी, उसके अलावा जो बाकी बचे हैं उनका 6 हजार का है, तो उनको 6 हजार मिलेगा ही, उसमें तो कहीं दो राय है नहीं ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय मंत्री महोदय, जो भूमिहीन हैं, भूमि उनको देना चाहती है । हालांकि वर्ष 2017 में ये लोग विस्थापित हुए हैं और अब तक नहीं हुआ है । लेकिन मामला यह है, मैं यह पूछ रहा हूँ कि जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिनको आपने 12 से घटाकर 6 और 70 से 25 किया है, तो जिन लोगों के घर कटे हैं, आपदा नियमावली के अनुसार, उनके घरों का मुआवजा जो 91 हजार हो रहा है कच्चा और पक्का मकान का, यह देने का इरादा रखती है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठिये । इन्होंने जवाब दे ही दिया है कि मुआवजा भुगतान पुनर्वास की कार्रवाई एक माह के अन्दर की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय ....

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, महोदय, नहीं महोदय, सिर्फ उन्होंने 6 और 25 को माना है...

(व्यवधान)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी से मांग लिया जायेगा ।

(इस अवसर पर ए0आई0एम0आई0एम0 के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : आप बैठिये अपनी जगह पर । आप अपने जगह पर बैठिये । माननीय सदस्य, डॉ0 मेवालाल चौधरी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1082 (डॉ0 मेवालाल चौधरी, क्षेत्र सं0-164, तारापुर)

(लिखित उत्तर)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय फेज-2 के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री अखतरूल ईमान जी, आप अपने स्थान पर बैठिये, उन्होंने जवाब दे दिया । आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । आप अपने स्थान से बोलियेगा, तभी जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के अनुरूप मुंगेर जिला अन्तर्गत रामपुर चौक पर अवस्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर के भवन का जीर्णोद्धार कराया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मेवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

अध्यक्ष : श्री अखतरूल ईमान जी, आप पहले बैठिये अपने स्थान पर । वेल से कोई भी बोली हुई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी और न कोई बात सुनी जायेगी । बैठे रहिये । आप अपने स्थान पर नहीं जाइयेगा, कोई नहीं सुनेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय.....

अध्यक्ष : पहले स्थान पर जाने के लिये कहिये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । आसन के निदेश का पालन कीजिये ।

अध्यक्ष : इस तरह से प्रेशर और दबाव में आसन नहीं सुनेगा । बोलिये, डॉ0 मेवालाल चौधरी, अपना पूरक ।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, महोदय .....

अध्यक्ष : श्री अखतरूल ईमान जी, आपके प्रेशर और दबाव में आसन नहीं आयेगा ।

(इस अवसर पर ए0आई0एम0आई0एम0 के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर चले गये ।)

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, ..

अध्यक्ष : एक मिनट । उनका प्रश्न हो जाने दीजिये । उनका प्रश्न हो जायेगा, तब बोलियेगा ।

टर्न-5/सुरज-संगीता/05.03.2021

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कब तक कर देंगे, चूंकि यह अस्पताल बड़ा जीर्ण-शीर्ण हालत में है । महोदय, समय-सीमा..

(व्यवधान)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : हम दिखवा लेंगे, जिला पदाधिकारी....

अध्यक्ष : आप क्यों ? अभी माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग बोलेंगे । अभी उनका चल रहा है ।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, समय-सीमा तय कर दी जाय । बड़ी हालत खराब है । क्रिटिकल कंडिशन है हॉस्पिटल का ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने जवाब में स्पष्ट लिखा है कि अगले वित्तिय वर्ष में इस कार्य को कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब...

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आप सदन के....

अध्यक्ष : एक चीज पहले । माननीय वीरेन्द्र बाबू बैठ जाइये । एक चीज सुन लीजिए । जब इतनी सहूलियत के साथ हमलोग पूछने दे रहे हैं प्रेशर बनाकर आसन से आप क्वेशचन नहीं करें । शालीनता के साथ बात करेंगे और आसन से सम्मान के साथ बात करेंगे, आसन तभी सुनेगा ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । आपका पहला तो है कि हम जब बोल रहे थे फिर आप उठ क्यों गए ? आप बैठिये । आप बैठ जाइये । यह उचित नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादव : आसन की बात सुन लीजिये ।

अध्यक्ष : यह उचित नहीं है पहली बार है आपका । माननीय मंत्री जी बतायें । बैठ जाइये । आप बार-बार उठ रहे हैं फिर कोई जवाब नहीं आयेगा आपका । बोलिये माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जो जिला पदाधिकारी से रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट का तो हम कर ही दिये हैं लेकिन माननीय सदस्य की अगर बात है तो मैं एक बार जिला पदाधिकारी से फिर पूछूंगी । इन्होंने 70 की संख्या दी है, जिला पदाधिकारी ने 25 की संख्या दी है तो इस हिसाब से यह भी उसी अनुसार से हो जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय सदस्य इतना गंभीर सवाल उठाये हैं और गरीब से संबंधित है, महोदय । माननीय मंत्री जी के जवाब से सहमत हैं हमलोग लेकिन माननीय सदस्य जो कहते हैं हम कहीं के क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हम वस्तुस्थिति जानते हैं । जिला पदाधिकारी, जो कर्मचारी का रिपोर्ट होता है । महोदय..

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि हम जांच करवा लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, प्रश्नकर्ता को वहां के जिला पदाधिकारी दोनों को बैठकर वस्तुस्थिति जो भी हो...

अध्यक्ष : जानकारी ले लीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : सरकार को रिपोर्ट दें ।

अध्यक्ष : श्री हरि नारायण सिंह । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं नियमावली की बात कर रहा हूं...

अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक बोले हैं फिर भी...

(व्यवधान)

आप इतना भावावेश में मत रहिये ईमान जी । ये आपके लिए उचित नहीं । जब मुख्य सचेतक बोले और उन्होंने कह दिया । शांति बनाये रखिये । सदन का हित है शांति से जवाब सुनिये । चलिये । श्री हरि नारायण सिंह जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1083(श्री हरि नारायण सिंह, क्षेत्र सं0-177, हरनौत)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिलान्तर्गत नगरनौसा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्क्रमित करने की योजना स्वीकृत है । आत्मनिर्भर बिहार के 7-निश्चय फेज-2 के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है । अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के अनुरूप चारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री हरि नारायण सिंह : माननीय मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाए रखिये । चन्द्रशेखर बाबू ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1084(श्री विद्या सागर केशरी, क्षेत्र सं0–48, फारबिसगंज)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल एवं उक्त परिसर में स्थित ए0एन0एम0 कॉलेज को चाहरदीवारी निर्माण हेतु बी0एम0एस0आई0सी0एल, पटना द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । प्राक्कलन के आलोक में तथा निजी उपलब्धता के आधार पर अगले वित्तिय वर्ष में निर्माण प्रस्तावित है।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर मामला हम लाना चाह रहे हैं । एक ट्रॉमा सेंटर जो है केंन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत था । इससे अलग बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : अलग नहीं बोलिये, बैठ जाइये समय कम है । आपका चहारदीवारी का प्रश्न था जवाब मिल गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1085(श्री बागी कुमार वर्मा, क्षेत्र सं0–215, कुर्था)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम–बसंतपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी गई है, परन्तु राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका है । आत्मनिर्भर बिहार के 7–निश्चय फेज–2 के तहत इकाई चिन्हित करते हुए कार्य योजना तैयार की जा रही है जिसके तहत इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन का भी निर्माण अगले वित्तिय वर्ष में कराया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1086(श्री विनय बिहारी, क्षेत्र सं0–5, लौरिया)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्न संख्या टन–36 को ज्ञाप संख्या–417, दिनांक–02.03.2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने आपके पर्यटन विभाग को ही भेज दिया है ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : हमने भेज दिया है उनको, उनकी समस्या है ।

अध्यक्ष : वे फिर आपके ही विभाग को भेज दिये हैं । दिखवा लीजिए एक बार । विनय जी ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : महोदय, ये पर्यटन के रोड मैप में है ।

अध्यक्ष : यह प्रश्न स्थगित हुआ । चलिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1087(श्री महबूब आलम, क्षेत्र सं0–65 बलरामपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : 1- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला में बारसोई प्रखंड के करणपुर पंचायत के करणपुर गांव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण हुआ है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- तत्काल सिविल सर्जन, कटिहार को निदेश दिया गया है कि वे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करणपुर में स्थानीय व्यवस्था के तहत चिकित्सक एवं कर्मियों को प्रतिनियुक्त कर इस केन्द्र को 30 दिनों के अन्दर क्रियाशील करें ।

वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है ।

आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार महिला चिकित्सा पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । महबूब जी, पूरक पूछिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, उत्तर के लिए 30 दिन तक प्रतिनियुक्त रहने का निदेश सिविल सर्जन को दिया है मंत्री महोदय ने । महोदय, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । साथ-साथ वर्तमान में विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3 हजार 706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2 हजार 632 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार सरकार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। महोदय, मेरा पूरक है कि आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा कब तक प्राप्त हो जायेगी और कब तक नियुक्त कर देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : बिहार तकनीकी सेवा आयोग से नाम की सूची प्राप्त होते ही उनको पदस्थापित कर दिया जायेगा और नाम से....

श्री महबूब आलम : महोदय, तकनीकी सेवा आयोग से सूची प्राप्त करने की तत्परता और दिलचस्पी सरकार की है कि नहीं है और कब तक यह हो जायेगी महोदय, ये तो भेज चुके हैं ....

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, बहुत अच्छा विषय रखा है । तत्परता और दिलचस्पी इतनी है महोदय कि अभी पिछले ही वर्ष जुलाई से अगस्त के बीच में 4 हजार चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है और फिर 4 महीने के अंदर ही अधियाचना भेज दिया गया है, इतनी तत्परता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी से मिल कर गंभीरता से बात कर लीजिएगा ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सदन को भी जानकारी होनी चाहिए....

अध्यक्ष : अब बता दिये, आगे बढ़ने दीजिए क्वेश्चन है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1088 (श्री अखतरूल ईमान क्षेत्र सं0-56, अमौर)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, उत्तर ऑनलाइन भी नहीं है । अभी भी नहीं हुआ है, हमको नहीं मिल पाया है ।

अध्यक्ष : अब उत्तर तो आया हुआ है, पढ़ दिया जाय माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां जिला अन्तर्गत अमौर प्रखंड के रेफरल अस्पताल में कुल 20 चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत पद के विरूद्ध 12 चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत हैं तथा बैसा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 17 चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत पद के विरूद्ध 06 चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत हैं । चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं ।

2- वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात कुल 6 हजार 338 पद रिक्त हैं । उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है ।

3- आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय मंत्री महोदय...

अध्यक्ष : सामान्य प्रश्न था...

श्री अखतरूल ईमान : सर, नहीं सर सामान्य नहीं है...

अध्यक्ष : अच्छा बोलिए ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, मेरे ज्ञान में यह था कि 20 पोस्ट सैंक्शन है लेकिन मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 20 और 17 पोस्ट सैंक्शन है । 17 है बैसा में और 20 हैं यानी कि 37 पोस्ट सैंक्शन है, सर । 37 की जगह पर सिर्फ 10 डॉक्टर वहां काम कर रहे हैं, सर और पूर्णियां जिला का सबसे सुदूर, बाढ़ग्रस्त और 50-50 किलोमीटर की दूरी पर पुल नहीं होने की वजह से वहां जनता की हालत बड़ी खराब है, न जाने कितने बच्चे पेट में

मर रहे हैं, कितने बीमार दवा के बगैर मर रहे हैं, आपके वेलनेस सेंटर बंद पड़े हुए हैं मकान बना हुआ है, क्या अतिशीघ्र...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछेंगे या अपनी भूमिका बनायेंगे....

श्री अखतरूल ईमान : नहीं, भूमिका नहीं सर मैं यह कह रहा हूं कि....

अध्यक्ष : आप एक सेन्टेंस में पूरक पूछिए ।

श्री अखतरूल ईमान : मेरे जितने स्वीकृत पद हैं उन तमामतर स्वीकृत पद पर डॉक्टर कब तक बैठेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि दोनों प्रखंडों में 37 के विरूद्ध 18 चिकित्सक हैं, 7 नहीं हैं । 37 के विरूद्ध 18 चिकित्सक हैं जो अभी सेवा दे रहे हैं और चिकित्सकों की उपलब्धता मुझे तभी होगी जब तकनीकी सेवा आयोग से नाम अनुशंसित होकर आ जायेंगे । मैंने अभी सदन को बताया कि पिछले ही साल जुलाई से लेकर सितंबर के पूर्व 4 हजार चिकित्सकों की नियुक्ति हमने की थी और फिर जनवरी और फरवरी के महीने में अधियाचना चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए हमने भेजी है । अभी यह अधियाचना भेजे हुए लगभग डेढ़ महीने का समय बीता है, जैसे ही वह अनुशंसित नाम प्राप्त होगा हम चिकित्सकों की नियुक्ति कर देंगे ।

टर्न- 6/ मुकुल-राहुल/05.03.2021

अध्यक्षः श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय ।

श्री अखतरूल ईमानः अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरक पूछने का हक है । मैं चुनौती देता हूं...

अध्यक्षः माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप एक मिनट बैठ जाइये । श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1089 (श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, क्षेत्र संख्या-200, बक्सर)</u>

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2-उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्क्रीनिंग समिति के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर राजकीय धनवन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर के प्रत्येक कर्मियों से अलग-अलग स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है एवं बिहार निजी चिकित्सा अधिनियम-1985 की धारा-6 के

उपधारा-3 के तहत विभाग में उसकी समीक्षा की गयी और समीक्षोपरांत सेवामुक्ति आदेश निर्गत किया गया है ।

3-कंडिका-02 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया है लेकिन मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूं क्योंकि वर्ष 2003 में...

अध्यक्ष: आप मंत्री जी से अलग से मिल लीजिएगा संतुष्टि हो जायेगी । श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: संजय जी आप अपनी बात जल्दी बोलिए ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: अध्यक्ष महोदय, आसन के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि वर्ष 2003 से यह मामला लंबित है और इसकी कब जांच की गई? चूंकि मेरा प्रश्न अगले बार भी यही था और उसमें स्पष्टीकरण माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया था । अब कब जांच कर ली गई इसके बारे में माननीय मंत्री जी मुझे बता दें इसके बाद मैं मिल लूंगा ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सारे कागजात प्राप्त हैं ।

अध्यक्ष: मंत्री जी इनको बुलाकर संतुष्ट करवा दीजिए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सारे कागजात की प्रति सदन की मेज पर भी रख देता हूं और माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करवा देता हूं ।

अध्यक्ष: ठीक है, श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, हमें भी संतुष्ट करवा दीजिए ।

अध्यक्ष: ठीक है, अब आप बैठ जाइये । श्री शकील अहमद खां ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष: आपने कहा कि आप मंत्री जी से मिलकर संतुष्ट हो जायेंगे ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, आप बोलेंगे तब ही न मंत्री जी संतुष्ट करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1090 (श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)</u>

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सासामुसा का सरकारी भवन बना हुआ है, साथ ही स्टाफ क्वार्टर भी बना हुआ है । डॉ0 फरहत जबी यूनानी आयुर्वेदिक चिकित्सक पदस्थापित हैं । डॉ0 मनीष कुमार, सामान्य चिकित्सक (M.B.B.S.), श्रीमती रंभा मिश्रा, जी0एन0एम0 तथा श्री नरेन्द्र कुमार

प्रयोगशाला प्रवौधिकी संविदागत कार्यरत हैं, जिनके द्वारा चिकित्सीय कार्य का संपादन किया जा रहा है ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेयः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बताया गया है तो एक बार अपने स्तर से उसको जांच करवा लीजिए कि वह चल रहा है कि नहीं चल रहा है । इसलिए कि सासामुसा से गोपालगंज की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है और कुचायकोट की दूरी 6 किलोमीटर है । अभी वहां कोई डॉक्टर वगैरह बैठता नहीं है इसलिए एक बार मंत्री जी अपने स्तर से दिखवा लें ।

अध्यक्षः मंत्री जी आप इसे दिखवा लें ।

तारांकित प्रश्न सं0-1091 (श्री शकील अहमद खां, क्षेत्र संख्या-64 कदवां)

अध्यक्षः श्री शकील अहमद खां प्राधिकृत हैं डॉ0 रामानुज प्रसाद । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः वस्तुस्थिति यह कि कटिहार जिलान्तर्गत कुरसेला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमिक करने की योजना स्वीकृत है । आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय फेज-2 के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है ।

अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के अनुरूप निर्माण कराया जाएगा।

डॉ0 रामानुज प्रसादः माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि कार्य योजना में है अगले वित्तीय वर्ष में ...

अध्यक्षः आप डायरेक्ट पूरक पूछिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राशि की उपलब्धता तो नये वित्तीय वर्ष में इसको प्राथमिकता के आधार पर कब तक माननीय मंत्री जी करा देना चाहते हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में हम इसको करवा देंगे।

श्री बिजय सिंहः अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह हमारे विधान सभा क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ मामला है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिस भूमि पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण होना था वह एन0एच0-31 के किनारे था । माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 फरवरी को 23 फरवरी को लगातार तीन दिन, एक दिन पांच आदमी की मृत्यु हो गई, 23 तारीख को छः आदमी की मृत्यु हो गई और स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने के कारण घायलों के इलाज कराने के लिए कटिहार से 40 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा । माननीय मंत्री जी से हम चाहेंगे कि कब तक वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण हो जायेगा ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने बात दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष में हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न-1092 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: (1) स्वीकारात्मक है ।

श्री मदन यादव, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में मशालची के पद पर नियमित कर्मी थे । वे दिनांक 26.08.2007 से लापता हो गए थे ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

यह सत्य है कि लापता होने के बाद रामपुर थाना, गया में काण्ड संख्या-123/11 दिनांक-11.06.2011 को दर्ज हुआ था तथा थाना द्वारा अंतिम प्रतिवेदन संख्या-128/14 दिनांक-30.06.2014 धारा-365 भा0द0वि0 के अंतर्गत न्यायालय ए0सी0जे0एम0, गया के समक्ष दाखिल किया गया । जिसे ए0सी0जे0एम0, गया के न्यायालय द्वारा दिनांक-15.05.2015 को स्वीकार कर लिया गया है ।

(3) स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि स्व0 मदन यादव के पुत्र श्री राकेश रौशन के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रपत्र में आवेदन सभी अनुलग्नकों के साथ अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया के पत्रांक-4116 दिनांक-25.11.2017 के द्वारा अपर समाहर्ता (विशेष) सह सचिव जिला अनुकम्पा समिति गया को भेजी गयी थी । पुन: जिला स्थापना उप समाहर्ता, गया के पत्र संख्या-389 दिनांक-28.03.2018 के प्राप्त निदेश के आलोक में संबंधित आवश्यक अभिलेख अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया के पत्रांक-1553 दिनांक-26.04.2018 द्वारा भेज दी गई है । श्री राकेश रौशन के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रस्ताव को जिला अनुकम्पा समिति गया के दिनांक-03.12.2018 की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2822 दिनांक-27.04.1995 के आलोक में कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: महोदय, पूरक यह है कि सरकार ने हमारे तीनों सवालों को स्वीकार किया है, लेकिन जिला अनुकम्पा समिति की मीटिंग में कालबाधित कह कर उसको अनुकम्पा पर नौकरी देने का जो अध्याय है उसे बंद कर दिया गया है ।

अध्यक्ष: आप सीधा पूरक पूछिए ।

श्री कुमार कृष्ण उर्फ सुदय यादवः अध्यक्ष महोदय, सरकार के अंदर में ही जिला पदाधिकारी हैं तो हम जानना चाहते हैं कि उसको अनुकंपा के आधार पनर नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, माननीय सदस्य ने स्वयं माना है जिला अनुकम्पा समिति की रिपोर्ट भी मेरे पास है उसमें लिखा है कि जिला अनुकम्पा समिति के पत्रांक–2822 दिनांक–27.04.1995 के आलोक में श्री राकेश रौशन के अनुकम्पात्मक नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों को काल बाधित होने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादवः महोदय, यह कालबाधित क्या है ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः उम्र से अधिक हो जाना ।

अध्यक्षः बैठ जाइए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, जो अपेक्षित उम्र होनी चाहिए उससे अधिक उम्र हो जाने को कालबाधित बोला जाता है ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादवः महोदय, 10 साल के अंदर में वह कालबाधित हो गया, उसकी उम्र ज्यादा हो गई तो सरकार क्या उसके दूसरे आश्रित को नौकरी देने का विचार रखती है ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, यह प्रश्न नही है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य अलग से प्रश्न कीजिए ।

तारांकित प्रश्न–1093 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र संख्या–82 दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः (1) अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि कुल 488 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों में ही दन्त चिकित्सक का एक–एक पद सृजित है । शेष 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी एक–एक दन्त चिकित्सक पद का सृजन की कार्रवाई की जा रही है । वर्तमान में बिहार दन्त सेवा के अन्तर्गत दन्त चिकित्सक (मूल कोटि) के 573 पद सृजित हैं। इसमें से 558 दन्त चिकित्सकों की रिक्तियों के विरुद्ध बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से 552 दन्त चिकित्सकों की अनुशंसा प्राप्त हुई । उक्त अनुशंसित 552 अभ्यर्थियों में से विभाग द्वारा आयोजित काउंसलिंग में कुल 543 दन्त चिकित्सक उपस्थित हुए जिनका वर्ष 2019 में नियुक्ति–सह–पदस्थापन विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में किया जा चुका है । उक्त नियुक्ति–सह–पदस्थापन के पश्चात् राज्य में बिहार दन्त सेवा अन्तर्गत वर्तमान में कुल

526 दन्त चिकित्सक कार्यरत हैं तथा मात्र 47 पद रिक्त हैं । सभी रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई शीघ्र की जायेगी ।

(2) उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं इतना जानन चाहता हूं कि इनका 46 स्वास्थ्य केन्द्र में पद रिक्त हैं बहाली करने की प्रक्रिया ये कब तक पूरे कर लेंगे और 47 रिक्त पद पर बहाली की प्रक्रिया कब तक पूरी कर लेंगे ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, जवाब में लिखा है कि सभी रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई शीघ्र पूरी कर लेंगे । शीघ्र का मतलब ये होता है कि...

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, यही जानना था ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः सुन लिया जाय माननीय सदस्य हमने कहा है कि 46 जो केन्द्र हैं जहां पर पद सृजित नही हैं वहां पर पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है उसकी एक प्रक्रिया होती है पदेन समिति में जाना पड़ता है, उसकी अनुशंसा होती है, फिर कैबिनेट से स्वीकृति लेनी पड़ती है । मैं समझता हूं कि अगले दो महीने में इस काम को हम कर लेंगे ।

तारांकित प्रश्न–1094 (श्री राम प्रवेश राय, क्षेत्र संख्या–100 बरौली)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि उक्त गांवों में कुछ जगहों पर बांस–बल्ले के सहारे तार लगाकर विद्युत का उपभोग किया जा रहा है । राज्य योजना अन्तर्गत रिकंडक्टरिंग के तहत उक्त वर्णित गांवों के बांस–बल्ले वाले स्थानों पर पोल एवं तार लगाकर विद्युत आपूर्ति करने का लक्ष्य मार्च, 2021 तक है ।

श्री राम प्रवेश रायः माननीय मंत्री जी कह रहे है कि बांस–बल्ले हटाकर पोल लगाने का लक्ष्य मार्च, 2021 तक है उक्त दोनों प्रखंडों के कई गांवों में आज भी लोग बांस पर तार लगाकर बिजली जला रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये विभाग को आवश्यक आदेश देकर के दिखवा लें कि जहां–जहां पर भी बांस–बल्ले पर तार लगाकर बिजली जलाने का काम करते हैं वहां पर पोल लगवाने का काम करेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः माननीय सदस्य लिख कर सूची दे दें, उसको दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न–1095 (श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र संख्या–15 केसरिया)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्रीः महोदय, वन एवं पर्यावरण विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है ।

अध्यक्षः ठीक है ।

तारांकित प्रश्न–1096 (श्री राहुल तिवारी, क्षेत्र संख्या–198 शाहपुर)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्रीः (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) सर्पदंश को प्राकृतिक आपदा/स्थानीय प्रकृति की आपदा के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है । यद्यपि बाढ़ अवधि के दौरान बाढ़ जनित कारणों से सर्पदंश के कारण हुई मृत्यु को प्राकृतिक आपदा जनित कारण मानते हुए एस0आर0डी0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान देय है । बाढ़ अवधि के बाद सर्पदंश को प्राकृतिक आपदा जनित कारण नहीं माना गया है ।

(3) जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार स्व0 प्रियंका कुमारी की मृत्यु बाढ़ जनित कारणों से नहीं हुई है । अतः प्रश्नगत मामले में अनुग्रह अनुदान देय नहीं है ।

श्री राहुल तिवारी: महोदय, मेरा सवाल यह है कि उत्तर यह है कि बाढ़ मे जो सांप काटते हैं, आपदा विभाग के द्वारा उनको राशि नहीं मिलती है, लेकिन पिछले सदन में सरकार की ओर से माननीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदीजी का एक वक्तव्य आया था कि बाढ़ के अलावा अगर सर्पदंश से किसी की मृत्यु होती है तो उसको वन विभाग अनुग्रह देगा, क्या यह बात सही है ?

टर्न-7/यानपति-अंजली/05.03.2021

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष जी, उत्तर स्वीकारात्मक था । सर्पदंश प्राकृतिक आपदा स्थानीय प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है । यद्यपि बाढ़ अवधि के दौरान बाढ़जनित कारणों से अगर सर्पदंश के कारण मृत्यु हुई है तो मृत्यु को प्राकृतिक आपदा जनित कारण मानते हुये एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया मानव दर के सदी से अनुग्रह-अनुदान, अन्य अनुदान देय है । बाढ़ अवधि के बाद सर्पदंश को प्राकृतिक आपदा जनित कारण से नहीं माना गया है और जिला पदाधिकारी भोजपुर से प्राप्त प्रोविडेंट के अनुसार में स्वर्गीय प्रियंका कुमारी की मृत्यु बाढ़जनित कारण से नहीं हुआ है । अतः प्रश्नगत मामले में अनुग्रह राशि अनुदान देय नहीं है ।

अध्यक्ष: अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

श्री राहुल तिवारी: एक सेकेंड सर । नियमावली में लिखा हुआ है कि वन विभाग के द्वारा पैसा मिलेगा और वन विभाग की आज चिट्ठी...

अध्यक्ष: देखिए आज शुक्रवार है । 12:30 बजे तक ही कार्यवाही होगी । इसलिए बैठ जाइये ।

श्री राहुल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । लास्ट मेरा है । नियमावली में लिखा हुआ है कि वन विभाग देंगे और वन विभाग में जब गया था तो उन्होंने लिखा कि इस तरह का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है । इसको जांच करवा लिया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय । अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री महानंद सिंह ।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, कह रहे थे कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी, ये मंत्री हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के । एक कार्यक्रम था हाजीपुर में और उसमें सहनी जी नहीं गये और अपने भाई को भेज दिये...

(व्यवधान)

शून्यकाल

श्री महानंद सिंहः अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला के प्रसादी इंगलिस से 10 नंबर रजवाहा तक पटना मुख्य नहर के आर.पी. चैनल कई जगह टूट जाने से किसानों को सैकड़ों एकड़ जमीन पटवन में दिक्कत हो रही है । मैं सदन से आर.पी. चैनल के पक्कीकरण की मांग करता हूं ।

अध्यक्षः बैठ जाइये । आप सब नियम के हिसाब से लायेंगे, हम देखेंगे ।

श्री अरूण सिंहः अध्यक्ष महोदय, काराकाट विधान सभा अंतर्गत बिक्रमगंज डेहरी पथ में रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर सड़क जर्जर होने से अनियंत्रित होकर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही है । 27 फरवरी, 2021 को एक मौत भी हो गई । मैं मांग करता हूं कि क्रॉसिंग के दोनों तरफ तत्काल सड़क की मरम्मत करायी जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः बैठ जाइये, माननीय सदस्यगण । ठीक है आपलोग अपनी बात को रखे हैं अब बैठिये ।

श्री रामबली सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी, हुलासगंज और रतनी प्रखंड में एक भी बालिका उच्च विद्यालय नहीं है । अगर सरकार का नारा-'' बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' गलत नहीं है तो सरकार से मांग है कि इन प्रखंडों में कम से कम एक-एक बालिका उच्च विद्यालय खोला जाय ।

श्री कृष्णनंदन पासवानः अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया ऐतिहासिक गांधी घाट से 5000 जनसंख्या वाली मझार गांव की दूरी 7 किलोमीटर है, गांधी घाट घनौती नदी पर पुल निर्माण से 1 किलोमीटर प्रखंड, अंचल, थाना, अस्पताल की दूरी मझार गांव से रह जाएगी ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि गांधी घाट घनौती नदी पर पुल निर्माण करावें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः बैठ जाइये । सभी माननीय सदस्य बैठ जाइये । हम देख रहे हैं कागज को ।

श्री पवन कुमार जायसवालः अध्यक्ष महोदय, जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का खाद्यान्न वितरण में अहम भूमिका है । राज्य सरकार से मांग करता हूं कि डीलर को सरकारी कर्मी घोषित कर 20000 मानदेय तीन वर्षों पर ऑनलाइन अनुज्ञप्ति नवीकरण, मैनुअल स्टॉक/वितरण पंजी की प्रथा समाप्त करने, साप्ताहिक छुट्टी, पूर्व की तरह केवल निलंबन व्यवस्था लागू किया जाय ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के निमा ग्राम में स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण छह वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था जो आज तक अधूरा है ।

अतः निर्माण अविलंब पूरा कराया जाय ।

श्री सुधाकर सिंहः अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के चौसा रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का कर लिया है लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है । राज्य सरकार अपने हिस्से का कार्य जल्द पूरा करायें ।

श्री राकेश कुमार रौशनः अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला के खोदगंज थाना अध्यक्ष द्वारा पैमार नदी से अवैध बालू खनन में प्रति ट्रैक्टर 4 से 5 हजार रुपया लिया जा रहा है जिसका वीडियो भी वायरल है ।

अतः खोदगंज थाना प्रभारी द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार की जांच कर कार्रवाई करावें ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारीः अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला कबड्डी संघ सचिव रवि भूषण पांडेय जी के पुत्र आदित्य नारायण पांडेय जो कि एक राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, की हत्या सासाराम में 22 फरवरी, 2021 को जहर देकर कर दी गई जिसमें नामजद एफ0आई0आर0 शिवसागर थाना में थाना कांड सं0-48/2021 दर्ज की गई है लेकिन आज तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे पास अभी अखबार की प्रति भेज दी है और इसको हम देख रहे हैं । मुझे मालूम नहीं था लेकिन यह आश्चर्यजनक है । मैं तो पूरी बात करूंगा क्या मामला है, जरूर देखूंगा । यह काम किसी मंत्री का नहीं है, यह काम किसी, अरे भाई आप यूं ही क्यों अभी बोल रहे हैं हमको मालूम नहीं था, मालूम हुआ अभी बात करेंगे । यह आपने नोटिस लाया है यह बात अखबार में छपी है और यह बात अगर सही है तो आश्चर्यजनक है । ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिये, लेकिन फिर भी बात करेंगे ।

श्रीमती भागीरथी देवीः अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड गौनहा के ग्राम शेरवा मस्जिदवा एवं धुमली परसा के बीच गायचाहा नाला पर पुलिया बनवाने की मांग करती हूं ।

श्री मिथिलेश कुमारः सीतामढ़ी नगर में विगत कई महीनों से जाम की समस्या के कारण कई लोगों के कई कार्य बाधित हो चुके हैं । दिनांक-04.03.2021 को आजाद चौक से मेहसौल चक तक तीन घंटे का जाम रहा । सरकार अविलंब प्रशासन को जाम से निजात दिलाने का आदेश दे ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण के मेहसी में लीची उत्पादन से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन पिछले पांच वर्षों से लीची के मंजर में स्टिंगबग कीट लगने से किसानों को भारी क्षति हुई है ।

अतः सरकार से मांग करते हैं तत्काल कीटनाशक छिड़काव एवं लीची फसल का बीमा करावें ।

श्री मुरारी मोहन झाः अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला में केवटी प्रखंड के बरीऔल पंचायत में खिरोइ नदी के पूर्वी बांध का स्लुईस गेट बंद कर दिया गया है । जिसके कारण रावण मोरी नाला बंद हो गया है । परिणामस्वरूप किसानों का 250 एकड़ जमीन जलाशय बन चुका है । सैकड़ों किसानों के कल्याण हेतु सरकार उचित निदान करे ।

श्री विजय कुमार खेमकाः अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया उर्स लाइन स्कूल सहित राज्य के सभी निजी विद्यालय लॉकडाउन में बंद स्कूल का फी नहीं देने पर अभिभावकों को प्रताड़ित कर बच्चों का रिजल्ट रोक दिया । स्कूल बंद रहने पर भी कंप्यूटर बस का फी लिया गया ।

अतः मैं सरकार से सभी निजी विद्यालयों को लॉकडाउन समय का पूर्ण फीस माफ करने का निर्देश देने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप बैठ जाइये अपना बोल दिये अब दूसरे का समय मत खत्म कीजिये ।

श्री विनय बिहारीः अध्यक्ष महोदय, लौरिया में स्वीकृत नंदनगढ़ महोत्सव विगत चार वर्षों से नहीं हो रहा है । सरकार इसे शीघ्र करावें ।

अध्यक्षः आपको धन्यवाद है कि 15 शब्द में आपने रखा ।

श्री मनोज कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के प्रखंड कोटवा के आवासित आम जनता अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा से वंचित है । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्क्रमित करने की मांग मैं सदन से करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्रः भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के बिहपुर जमालपुर पंचायत के पश्चिमी केबिन के बायें छोटी धार में पुल नहीं रहने के कारण पांच पंचायतों के किसानों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ।

अतः सरकार से उक्त धार में पुल बनाने की मांग करता हूं ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/05-03-21

श्री पवन कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के अन्तर्गत आशा कार्यकर्त्ता एक फैसिलीटेटर को दिये जा रहे पारितोषिक रू0 1000 उसके द्वारा प्रसव में वृद्धि एवं शिशुओं के मृत्यु दर में हो रही कमी और कार्यकुशलता को देखते हुए रकम काफी कम है। अतः सरकार से पारितोषिक रकम में वृद्धि करने की मांग करता हूँ।

श्री विनय कुमारः अध्यक्ष महोदय, परैया प्रखंडान्तर्गत शहीद सुनील विद्यार्थी के गांव वोकनारी से पूनाकला होते हुए गया-कपस्या मुख्य मार्ग से जुड़ने वाली सड़क का निर्माण करवाया गया था परन्तु सड़क को 2 कि0मी0 पहले ही छोड़ दिया गया है जिससे सड़क बनाने का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। अतः इसे पूर्ण करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूँ।

श्री मुकेश कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1780/2006 दिनांक 06-12-2006 के द्वारा राज्य स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में अनुबंध पर नियुक्त विगत 14 वर्षों से कार्यरत कर्मी को डी0आर0डी0ए0 मैनुअल की कंडिका 4.2 के अनुसार लाईन डिपार्टमेंट में समायोजित करने की मांग करता हूँ।

श्री शाहनवाजः अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम महसेली निवासी मो0 इमरान पिता मो0 लईक को बौसी थाना द्वारा दिनांक 27-2-21 को हत्या के संदेह के तहत गिरफ्तार कर दिनांक 28-2-21 को सुबह में थाना हाजत में संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया। अतः मैं सदन से उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूँ।

डॉ0 शमीम अहमदः अध्यक्ष महोदय,पूर्वी चम्पारण जिला में कोरोना काल से ही भारत और नेपाल बोर्डर सील है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि भारत नेपाल बोर्डर को शीघ्र चालू करावे।

श्री प्रणव कुमारः अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिलान्तर्गत मोकबिरा चाय टोला में विगत दिनों अगलगी के कारण पीड़ितों को सरकार द्वारा अनुशंसित राशि 9800/-रू0 के बदले मात्र 6800/-रू0 का भुगतान किया गया है। अतः सरकार से पूर्व में भी पीड़ित परिवारों को 9800/-रू0 के भुगतान कराने की मांग करता हूँ।

मो0 नेहालउद्दीनः अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत रफीगंज प्रखंड के रफीगंज गुरारू पथ में नहर के बगल से झिकटिया, काजीचक होते हुए गोह आंति पथ तक रोड का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है,यह सड़क कई गावों को एक दूसरे से जोड़ेगी।

श्री आनंद शंकर सिंहः अध्यक्ष महोदय,औरंगाबाद प्रखंड अन्तर्गत सोहरैया के पास नहर से दिलमोहम्मदगंज पुलिया क्षतिग्रस्त है। उक्त पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से वाहनों के आवागमन में कठिनाई एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अतः सरकार उक्त पुलिया का निर्माण जनहित में जल्द करावे।

श्री भूदेव चौधरीः अध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत रजौन प्रखंड मुख्यालय खेल स्थल पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, रजौन का एन0ओ0सी0 लिये बिना ही थाना प्रभारी, रजौन द्वारा पकड़ी गयी गाड़ियों को लगाने से खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही है। अतः खेलप्रेमियों एवं आमजनों के लिए उक्त स्थल को वाहन मुक्त करने की मांग करता हूँ।

श्री ललन कुमारः अध्यक्ष महोदय,भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड अन्तर्गत इंटरस्तरीय उच्च विद्यालय, ईशीपुर के भवन पर पिछले दस वर्षों से एक व्यक्ति का अवैध कब्जा है। अतः सरकार से दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए विद्यालय भवन को कब्जा मुक्त कराने की मांग करता हूँ।

श्री आलोक कुमार मेहताः अध्यक्ष महोदय,आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया जा रहा है, कारणवश जनता परेशान है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि समयावधि में उक्त प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु जनहित में कड़े कदम उठाई जाए।

श्री अरूण शंकर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली से मधुबनी भाया रसीदपुर जाने वाली मुख्य सड़क स्थित पैन सागर के निकट रसिदपुर गांव में बना पुल जर्जर हो गया है जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अतः शीघ्र क्षतिग्रस्त पुल की जगह आर0सी0सी0 पुल निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमीः अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ सी0एच0सी0 अस्पताल बनाते बनाते संवेदक अधूरा छोड़ दिया गया है जिस कारण मरीज तथा मेडिकल स्टाफ को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मैं भवन निर्माण विभाग से मांग करता हूँ कि संबंधित संवेदक के खिलाफ संज्ञान लेते हुए अविलम्ब निर्माण पूर्ण करायी जाय।

श्री रणविजय साहूः अध्यक्ष महोदय,समस्तीपुर जिला के पटोरी अनुमंडल की स्थापना 27 वर्ष पूर्व हुई थी आज तक वहां निबंधन कार्यालय की स्थापना नहीं हुई है। अभी भू-निबंधन के लिए 35 कि0मी0 दूर समस्तीपुर या दलसिंहसराय जाना पड़ता है। मैं मांग करता हूँ कि पटोरी में निबंधन कार्यालय की स्थापना शीघ्र हो।

श्री प्रकाश वीरः अध्यक्ष महोदय,नवादा जिलान्तर्गत पत्थर,बालू,खनिज उत्खनन से पर्यावरण प्रभावित होता है। प्रभावितों के स्वास्थ्य लाभ एवं विकास आदि के लिए सरकार के पास पृथक कोष में अरबों रू0 जमा है। जनहित में उक्त राशि को प्रभावितों पर खर्च की जाय।

श्री गोपाल रविदासः अध्यक्ष महोदय,सरकार ने 5 हजार की आवादी पर स्वास्थ्य उप केन्द्र को उत्क्रमित कर अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र करने की संकल्प ली थी लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि ग्राम परसा,कुरथौल,कुरकुरी एवं गोनपुरा को अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाय।

श्री विद्या सागर केशरीः अध्यक्ष महोदय,अररिया जिलान्तर्गत नगर परिषद, फारबिसगंज के पटेल चौक पथ निर्माण विभाग सड़क से सदर रोड स्टेशन चौक होते हुए पोस्ट ऑफिस चौक से रजिष्ट्री ऑफिस होकर मार्केटिंग से सुभाष चौक तक सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहित करते हुए चौड़ीकरण मजबूतीकरण एवं नाला के निर्माण हेतु सदन से मांग करता हूँ।

श्री कुमार कृष्ण मोहनः अध्यक्ष महोदय,जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड रतनी फरीदपुर के ग्राम इब्राहीमपुर निवासी सोनामती देवी पति कमल यादव की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक 04-11-2021 को हो गया है। आश्रित को सरकार से मुआवजा की मांग करता हूँ।

श्रीमती बीना सिंहः अध्यक्ष महोदय,वैशाली जिला के महनार बाजार में महिलाओं के लिए कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं होने की वजह से आस-पास की गांव से महनार बाजार आई महिलाओं को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सरकार जनहित में महिलाओं की सुविधा के लिए महनार बाजार में एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करे।

श्री सुदामा प्रसादः अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के पीरो नगर पंचायत के लोहिया चौक पर ट्राफिक पुलिस की स्थायी व्यवस्था कर सरकार जाम से छुटकारा दिलावे।

अध्यक्षः आपको भी धन्यवाद मात्र 15 शब्दों में है।

श्री अमरजीत कुशवाहाः अध्यक्ष महोदय,सीवान जिलान्तर्गत मौरवा नगर पंचायत में बस स्टैंड नहीं रहने के कारण यात्री गाड़ी मुख्य सड़क पर खड़ी रहती है जिसके कारण आमलोगों को कठिनाई होती है,जनहित में उक्त नगर पंचायत में बस स्टैंड का निर्माण की मांग करता हूँ।

श्री अचमित ऋषिदेवः अध्यक्ष महोदय,अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड विशनपुर पंचायत मधुलता निवासी नागो ऋषि उर्फ लाली का 5-8-20 को नदी में डूबने से मृत्यु हो गयी जिसका यू0डी0 केस 10/20 रानीगंज थाना में दर्ज है। मृतक के आश्रित को सरकार से अनुग्रह अनुदान देने की मांग करता हूँ।

श्री मनोज मंजिलः अध्यक्ष महोदय, शिक्षा सेवकों(टोला सेवक,तालिमी मरकज)जो दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय से आते है इनसे शिक्षण कार्य सहित सभी काम जैसे चुनाव,जनगणना,नामांकन अभियान लिया जाता है और इनका मानदेय मात्र 8800 रू0 है और वह भी समय से नहीं मिलता है। मैं इनके शिक्षक के रूप में समायोजन एवं नियमित वेतनमान की मांग सदन के सामने रखता हूँ।

श्री संदीप सौरभः अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के पालीगंज और दुल्हिनबाजार प्रखंड में स्थित सभी नहरों की हालत जर्जर है,पानी अंतिम छोर तक नहीं जा पाता है,जिसके कारण किसानों को सिंचाई में भारी दिक्कत होती है। इन सभी नहरों की उड़ाही और पक्कीकरण की मांग सदन के सामने रखता हूँ।

टर्न–9/मधुप/05.03.2021

श्री राजवंशी महतो : अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों के मानदेय में समानुपातिक वृद्धि जनहित में करने की मांग करता हूँ ।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत उचकागांव अंचल में मीरगंज में रजिस्टर–2 में खाता संख्या 426 में किसी का नाम अंकित नहीं है ।

अतएव सर्वेक्षण कराकर उक्त खाता में नाम जोड़ने की माँग करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लॉकडाउन काल के सभी प्रकार के कर्जों को माफ और उनके लिए रोजगार सृजन की व्यवस्था करने की माँगा करता हूँ ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखण्ड अन्तर्गत भोपतपुर पंचायत में मुन्सी बिगहा और जीवन बिगहा के बीच पुनपुन नदी पर पुल नहीं रहने के कारण जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है । मैं सरकार से यहाँ पुल निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा मोहनियां जीरो माईल से जगदीशपुर के गीच हरिगाँव एन0एच0 30 पर पीरो से जगदीशपुर के बीच जितौरा एस0एच0 102 पर ओ0पी0 आम जनता की सुरक्षा हेतु खोलने की मांग सदन से करता हूँ ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालय के छात्र/छात्राएं जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं ।

अत: मैं सरकार से मॉंग करता हूँ कि मदरसा की तरह संस्कृत विद्यालय के लिए भी भवन निर्माण/मरम्मति आदि के लिए राशि का प्रावधान करें ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल समाप्त हुआ ।

अब ध्यानाकर्षण सूचना लिये जायेंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री जनक सिंह, रामप्रवेश राय एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [जल संसाधन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, सारण प्रमंडल के तीनों जिलों गोपालगंज, सिवान एवं सारण को प्रभावित करने वाला तटबंध है सारण तटबंध । इसके पर्याप्त मजबूत नहीं रहने और क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वर्ष 2017 एवं 2020 में गोपालगंज एवं सारण जिले में भीषण बाढ़ आयी जिससे सैकड़ों घर एवं दर्जनों सड़कें तहस-नहस हो गईं । भविष्य को ध्यान में रखते हुए सारण तटबंध का मजबूतीकरण आवश्यक है । इसके लिए बोल्डर पिचिंग एवं ब्लैक टॉपिंग कराये जाने की आवश्यकता है ।

अत: बोल्डर पिचिंग एवं ब्लैक टॉपिंग कर सारण तटबंध का मजबूतीकरण किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इसके आगे भी एक ध्यानाकर्षण सूचना है । माननीय सदस्य से पढ़वा दिया जाय ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : बस दो मिनट में मैं जवाब दे देता हूँ ।

महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गंडक नदी के दायें तट पर निर्मित सारण तटबंध गोपालगंज एवं सारण जिलान्तर्गत अवस्थित है जिसकी कुल लम्बाई 152 कि0मी0 है । सारण तटबंध के 80 किलोमीटर का प्रभाग सारण जिला में एवं 80 किलोमीटर से आगे 152 किलोमीटर का प्रभाग गोपालगंज जिला अन्तर्गत अवस्थित है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बाढ़ वर्ष 2017 में नेपाल प्रभाग के जलग्रहण में अत्यधिक वर्षापात के कारण जो क्षति हुई, 2018 में उसका कटाव निरोधक कार्य करके पुनर्स्थापन मरम्मती कर लिया गया । 2020 में 19 और 21 तारीख के बीच गंडक नदी के नेपाल स्थित जलग्रहण क्षेत्र में अप्रत्याशित वर्षापात के फलस्वरूप गंडक नदी में 4,36,500 क्यूसेक पानी प्रवाहित हुई । उक्त के अतिरिक्त उत्तर बिहार में भी काफी बारिश हुई जिससे 5 लाख 36 हजार क्यूसेक पानी प्रवाहित हुई । अन्य बहुत जगहों पर

एच0एफ0एल0 बढ़ा, उसका डिटेल मैं, मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, जो उनका प्रश्न है कि गोपालगंज एवं सारण जिला अन्तर्गत गंडक नदी के दायें तट पर निर्मित सारण तटबंध छरकिया जमींदारी बांध रिटायर्ड लाईन पर कुल रू0 211.21 करोड़ की लागत की राशि से 32 अदद एजेंडाओं के तहत पुनर्स्थापन, सुदृढ़ीकरण एवं कटाव निरोधक कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिसे दिनांक- 15.5.2021 तक पूर्ण किये जाने का कार्यक्रम है ।

उल्लेखनीय है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण तटबंध की कुल लम्बाई 72 कि0मी0 है । लम्बा प्रभाग होने के कारण उपरोक्त के अतिरिक्त बोल्डर पिचिंग एवं पक्कीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से कराये जाने का कार्यक्रम है । इस क्रम में सारण तटबंध के विभिन्न बिन्दुओं पर लगभग 38 कि0मी0 की लम्बाई में सुदृढ़ीकरण एवं बोल्डर पिचिंग के कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसकी प्राक्कलित राशि 178. 92 करोड़ है । साथ-ही, सारण तटबंध के किलोमीटर 80 से किलोमीटर 120 के बीच तटबंध का सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण के कार्य का भी प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसकी प्राक्कलित राशि 124.11 करोड़ है । उक्त दोनों कार्यों की प्राक्कलित राशि 40 करोड़ से अधिक रहने के कारण योजना प्रस्ताव पर जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त किये जाने निमित्त विस्तृत योजना प्रतिवेदन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना को समर्पित है । जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं जल संरक्षण विभाग से तकनीकी एप्रेजल प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त दोनों योजना के कार्यान्वयन का कार्यक्रम है ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष : एक मिनट ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 239 के तहत लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या- 704 एवं 706 की एक-एक प्रति को सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

सर्वश्री युसुफ सलाहउद्दीन, मोहम्मर इसराईल मंसूरी एवं अन्य बारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आगे भी एक ध्यानाकर्षण सूचना हमलोगों का है ।

अध्यक्ष : अगली तिथि को ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, अगली तिथि को कब ? तिथि तो बता दिया जाय । सोमवार को?

अध्यक्ष : Tuesday को ।

श्री ललित कुमार यादव : मंगलवार को ?

अध्यक्ष : हॉ ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री.....

अध्यक्ष : समय समाप्त है, पहले वाले ध्यानाकर्षण का पूरक शॉर्ट में पूछ लीजिए ।

श्री जनक सिंह : महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने...

अध्यक्ष : आधा मिनट में बोलिए । समय समाप्त है ।

श्री जनक सिंह : मंत्री जी ने कहा है, तुलना भी किया है कि 2017 और 2020 में गोपालगंज में जहां-जहां तटबंध टूटा था तो उसका 26 सेंटीमीटर अधिक आपको जल का प्रेशर पड़ा और फिर सारण जिला में 13 सेंटीमीटर, दोनों को तुलना करेंगे तो अधिक जल का । हमारा कहना है अध्यक्ष जी, कि उसकी ऊंचाई...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : वहॉ अनेक जगहों पर, जैसे तरैया विधान सभा क्षेत्र के दर्जनों ऐसे प्वायंट हैं....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री जनक सिंह : हम तो यही चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप समय दें और सभी जन प्रतिनिधियों से जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको लेकर....

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी इनको समय देकर अलग से मिल लीजिएगा ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : मैं बुला लूँगा ।

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : अलग से चले जाइयेगा आप भी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, छोटे लाल राय जी भी इससे जुड़े हुए हैं । इनको भी उसमें जोड़ दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप भी चले जाइयेगा ।

अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल)

टर्न–10/आजाद/05.03.2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, उद्योग विभाग की अनुदान की मांग पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल	–	56 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	–	55 मिनट
जनता दल युनाइटेड	–	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	–	14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	–	09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस–ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन	–	04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	–	03 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	–	03 मिनट
सी0पी0आई0एम0	–	01 मिनट
सी0पी0आई0	–	01 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	–	01 मिनट

माननीय मंत्री, उद्योग विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ....

'' उद्योग विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 12,85,17,16,000/–(बारह अरब पचासी करोड़ सत्रह लाख सोलह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा, श्री सत्यदेव राम, श्री अख्तरूल ईमान, श्री सुधाकर सिंह एवं श्री महबूब आलम से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं, जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श

कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विजय शंकर दूबेः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटायी जाय । ''

अध्यक्ष महोदय, आज सदन में .....

अध्यक्ष : 4 मिनट का समय आज आपको दिया गया है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, फिर कल ही वाला बात आप चाहते हैं.....

अध्यक्ष : हमको तो बता देना है समय क्या है ?

श्री विजय शंकर दूबे : आज तो मेरे दल का समय है न 14 मिनट महोदय ।

श्री विजय कुमार : महोदय, एक विशेष सूचना है ।

अध्यक्ष : एक मिनट ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 03.03.2021 को कोचिंग जाने के क्रम में एक छात्रा का एक्सिडेंट हो गया लहेरियाकट मोटरसाईकिल वाला उसको मार दिया था लेकिन अभी समाहरणालय पर उनके परिजन और लगभग एक हजार छात्रायें जाकर वहां विरोध कर रहे थे और उनको महोदय, दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया है, इसकी जॉच होनी चाहिए महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मंत्री शाहनवाज जी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, इनका हाईकमान इनको बिहार भेजा है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है । महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि उद्योग विभाग ऐसे हालात में है और ऐसा भद्दजीम बन चुका है बिहार का, जिसमें कोई आवाज नहीं । शाहनवाज जी, कोशिश भी करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उद्योगपतियों से बात करेंगे, देश के बड़े उद्योगपति को बिहार लाना चाहेंगे भी लेकिन इससे आगे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए मैं इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटाई जाय का प्रस्ताव उपस्थापित किया हूँ ।

महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि इस राज्य में पिछले 15 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी भाग्यशाली प्रमाणित हो चुके हैं कि श्रीबाबू से भी ज्यादा समय तक राज करने का इनको सुअवसर मिला है लेकिन महोदय, 15 साल में एक उद्योग-धंधा कोई भी उद्योग नहीं खड़ा हुआ । जो हमारे पुराने उद्योग-धंधे हैं गन्ना उद्योग, उस गन्ना उद्योग के किसानों का भी सम्पूर्ण भरपाई पेमेंट नहीं

हो सका है, रेगुलर पेमेंट नहीं हो सका है। महोदय, आप जानते हैं कि उत्तर बिहार के किसान कृषि पर आधारित उनका सारा कारोबार चलता है, लड़के की पढ़ाई हो, लड़की की शादी हो, बूढ़े माँ-बाप की दवाई हो, सारा काम कृषि पर निर्भर करता है महोदय, किसान गन्ना देकर के घर बैठ जाता है । नया सिस्टम, नई तकनीकी देश में आयी और नया किसान इसमें ऐसे भी महोदय .....

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त करते हुए ।

श्री विजय शंकर दूबे : जी । इसमें ऐसे भी किसान हैं जो एक बैलगाड़ी पर, एक टायरगाड़ी पर गन्ना ले जाकर दे दिया और पुर्जी लेकर के घूम रहा है । लोगों से पूछता चलता है कि भाई ई-पेमेंट इसको हम कहां लेकर जायं कि ई-पेमेंट हमारा हो जाय। सरकार और सरकार की व्यवस्था प्रशासन, जिला प्रशासन एक आदमी के लिए उत्तरदायी है हुजूर लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस व्यक्ति को कोई कहने वाला नहीं कि आप चलो, आपका पेमेंट कराते हैं। नहीं पेमेंट हो सकता है और हार पारकर के महोदय, एक टायर, दो टायर, एक बैलगाड़ी, दो बैलगाड़ी गन्ना बेचने वाले किसान ऐसे ही घूमा करता है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, हमारा समय 14 मिनट है न, कोई सदस्य कांग्रेस का अभी नहीं है । मैं हूँ, मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । चलिए ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ये हालात है राज्य के और शाहनवाज जी घोषणा किये कि हम नया उद्योग इथेनॉल उद्योग लगायेंगे, उसका स्वरूप अभी तय नहीं है। यह अन्दरखाने में है कि राज्य का उद्योगपति बेरोजगार नौजवान वह उद्योग चलायेगा या बाहर के अम्बानी और अडानी के वंशज बिहार आयेंगे उद्योग चलाने के लिए । यह भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, देश में सारी चीजें उद्योगपतियों को देने का जो षडयंत्र हैं उसका यह हिस्सा नहीं बने, यह माननीय मंत्री श्री शाहनवाज जी से मेरा अनुरोध है और इस बात का ध्यान रखें कि बिहार के नौजवानों के लिए उद्योग लगे और नौजवानों का इनवॉल्वमेंट हो और नया उद्योग-धंधा खड़ा हो । 15 साल में तो यह नहीं हुआ, अब तो नया हुआ है । अब महोदय, इस बात पर हमारे माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्रवण बाबू बड़ा पहले तो थाली बजाये और बाद में बेंच बजाने लगे । मुझे उसी पर एक कहानी याद आती है । महोदय, एक राजा थे और राजा को पुत्ररत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी, शादी के 10-15 साल होने के बाद और महोदय, एक दिन राजा के यहां रात में वाद्ययंत्र बजने लगे, नगाड़ा बजने लगा, शहनाई बजने लगी और सायरन

बजने लगा महोदय और हेड परिचारिकायें जो संदेश दी अन्दर से, उस पर महाराजनी को, पंडित को, महाराज को और बड़े-बड़े धर्माचार्य को बुलावा जाने लगा । पूरे राज्य में खुशी होने लगी कि महाराज को आज पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी । दो घंटे के बाद महोदय, हेड महाराजनी जो थी, उनका एनाऊंसमेंट हुआ कि ये महारानी को दर्द नहीं थी, महारानी के पैर में मखमली पांव पोछने में चोट लग गया था उसकी दर्द थी, इसलिए गलती से सायरन बजा दिया गया था । यह महोदय हालात है और उसमें भी श्रवण बाबू पूरा ताली पीट रहे थे, अभी तो उद्योग का पता नहीं, आयेगा, नहीं आयेगा, कागज में सिर्फ एनाऊंसमेंट हुआ और सरकार की ओर से इनको रखा गया है नया बंडी देकर के ऐसे ही ताली बजाने के लिए बिना वजह ताली बजाते रहते हैं । .....

क्रमशः .....

टर्न-11/शंभु/05.03.21

श्री विजय शंकर दूबे : क्रमशः महोदय, मैं आगे निवेदन करना चाहता हूँ ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : हुजूर, माननीय विजय शंकर दूबे जी बहुत पुराने सदस्य हैं, बहुत अनुभवी भी हैं । हमने कल ही कहा था कि इनके अनुभव का इस्तेमाल हमलोग जानते हैं कि क्या इनके पास अनुभव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनके अनुभव का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है । इनके दिल में जो दर्द है वे हमलोगों के बारे में कुछ बोलकर निकाल लेते हैं तो हमलोगों को भी प्रसन्नता होती है कि कम से कम इनके दिल का दर्द तो दूर हो रहा है।

अध्यक्ष : अब इनका दो मिनट समय बचा है बोलने दीजिए । दो मिनट समय बचा है बोलिये अब, 14 मिनट में 2 मिनट बचा है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, उद्योग विभाग के डिमांड के साथ पर्यटन और अन्य जो विभाग हैं, पर्यटन को बढ़ावा देकर के राज्य में आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं, राज्य का राजस्व बढ़ सकता है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में भी 15 साल में बिहार के जो दर्शनीय स्थल हैं उसको जितना डेवलप किया जाना चाहिए था वह डेवलप नहीं हो सका और नहीं किया गया । इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि राज्य के पर्यटन स्थल को सरकार विकसित करे ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री विजय शंकर दूबे : और उद्योग के क्षेत्र में शाहनवाज जी दिल्ली से आये हैं, बड़ा अनुभवी है, अच्छे लोग हैं और अच्छे नेता हैं इसलिए बिहार को अपेक्षा है कि उद्योग में नौजवानों को रोजगारोन्मुख करें । महोदय, बिहार में उद्योग के मामले में सारी संपत्ति उद्योग विभाग की

जितनी जमीन थी पटना में, हाजीपुर में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में सारी जमीन उद्योग विभाग का औनेपौने भाव में बिक गया । एक अच्छा काम हुआ कि सिटी का जमीन थोड़ा उद्योग का नीतीश जी ने गुरूद्वारा में दिया, वह अच्छ काम हुआ इसके अलावे सारी जमीन औनेपौने भाव में बेचे गये ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि राज्य में कृषि उद्योग विकसित हो, उद्योग मंत्री बढ़िया से काम करें ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री भरत भूषण मंडल, प्रारंभ करें ।

श्री भारत भूषण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आपके माध्यम से जो मुझको यह सुअवसर मिला है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर पर हूँ । राज्य का बजट सत्र चल रहा है और प्रायः ऐसा देखा जाता है आज जैसे पर्यटन मंत्री नहीं हैं, कल ऐसे महत्वपूर्ण विभाग रेवेन्यु का बजट चल रहा था और अधिकारी भी ठीक से उपस्थित नहीं थे ।

अध्यक्ष : ट्रेजरी बेंच इसको देख ले कि जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वे उपलब्ध रहें और संबंधित विभाग के पदाधिकारी भी रहें ।

श्री भारत भूषण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि मैं पहली बार सदन में बोलने खड़ा हुआ हूँ और मैं हृदय से इस बात के लिए आसन को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ आसन के प्रति ।

अध्यक्ष : 15 मिनट आपका समय है उसके अंदर ही समाप्त कर लीजियेगा ।

श्री भारत भूषण मंडल : जी-जी । आज चूंकि पहली बार खड़ा हुआ हूं तो मैं जिस क्षेत्र से जीतकर आया हूँ उस क्षेत्र की महान जनता को सामाजिक न्याय के अप्रतिम योद्धा, गरीबों के लाल श्री लालू प्रसाद यादव एवं श्री फनीश्वर नाथ रेणु जी जिनकी यह जन्म शताब्दी समय है । मैं उनको खास तौर पर अपना यह भाषण समर्पित करना चाहता हूँ । मित्रों, आप सभी को मालूम है कि मैं उद्योग विभाग पर विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । बिहार की स्थिति बिहार बेहद औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा हुआ प्रांत है । यह पूरी दुनिया जानती है और जो औद्योगिक रूप से बेहद पिछड़ा हुआ प्रांत है जहां कोई उद्योग धंधा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो बिहार का बहुसंख्यक अवाम है, विशेषकर के जो अति पिछड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और महिलाएं हैं वे पलायन करने को अभिशप्त हैं । मित्रों, मैं बताना चाहता

हूँ अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अगर यही सूरतेहाल बिहार का बना रहा तो क्या होगा आनेवाले समय में बिहार का इसका चिंतन मनन आप सही ढंग से जान सकते हैं । हम जिस मधुबनी के इलाके से आते हैं । पिछले दिनों जो वहां चीनी मिल था, जो सकरी में, लोहट में, रैयाम में, जो बंद पड़ा पंडौल में सूता मिल है- सारा उद्योग धंधा, नया उद्योग लगाने की तो बात छोड़िये, जो पुराने उद्योग धंधे थे वह भी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है । इस सरकार का क्या नजरिया है ये सरकार क्या चाहती है बिहार के निवासियों के साथ यह बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय विषय है । मुझको तो लगता है कि यह सरकार सुशासन के नाम पर केवल ढिंढोरा पीट रही है इसका सुशासन से कोई लेनादेना नहीं है । बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाया गया 2016 में उसका क्या हाल है ? 2016 से 2020 की अवधि में राज्य सरकार के पास 19438 करोड़ रूपये का निवेश आया, लेकिन वास्तविक निवेश हुआ 1868 करोड़ रूपये मात्र । इसलिए मित्रों, इस अवधि में हम यह बताना चाहते हैं कि एन0डी0ए0 की सरकार बिहार के लिए बोझ बन गयी है इससे बिहार का कुछ भला होनेवाला नहीं है । मित्रों, इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज इसी अवधि में जो दूसरे प्रांत हैं, जो विकसित प्रांत हैं हिन्दुस्तान के वे किस तेजी से प्रगति कर रहे हैं और हमारी क्या स्थिति है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं । जो कृषि की स्थिति है, जो उद्योग की स्थिति है सबमें जड़ता की स्थिति कायम हो गयी है, यथास्थिति कायम हो गयी है, कहीं से कोई गति नहीं आ रही है न तो सरकार में गति आ रही है और न बदलाव के लिए सरकार के मन में कोई इच्छाशक्ति है । इसीलिए मित्रों, हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि इस सूरत को बदलने के लिए एक विशेष प्रयास करने की जरूरत है, एक विशेष तवज्जो देने की जरूरत है तभी जाकर बिहार में उद्योग का जाल बिछ सकता है और उद्योगपति बिहार में निवेश करने आ सकते हैं । पूरे बिहार की छवि हिन्दुस्तान में और दुनिया में आज खराब हो गयी है, सुशासन केवल नाम का है । यहां पूरी तरह से महा जंगलराज स्थापित हो गया है और कोई बिहार आने को तैयार नहीं है । मित्रों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी आबादी है बिहार में जिनको आपने कोरोना काल में देखा ये जो बड़ी संख्या में बिहार से पलायन करने को अभिशप्त हों, जब देश के दूसरे प्रांतों में गये और जब कोविड बीमरी महामारी का रूप लिया उसके कारण उस समय जो अफरा-तफरी का माहौल इस देश में बना खासकर बिहार के मजदूरों का उसकी चर्चा करने से दिल घबड़ा जाता है । लाखों लोग बिहार के बाहर जो काम करने गये थे, गरीब और गुरूबत को झेल रहे लोग उसकी क्या दशा हुई बिहार के लोग

भलीभांति जानते हैं । हजारों लोग पानी, भूख और रास्ते में दुर्घटना का शिकार होकर के अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन ये जो संवेदनहीन सरकार है उसने उसकी कोई सुधि नहीं ली, उसकी कोई खोज खबर नहीं ली । इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि इस हालत को बदलने के लिए एक जो फनीश्वर नाथ रेणु जी ने कहा ।

(व्यवधान)

मित्रो, बैठ जाइये, आपकी बारी आयेगी तो बोलियेगा ।

अध्यक्ष : क्या हुआ आपको ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, माननीय सदस्य बार-बार मित्रो बोल रहे हैं जो यहां पर नहीं कहा जाना चाहिये ।

श्री भारत भूषण मंडल : तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बता रहा था कि यह जो बहुसंख्यक आबादी है उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्य है ? फनीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल में दूसरी लेखनी अपनी रचना के माध्यम से जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है उसपर बहुत गहरा प्रकाश डाला है और यह बताया है कि किस प्रकार जो बिहार का 90 फीसदी अवाम है घोर गरीबी और गुरूबत में जी रहा है । उनके पास शिक्षा पाने लायक, उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, उनके बच्चे कैसे पढे लिखेंगे, उनका शेष जीवन कैसे बीतेगा इसकी कोई रूपरेखा बिहार सरकार के उद्योग विभाग के बजट में दिखायी नहीं दे रहा है । इसलिए मित्रो, मैं कहना चाहता हूँ भाइयो, हम आपके माध्यम से अध्यक्ष जी कहना चाहते हैं कि यह जो गहरी विषमता पैदा हो गयी है, यह जो गहरा सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी पैदा हो गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सदन है, सभा स्थल नहीं है ध्यान रखेंगे ।

टर्न-12/ज्योति/05-03-2021

श्री भारत भूषण मंडल: जी, जी, महोदय, चूंकि मैं पहली बार बोल रहा हूँ ।

अध्यक्ष : आसन की ओर देख कर संबोधित करेंगे ।

श्री भारत भूषण मंडल : जी, आसन की ओर ही देखकर तो मैं कह रहा था कि यह जो भारी सामाजिक, आर्थिक गैर बराबरी सरकार की नीतियों से पैदा हुआ है । सरकार की जन विरोधी नीतियों से पैदा हुआ है उसका खामियाजा 90 फीसदी लोग भोग रहे हैं । उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन में कैसे बदलाव होगा, उसका सर्वांगीण विकास कैसे होगा, कैसे वह इस घोर महंगाई में अपना जीवन गुजारा करेगा । इसकी कोई चर्चा इस विभाग में नहीं है । मैं कहना चाहता हूँ कि स्थिति यह हो गयी है कि इस स्थिति को बदलने के

लिए बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों का जाल बिछाना होगा । बिहार की जो स्थिति है कृषि की तो उसकी भी वही हाल है जो कृषि का प्रति कट्ठा जो अधिकत्तम पैदावार हम ले सकते हैं उसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है । जबतक कृषि में जो व्याप्त संभावना है उसका पूरी तरह से हम हल नहीं निकालेंगे तो नये उद्योग लगाने के लिए जो पूंजी निर्माण का सवाल है, कैपिटल फौर्मेशन का सवाल है वहं कहॉ से मुमकिन हो पायेगा इसलिए आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, यह कहना चाहते हैं कि इस गैर बराबरी को मिटाने के लिए एक बड़े व्यापक सर्वे की जरुरत है। सरकार के इरादे बहुत कमजोर दिखते हें जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आयी है जो अति पिछड़े, वर्ग दलित वर्ग, एस. सी., एस.टी. वर्ग पर जो बजट का प्रोविजन किया गया है वह निहायत ही कम है । आबादी है 90 फीसदी इसलिए यह ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन के समान है । इसलिए हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, कि स्थिति को बदलने के लिए एक व्यापक प्रयास की जरुरत है । जहॉ तक ज्ञान और धन के बंटवारे का सवाल है, आप सभी जानते हैं कि ज्ञान और धन आज मुट्ठी भर हाथों में कैद हो गया है जो 90 फीसदी आवाम है उसके पास टोटल प्रोपर्टी का, पूरे पौपुलेशन का केवल एक परसेंट है और चंद जो मुट्ठी भर जो बड़े भूस्वामी हैं, बड़े जमींदार है, बड़े धनासेठ हैं, उनके पास दौलत का 98 फीसदी, 99 फीसदी कौंसन्ट्रेशन हो गया है इस स्थिति को बदलने के लिए एक विशेष प्रयास की जरुरत है । हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार अपनी रफ्तार को तेज करे जो रफ्तार है, सरकार के काम करने की जो गति है, वह बहुत धीमी है । जबकि दूसरे प्रांत बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उसके मुकाबले हमारी गति बहुत धीमी है । इस रफ्तार से हम चलते हैं तो बिहार से गरीबी को हटाना, बिहार से बेरोजगारी को हटाना, बिहार से मुफलिसी को हटाना नामुमकिन हो जायेगा इसलिए सरकार से मांग करते हैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि स्थिति को बदलने के लिए और व्यापक गरीब जनता के हक में नीतियॉ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों का जाल बिछाया जाय, गरीबों का सर्वेक्षण कराके बजटीय प्रोविजन जो अति पिछड़ो के लिए पिछड़ों के लिए ही नहीं बल्कि हम लोग मांग करते रहे हैं कि लोकतंत्र में यह आवाज उठती रही है ''जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी'' उस हिसाब से बजट का प्रोविजन किया जाना चाहिए जो अति पिछड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, उनके लिए बजट का प्रोविजन हो, उनकी तरक्की और विकास के लिए 90 फीसदी एलौटमेंट करना चाहिए । इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूॅ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जब ज्यादा बोल देते हैं तो आपको जानकारी हो, एक माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी का समय ही नहीं बचा क्योंकि जिनका एक मिनट है वह दो मिनट बोल दिए तीन मिनट बोल दिए ।

श्री ललित कुमार यादव : जिस पार्टी का जितना समय है उतना में तो बोलेंगे ही ।

अध्यक्ष : अब विपक्ष के कई सदस्य का एक एक मिनट है और आप ही उठकर कहते हैं दो मिनट और बोलने दीजिये, एक दो मिनट में क्या होगा ऐसी स्थिति में आसन को एडजस्ट करना पड़ता है ।

श्री ललित कुमार यादव : जिस पार्टी का जितना समय है उसी पार्टी के समय में से कटेगा जिसका बचेगा, आगे उसका वक्ता ज्यादा बोलेंगे ।

अध्यक्ष : श्रीमती शालिनी मिश्रा । 6 मिनट का समय है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी के उद्योग विभाग की मांग के समर्थन के लिए खड़ी हूं । महोदय, किसी भी राज्य की समृद्धि का दर्पण उस राज्य का उद्योग धंधा होता है । कोई राज्य कितना विकसित है, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी विकसित है, उस राज्य के उद्योग से समझ सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे बिहार में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक सम्पदा के रहते हुए भी उद्योग के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है । हम सभी इस बात से सहमत हैं कि किसी भी प्रदेश को तबतक विकसित नहीं किया जा सकता जबतक वहाँ उद्योग धंधे प्रचुर मात्रा में नहीं लगायें जायं । महोदय, उद्योग लगे, भारी निवेश हों उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरुरत होती है और कुछ माहौल की भी जरुरत होती है । विपक्ष के माननीय सदय महोदय कह रहे थे मैंने सुना कि चीनी मिल बंद हो गया, यह हो गया, वह हो गया, बहुत सारी प्रौब्लेम बता रहे थे, मैं मानती हूँ कि सब कुछ हो गया लेकिन मैं उसके साथ साथ यह भी कहना चाहती हूँ कि आप उस दौर को याद करें जब 1990 से 2005 के बीच में बिहार में

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नई माननीय सदस्या हैं, शांति से सुनें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : कुछ त्रुटि हुई है तो माफ करेंगे । मैं इनलोगों को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहती हूँ बिहार में 1990 से 2005 के बीच में डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी जो भी थे वे अपनी जान बचाकर बाहर भाग रहे थे । कोई अगर इसका जिम्मेदार है तो आज का विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार था । महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि उस समय जो

सबसे ज्यादा बड़ा धंधा चल रहा था अपने बिहार में जो फल फुल रहा था और पूरे भारत में पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, वह था अपहरण का महोदय, और उस अपहरण के लिए फिरौती कहॉ जा रही थी , क्या हो रहा था हम सभी जानते हैं, कहने की जरुरत नहीं है। इन लोगों को जो इतनी परेशानी हो रही है वह जो विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य हैं उनको इतनी परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अपहरण का इनका धंधा बंद हो गया और यहॉ पर बिहार में शांति कायम हो गयी इस वजह से इनको इतनी परेशानी हो रही है । महोदय, उस काल खण्ड में अगर हम बात करते हैं तो उस काल खण्ड में न इन्फ्रास्ट्रक्चर था, मैं खुद ही कॉरपोरेट वर्ल्ड से आयी हूँ इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ तो अगर किसी राज्य में अगर उद्योग को पनपना है तो उसके लिए कुछ आधारभूत संरचनाओं की जरुरत होती है । महोदय, आपलोग थोड़ा शांति बनाये रखें ।

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये, नये सदस्य हैं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : ये महिलाओं के लिए घर में क्या करते होंगे सदन में नहीं बोलने दे रहे है महिलाओं को तो।

अध्यक्ष : इशारों से बचिये सब लोग ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : उद्योगों के विकास के लिए सड़क चाहिए, बिजली चाहिए और कच्चे माल की व्यवस्था चाहिए और सबसे बड़ी बात होती है लॉ ऐण्ड और्डर वह चाहिए । महोदय, आपने जो किया था 1990 से 2005 में हमारे विपक्ष ने जो किया था उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उन्होंने हुकूमत संभाली है 2005 में उसके बाद से उन्होंने धीरे धीरे लॉ ऐण्ड ओर्डर कायम किया, सड़क और पुल पुलियों का जाल बिछाया, बिजली की व्यवस्था की । नल से जल की व्यवस्था की । उन्होंने इतनी व्यवस्था की कि आज के समय में मैं गर्व से कह सकती हूँ कि बिहार में कानून का राज कायम हो गया अब जो समय है महोदय, आने वाला जो समय है, महोदय, एक बात और मैं कहना भूल गयी ..

(व्यवधान)

बोलने दीजिये कोई बात नहीं है । माननीय सदस्यगण, सदन में कुछ कंसट्रक्टीव काम कर लेंगे तो हम सबों के लिए अच्छा होगा, हमारे लोगों के लिए अच्छा होगा । आग्रह होगा कि थोड़ा सा सकारात्मक सोच रखिये और हमारी बातों को सुने ओर आपकी भी बात भी हम बहुत शांति से सुनते हैं ।

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कर लीजिये, समाप्त करिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रही थी कि शांति कायम हो गया, अमन कायम हो गया, पुल पुलिया बिछ गया और आगे जो हमें करना है वह है उद्योग का विकास करना जो होकर रहेगा । क्रमशः

टर्न–13/अभिनीत–पुलकित/05.03.2021

(क्रमशः)

श्रीमती शालिनी मिश्राः जहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी जैसे सकारात्मक सोच वाले नेता हैं, जहां पर हमारे उद्योग मंत्रीजी जैसे डायनेमिक, एक्सपीरियंस और पोजिटीव अप्रोच वाले मंत्री हैं जहां पर हमारे सारे नेतागण, सत्तापक्ष, एन0डी0ए0 पक्ष इतने सकारात्मक हैं तो मैं जानती हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेताओं के लीडरशिप में, कि हमारे पी0एम0 के लीडरशिप में, हमारे सी0एम0 जी की लीडरशिप में यह होकर रहेगा ।

अध्यक्षः अब बैठ जाइये ।

श्रीमती शालिनी मिश्राः महोदय मेरे क्षेत्र की कुछ बातें हैं जिन्हें मैं कहकर समाप्त करती हूँ । सदन पटल पर अपनी बातें रखूंगी । पर्यटन भी एक ऐसा उद्योग है जिससे कोई राज्य फलता फूलता है तो मेरा आपसे आग्रह है कि ....

अध्यक्षः अब बैठ जाइये ।

श्रीमती शालिनी मिश्राः महोदय, एक मिनट, हमारे केसरिया क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है उसको डेवलप कराकर पर्यटक स्थल बनाया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ एक मिनट में मैं कहना चाहती हूं कि हमने जो देखा है, हमारे मुख्यमंत्रीजी में तीन चीजें हैं...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत जी ।

श्री कुमार सर्वजीतः अध्यक्ष महोदय, आज मैं विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, मंत्रीजी बहुत अनुभवी हैं और मैं कैसे कह सकता हूँ, हम लोग मगही में बोलते हैं– 'जो दुःख तोर, वही दुःख मोर' । बेचारे भारत के इतने बड़े लीडर और भाजपा के सबसे बड़े प्रवक्ता, बिहार में इनको लाया गया है ।

अध्यक्षः आप उद्योग पर बोलिये । विषय से हटकर क्यों बोल रहे हैं ।

श्री कुमार सर्वजीतः महोदय, मेरा कहना है कि यह जो विभाग बिहार में इनको दिया गया है, कुछ न कुछ तो सरकार ने अच्छा ही सोचा है ।

अध्यक्षः चलिये ।

श्री कुमार सर्वजीतः आखिर बिहार कैसे तरक्की करेगा । पन्द्रह साल में अगर नहीं कर सका तो शायद हमारे शाहनवाज भाई अगर जाते हैं तो शायद उसकी तरक्की हो, बिहार में इंडस्ट्री

लगे चूंकि इनकी पहचान भी देश दुनिया में काफी है । महोदय, मैं नीति, जिसकी भी चर्चा होती है उसकी नीतियां बनती हैं । कैसे इंडस्ट्रियां आती हैं, कैसे बिहार का विकास होता है, इस पर मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा इनकी नीयत पर हमारा सवाल होगा । इनकी नीयत क्या है ? क्या ये सच में बिहार की तरक्की चाहते हैं अगर चाहते हैं तो पीछे क्या हुआ, अभी क्या हुआ, इस पर बहुत ज्यादा विशेष चर्चा करने की आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं है । अगर नीति आपकी अच्छी है तो नीयत भी अच्छी होनी चाहिए । महोदय, सबसे बड़ी समस्या है यहां पर बिहार में कि हमारे यहां सिन्गल विंडो सिस्टम की समस्या है । शाहनवाज जी, अनुभवी व्यक्ति हैं और मैंने बचपन से इनको देखा भी है । बोधगया में इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, उससे बोधगया का विकास हुआ, इसमें कही से कोई दो मत नहीं है, चूंकि अनुभवी आदमी है, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जब तक बिहार में आप सिन्गल विंडो सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक बिहार इन्डस्ट्री के नाम पर तरक्की नहीं करेगा । महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि निवेश आयुक्त, 09.11.2018 में सरकार इनकी थी । निवेश आयुक्त ने एक बयान दिया महोदय, वो कहते हैं कि कैबिनेट से पास होने के बाद भी बियाडा को नहीं मिली जमीन, जमीन मिलने में देरी होने से प्रिया गोल्ड बिस्कुट का प्लांट उड़ीसा चला गया । इसके बाद ये कहते हैं कि बियाडा बंद होने के कगार पर, विवादों में फंसा है बियाडा की 25 सौ एकड़ जमीन । महोदय, अगर सिन्गल विंडो सिस्टम इनकी होती है तो जो व्यक्ति देश से आना चाहता है बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए तो एक ही टेबल पर उसको दे दीजिए कि कितनी फैसिलिटी आपको चाहिये बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए, हम सब चीज, आपको एक ही सिन्गल विंडो सिस्टम है हमारा यहीं से सबकुछ ले लीजिए तो निश्चित तौर पर इससे इंडस्ट्रीज यहां पर लगेंगी । शाहनवाज जी, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, पता नहीं क्यों उनको यहां भेजा गया, हमलोगों को भी खुशी हो रही है, चूंकि महोदय....

अध्यक्ष: घबरा नहीं रहे हैं न !

श्री कुमार सर्वजीत: नहीं, महोदय, घबरा नहीं रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है । मैं जिस समाज से आता हूँ 90 प्रतिशत हमारा समाज अभी भी अशिक्षित है । जो व्यक्ति अपने बच्चों को डी0पी0एस0 और डी0ए0वी0 में पढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि उनको रोजगार का अवसर मिलेगा, चूंकि परेशानी हमको नहीं है, देश में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार कोई झेल रहा है तो वैसे व्यक्ति के बच्चे झेल रहे हैं जिन्होंने अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया है । हमारे बच्चे तो गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से जीते हैं, बड़ी मुश्किल

से खाते हैं । खैर, आगे फिर इनके एक निवेश आयुक्त सह बियाडा के एम0डी0 आर0एस0 श्रीवास्तव बोलते हैं महोदय, बिहार के पिछड़ेपन को नौकरशाह जिम्मेवार । यह हम नहीं कह रहे हैं महोदय, हमारे विपक्ष के लोग नहीं कह रहे हैं, इनके सरकार में बैठे अधिकारी कह रहे हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के लिए नौकरशाह जिम्मेदार है । महोदय, इसमें ये कहते हैं कि जमीन नहीं देने से 250 करोड़ रुपये का निवेश बिहार से बाहर चला गया । मैं समझता हूँ कि शाहनवाज जी, इसको देखेंगे, अनुभव करेंगे कि आखिर जो लोग बिहार में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं आखिर क्यों वापस जा रहे हैं । अब तो जो हमें बदनाम करते हैं वह सरकार तो है नहीं यहां, अब तो आपकी सरकार है और इतनी अच्छी सरकार होने के बावजूद पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद हैं । इंजीनियर्स हमारे पढ़-लिख करके, चूंकि बिहार की 90 प्रतिशत आबादी जो स्टूडेंटों की है, यूथ की है वे बाहर जाकर के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर के आ रहे हैं और आपसे आस लगाये बैठे हुए है । आपने देखा भी होगा, आप चूंकि प्रवक्ता हैं, आपलोगों से सीखने का हमलोगों को अनुभव भी मिलता है, अगर आप इस परिस्थिति को 15 वर्षों में सुधारे होते तो शायद 30 लाख गरीबों के बेटे अपने कंधे पर बोझा लेकर के दिल्ली से बिहार नहीं आतें । अभी भी समय है, महोदय, स्टैंडअप इंडिया योजना में बैकफुट पर बिहार, उप मुख्यमंत्रीजी क्या कहते हैं शाहनवाज जी, देखिए, इसको सुनियेगा कि स्टैंडअप इंडिया योजना में बिहार पिछड़ता दिख रहा है । इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग और महिलाओं को पहली बार उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 01 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाता है । बिहार में कुल 32 बैंकों में से 18 बैंकों ने इनको एक भी रुपया नहीं दिया और इनके डिप्टी सी0एम0 का जो बजट भाषण था उसमें बड़ी खूबसूरती से बड़े अक्षरों में लिखा गया है महोदय, इनकी योजना का नाम । बड़े अक्षरों में इनकी योजना का नाम लिखा हुआ है और इस किताब में डिप्टी सी0एम0 कहते हैं कि हमने अनुसूचित जाति और जनजाति को इतनी फैसिलिटियां दीं और उसके बाद 18.12.2020 को यह बयान देते हैं कि बैंक इनको कर्ज ही नहीं दे रही है । खैर, महोदय, हम एक और आग्रह करना चाहते हैं....

अध्यक्ष: अब आप संक्षिप्त करें ।

श्री कुमार सर्वजीत: जी, हम सिर्फ, चूंकि आंकड़ों का खेल शाहनवाज हुसैन जी के सामने बड़ी मुश्किल होगी महोदय । ये प्रवक्ता हैं और आंकड़ों का खेल, इनको इतना अनुभव है, हम आंकड़ों के खेल पर नहीं जाना चाहते हैं हम उनको सिर्फ यह बता देना चाहते हैं

कि फतुहा में सोनालिका ट्रैक्टर की इंडस्ट्री आयी थी बंद क्यों हो गयी ?

(क्रमशः)

टर्न-14/हेमन्त-धिरेन्द्र/05.03.2021

...क्रमशः...

श्री कुमार सर्वजीत : मुझे लगता है आप अपने भाषण में जरूर बतायेंगे, औरंगाबाद में महोदय, याद होगा आपको, आप भी मंत्री थे, इसी सदन में कहा गया था कि औरंगाबाद में बहुत बड़ी साइकिल की इंडस्ट्री लगायी जा रही है । यह भी इनको बताना चाहिए कि औरंगाबाद में साइकिल की फैक्ट्री क्यों बंद हो गयी । महोदय, हाजीपुर में छः एकड़ में, पशुपालन मंत्री है न, हां, ठीक है, मुर्गीदाना की फैक्ट्री लगी थी । हमने तो खाया नहीं, फैक्ट्री बंद हो गयी ।

अध्यक्ष : अब कन्क्लूड करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं एक चीज आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मनमोहन सिंह की सरकार थी और स्वर्गीय रामविलास पासवान स्टील मंत्री थे । महोदय, रामविलास पासवान जी को उस गठबंधन में लाने का सबसे बड़ा अनुभव शाहनवाज हुसैन जी को प्राप्त था । मैं गवाह था, नहीं हैं बेचारे, उनके द्वारा स्टील प्रोसेसिंग प्लांट भारत सरकार से गया में 200 करोड़...

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये ।

श्री कुमार सर्वजीत : मोतिहारी में, बेतिया में, हाजीपुर में, उसकी जमीन भी खरीदी गयी । इसके बावजूद भी वह आज तक नहीं लगी ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये ।

श्री कुमार सर्वजीत : अंत में मैं एक आग्रह करूंगा कि जिस व्यक्ति को शाहनवाज भाई ने, माननीय मंत्री जी ने, सामाजिक न्याय का रास्ता भटकाकर अपनी ओर ले गये, अगर उनके द्वारा लायी गयी इंडस्ट्री बिहार में नहीं लग सकी, तो दलित की, इस देश के सबसे बड़ा नेता क्या इस सदन के बाहर उनकी एक मूर्ति स्थापित करने का विचार आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं ? ये हम आग्रह करेंगे ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, क्योंकि अगर मुझे.....

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, आज उद्योग विभाग के बजट पर जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष ने दिया है, उसके विरोध में बोलने के लिए मैं सरकार की तरफ से खड़ा हुआ हूं

और अध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करते हुए, पार्टी के नेता, पार्टी के उपमुख्यमंत्री और पूर्णिया की जनता, जिसने मुझे यहां दोबारा भेजा है, मैं सदन में उनका आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बातों को शुरू करने से पहले हमारे आदरणीय उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज जी का मैं सदन में जोरदार स्वागत करता हूं । आपको देश के लिए काम करने का बड़ा लंबा अनुभव है, अभी सर्वजीत जी भी बोल रहे थे । अनेक विभाग

फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स उद्योग, नागरिक उड्डयन सहित छः मंत्रालयों को आपने बखूबी संभाला है और आप पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चहेते भी रहे हैं और उनके नेतृत्व में देश को बहुत कुछ मिला है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बिहार की सेवा के लिए आपको भेजा है और आप विकास पुरुष एवं सुशासन का नेतृत्व करने वाले माननीय नीतीश कुमार जी के भी रत्नों में से एक रत्न हैं । इसलिए पूरी उम्मीद है बिहार की जनता को कि इस विभाग को आपके नेतृत्व में चमकने का अवसर मिलेगा और इस गौरवशाली बिहार के अतीत पूर्णीय स्थापित होगा । अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व के नेता बता रहे थे कि 15 साल में क्या हुआ है, जो बिहार था, अपना सम्पूर्ण बिहार, जो था झारखण्ड में चला गया, हमारे पास बहुत कुछ था । खनिज और बड़े-बड़े उद्योग भी यहां पर थे लेकिन जो था, वह झारखंड में चला गया और जो बचा, उसे आपके 15 साल जंगलराज ने निगलने का काम किया । इसलिए बिहार की यह स्थिति बनी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि उद्योग की ऐसी स्थिति है और आज बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और हमारे उपमुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एन0डी0ए0 की सरकार में उद्योगों का विस्तार हो रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, उद्योग आगे अग्रसर है, लेकिन हमारे विपक्ष के भाई को, श्री ललित भाई को सुनना अच्छा नहीं लगता है । इसलिए, सुनना अच्छा नहीं लगता है, उद्योग की महत्ता को सुनिये....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष महोदय, मुझे बारह मिनट ही मिले हैं । इसे लेकर हम अपने विपक्ष के भाई को कहना चाहते हैं कि....

अध्यक्ष : आप भटकिये मत, इधर देखिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, जरा उद्योग के विषय में सुनिये....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठे-बैठे मत बोलिये । यह गलत बात है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, शाहनवाज जी के नेतृत्व में उद्योग का कैसे विस्तार होगा..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अभी समय नहीं हुआ है । अभी बैठिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों को रोजगार देता है उद्योग । ललित भाई जरा सुनिये, बेरोजगारों को रोजगार देता है, उद्योग ।

अध्यक्ष : बैठे-बैठे मत बोलिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण है, उद्योग । सुदामा भाई, मजदूरों....

अध्यक्ष : आप इधर-उधर क्यों देखते हैं ?

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों, श्रमिकों की सहायता करता है, उद्योग । गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करता है, उद्योग । सबके जीवन को सुविधायुक्त बनाता है, उद्योग । सस्ता, अच्छा और टिकाऊ उत्पादन देता है उद्योग और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वदेशी के लिये लोकल-वोकल-ग्लोबल बनाता है उद्योग । आधुनिकीकरण की सीढ़ी चढ़ रहा बिहार में उद्योग । छोटी पूंजी से भी चलता है बिहार में अब हमारा उद्योग । अध्यक्ष महोदय, उद्योग पथ पर अग्रसर है हमारा बिहार और औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु प्रमाणीकृत 140 स्टार्ट-अप के विरूद्ध 88 स्टार्ट-अप को सीट सैंड के रूप में 701.15 लाख विमुक्त किया गया है । अध्यक्ष महोदय, जो 15 साल था, जब भी बात आती है, धड़कन विपक्ष की तेज हो जाती है, इसलिए हो जाती है कि आज उद्योग बढ़ा है लेकिन उन 15 सालों में उद्योग जो था, वह अपहरण का उद्योग हो रहा था ....

(व्यवधान)

और जो व्यवसाय थे, जो उद्यमी थे, अध्यक्ष महोदय, वे पुरानी मोटर साईकिल भी खरीदना नहीं चाहते थे, ऐसी असुरक्षा की स्थिति उन 15 सालों में बनी हुई थी । पलायन कैसे हुआ ? पलायन कब हुआ ? इससे कौन परिचित नहीं है । क्या उस समय उद्योग नहीं थे ? हमारे उद्योग मंत्री सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं वह सहरसा, पूरा पूर्णियां प्रमंडल का क्षेत्र है, वहां पर अनेक राईस मिल थे, प्लाइवुड के मिल थे, वे सारे मिल बंद हो गये । उद्यमी बिहार छोड़कर बहार चले गये । इसका एक मात्र कारण था असुरक्षा, आपकी सोच, आपकी नीति और नीयत में अंतर था लेकिन एन0डी0ए0 की सरकार में नीति और नीयत हमारी एक है इसलिए, हम आज उद्योग के क्षेत्र में....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मौका मिलेगा बोलने का, बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग, दलित योजना के अंतर्गत 5394 आवेदनों का चयन हुआ । अध्यक्ष महोदय, 5394 आवेदनों में 4425 को प्रशिक्षण के उपरांत प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गई ताकि 3058 लाभुकों को द्वितीय किस्त भी, 1150 लाभुकों को तृतीय किस्त भी उपलब्ध कराई गयी ताकि हमारा उद्योग बढ़ सके । (क्रमशः)

टर्न-15/सुरज-संगीता/05.03.2021

...क्रमशः...

श्री विजय कुमार खेमका : इस तरह बढ़ रहा है हमारा उद्योग लेकिन विपक्ष कहते हैं रोजगार कहां से आयेगा । चुनाव से पूर्व घोषणा किये 10 लाख रोजगार देंगे, हमने कहा हमारी नीति और नियति साफ है हमने कहा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और उसके लिए उद्योग का आज हम जाल बिछाये हुए हैं । आज छोटे से छोटे, बड़े से बड़े उद्योग हमारे यहां संचालित हैं चाहे चावल का मिल हो, चाहे प्लाईवुड हो, अब लोग निवेश कर रहे हैं निवेशक आ रहे हैं । कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ये भी हमारे यहां चल रहे हैं और मेज प्रोसेसिंग और हमारे यहां तो रेशम उद्योग हुआ हमारे शाहनवाज जी भागलपुर क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किये हैं । देश के प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में जो रेशम उद्योग, जिसको जीविका ने चलाने का काम किया उसकी चर्चा पूरे देश में, विश्व में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने करने का काम किया है । आज जूट मिल है जूट का सबसे बड़ा क्षेत्र था, कब बंद हुआ उसी 15 साल के जंगलराज में जूट मिल भी बंद हो गये नहीं तो हमारे क्षेत्र में जूट का काम होता था । आज हमारे नौजवान छोटे-छोटे रोजगार कर रहे हैं डिस्पोजल ग्लास बना रहे हैं, कृषि पर आधारित यंत्र बना रहे हैं जो आपके बच्चे नूडल्स खाते हैं उसे बना रहे हैं और जो छोटे-छोटे जो उद्योग हैं, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट हमारे यहां लग रहा है । हमारे एक मित्र कह रहे थे कि जो किसान नीति आई है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कानून लाया है ये शैलो गोदाम अंबानी का बन रहा है । मैं आपको बताना चाहता हूं 30 हजार मीट्रिक टन का शैलो गोदाम हमारे पूर्णिया में आज से 3 साल पहले बनकर तैयार हो गया था तो उनको क्या सपना आया क्या ? वो क्या अडानी का है क्या लेकिन हमारे विपक्ष जो हैं वह अपहरण..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये

श्री विजय कुमार खेमका : और सुरक्षा पर आप विश्वास रखते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार खेमका : आपके समय में उद्योग का पलायन हुआ ।

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त करिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के सम्पूर्ण जिलों में हम खादी का मॉल खोलने का काम करेंगे ताकि...

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कर लीजिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : ताकि खादी ग्रामोद्योग का विस्तार हो और इसलिए अध्यक्ष महोदय, समय है अध्यक्ष महोदय, अभी 12 मिनट समय है अध्यक्ष महोदय । अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : संक्षिप्त करने के लिए कह रहे हैं । संक्षिप्त करिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, रानीपत्रा में मैं उद्योग मंत्री जी का ध्यान भी आकृष्ट कराना चाहता हूं । पूर्णिया में भी हमारा जो खादी मॉल खुलने वाला है उसकी जमीन चिन्हित हो गयी है मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसकी स्वीकृति आपके द्वारा हो जाये ताकि वहां खादी मॉल का काम शुरू हो जाये और रानीपत्रा हमारा गांधी की धरती, महबूब साहब...

अध्यक्ष : आप इधर-उधर मत देखिये, समय समाप्त हो रहा है ।

श्री विजय कुमार खेमका : और रानीपत्रा जो गांधी की आगमन की धरती है...

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : जहां सर्वोदय आश्रम है, वहां पर सिटी रेशम कोकून, रेनिन का जो है निर्माण हो उसका भी प्रस्ताव आया हुआ है और पर्यटन पर भी आज बोलना है और पर्यटन के क्षेत्र में...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये आप बोल चुके हैं ।

श्री विजय कुमार खेमका : पर्यटन के क्षेत्र में भी अनेक काम हुए हैं आज बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में लोग जानने लगे हैं इसलिए मैं पर्यटन मंत्री से भी आग्रह करना चाहूंगा कि रानीपत्रा को बापू सर्किट से जोड़कर पूर्णिया को पर्यटन स्थल आप बनाने का काम करें ताकि देश की जनता पूर्णिया के नजदीक पहुंच सकें...

अध्यक्ष : श्री अनिल कुमार साहनी ।

श्री विजय कुमार खेमका : पूर्णिया को देख सके । इसी के साथ मैं पटल पर अपने विचारों को अपने जो हमारे वक्तव्य हैं उसको रखने का काम करता हूं ।

अध्यक्ष : आपको जानकारी हो सिर्फ मंत्री का जायेगा सभा पटल पर ।

श्री विजय कुमार खेमका : जी महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है । समय का सदुपयोग नहीं कर पाए, बैठिये ।

श्री अनिल कुमार साहनी : अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष द्वारा लाये गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और बिहार के गरीबों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों और विकास से जुड़ा यह विभाग उद्योग विभाग जिस पर बोलने से पहले मैं दो शब्द कह देना चाहता हूं- बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है उद्योग, आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है उद्योग, बिहार के बेरोजगार नौजवान किसान को पलायन करती है बिहार के उद्योग, बिहार के नौजवान गरीब किसान को, मजदूर को पलायन कराती है बिहार के उद्योग । आदरणीय, सभापति महोदय...

(व्यवधान)

आदरणीय, अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप बिहार विधान सभा में हैं ।

श्री अनिल कुमार साहनी : आदरणीय, अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग इनको डिस्टर्ब मत करिए, गड़बड़ा जाते हैं । आप सामने देखिए ।

श्री अनिल कुमार साहनी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शाहनवाज हुसैन जी हमारे बहुत ही निकट के सहयोगी भी रहे हैं और जिस प्रकार से इनको केन्द्रीय नेतृत्व ने बिहार में विकास करने के लिए और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो पलायन कर रहे हैं और जो पलायन करके यहां से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं उन मजदूरों को, गरीब नौजवानों को बुलाने का आप कोशिश करेंगे । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं आगे इस पर कह रहा हूं । सर आप देखिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग इन लोगों के लिए आपके उद्योग विभाग द्वारा 5 लाख रुपया अनुदान और 5 लाख रुपया जीरो परसेंट पर कर्ज दिया बैंक से देने के लिए, आपके यहां 40 हजार आवेदन लंबित है, महोदय । आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हमें उम्मीद है कि आप आशा और विश्वास के साथ आए हैं इन 40 हजार जो अति पिछड़ा, पिछड़ा और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं उनको आप यह अनुदान और बैंक से जीरो परसेंट पर लोन दिलाने का आप कार्य करेंगे क्योंकि आज खासकर के इसी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं, काम करते हैं और वहां करते हैं

काम और सहते हैं अपमान । बार-बार उन्हें अपमानित किया जाता है, मारा और पीटा जाता है इसकी ओर भी आपको ध्यान देना होगा । साथियों.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप इधर देखिए, इधर-उधर क्यों देखते हैं । आप इधर देखते रहिए, उधर मत देखिए इधर सामने देखते रहिए ।

श्री अनिल कुमार साहनी : महोदय, हमारे शाहनवाज साहब आपको कृषि पर आधारित कुछ उद्योग को लगाना चाहिए । जिस प्रकार से हमारा यहां पर मक्का के आधारित कॉर्नफ्लेक्स के लिए आप यहां पर उद्योग लगा सकते हैं । आप केला पर आधारित उद्योग लगा सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं । आप आलू पर आधारित उद्योग लगा सकते हैं और चिप्स बना सकते हैं । आप हमारे मुजफ्फरपुर के लिची को जूस बनाकर जूस फैक्ट्री लगाकर, आम फैक्ट्री लगाकर आप इसका उद्योग लगा सकते हैं, इसमें हमारे लाखों लाख हमारे नौजवान को आप काम दे सकते हैं, उसे रोजगार दे सकते हैं । मगर यहां काम पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ । साथियों, एक काम हुआ है हमारे बहुत से साथी लोग बोल रहे थे यहां कोई उद्योग नहीं खुला, कोई उद्योग नहीं खुला । अध्यक्ष महोदय, एक उद्योग खुला है, जहरीली शराब का । जहरीली शराब का उद्योग खुला है इस बिहार में । हमारे कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 3 व्यक्यिों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गयी, हमारा कटरा, औराई में 4 व्यक्तियों का जहरीली शराब पीने से मौत हो गया और बिहार में मौत हो रहा है । महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक उद्योग बहुत जोर से खुला है उसका नाम है, जहरीली शराब की दुकान...

अध्यक्ष : इसको बढ़ाना है कि रोकना है ।

श्री अनिल कुमार साहनी : जहरीली शराब की दुकान खुलवाकर गरीब के बच्चे को मरवाने का जो काम कर रहे हैं, ये लोग भी देख रहे हैं । महोदय, मैं गन्ना उद्योग के बारे में आपको बताना चाहता हूं ।

...क्रमशः...

टर्न-16/ मुकुल-राहुल/05.03.2021

क्रमशः

श्री अनिल कुमार साहनी: जितने भी गन्ना उद्योग थे, आपने उनको बियाडा में दे दिया, बंद गन्ना उद्योग को और वे दस सालों से वैसे ही पड़े हुए हैं । चीनी मिल को आपने बियाडा में दे दिया, उसकी जमीन वगैरह सब चीज और वहां पर क्या हो रहा है । वहां पर न खेती

हो रही है और न कोई काम हो रहा है । बियाडा उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, उसमें हमारे कुढ़नी विधान सभा क्षेत्र के बगल के गोरोल चीनी मिल । हमारे मुजफ्फरपुर, हमारे कुढ़नी विधान सभा क्षेत्र के बगल के मोतिपुर चीनी मिल, हमारे समस्तीपुर की चीनी मिल, हमारे मोतिहारी की चीनी मिल, ये सारी की सारी चीनी मिल जो हैं आज बंद पड़ी हुई हैं, इसकी ओर आपका क्या ध्यान है ? आप जिस प्रकार से इस उद्योग को चालू न करें, बियाडा से वापस लीजिए और उसको गन्ना विभाग में भेजिए और गन्ना विभाग से उन्हें शुरू करवाइये ताकि किसानों का जो नगद आमदनी करने का जरिया था, ईख से जो उसकी आमदनी का जरिया था, गन्ना से जो उसकी आमदनी का जरिया था, आज वह बंद हो चुका है हमारे क्षेत्र में और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी चुनाव में जाते थे तो बोलते थे कि इस चीनी मिल को जब हम अगली बार जीतकर आयेंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनकर आयेंगे तो इसमें धुंआ लगेगा और धुंआ चलेगा और इसी चीनी मिल की हम चीनी पीयेंगे तो यह जो है सो ''वादा तेरा वादा, वादे पे हमको मारा गया ।''

अध्यक्ष: आप उधर मत देखिये ।

श्री अनिल कुमार साहनी: अध्यक्ष महोदय, बिहार की जनता उद्योग के मामले में आज त्राहिमाम कर रही है, मैं बता देना चाहता हूं । अभी हमारे एक माननीय सदस्या बोल रही थी कि 15 साल में उद्योग नहीं लगा और पिछले 15 सालों के बारे में बता रही थी । मगर आप बताइये कि वर्ष 2000 में पेप्सी फैक्ट्री हाजीपुर खुली और आज बंद पड़ी हुई है वर्ष 1917 से, आज हाजीपुर इन्डस्ट्री एरिया में व्यवसायी गुंजन खेमका का मर्डर किसके राज्य में हुआ, कौन उसको पकड़ा और उसके हत्यारों को पकड़ने के लिए, आज इसके कारण हाजीपुर के सारे उद्योग बंद हो गये हैं । हमारे बगल के कुढ़नी के क्षेत्र का जो बेला उद्योग आज बंद पड़ा हुआ है यानी पूरे बिहार का उद्योग आपका बंद पड़े हुए हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शाहनवाज हुसैन से मैं इस सदन में आश्वासन चाहूंगा कि जो बंद पड़े जो हमारे मुजफ्फरपुर का बेला है या हाजीपुर का जो है आज इसमें निजी घर बनाकर लोग रह रहे हैं और व्यवसाय कर रहे हैं दूसरा काम कर रहे हैं उसे आप शुरू कराने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं । वहीं मैं आपको अब अति पिछड़ा और पिछड़ा आयोग जो है, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, यह हमारे अति पिछड़ा समाज से ही आती हैं ।

अध्यक्ष: अब आप संक्षिप्त कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास दो मिनट का समय बचा है ।

श्री अनिल कुमार साहनी: अध्यक्ष महोदय, हमारा समय तो बचा हुआ था मंडल जी कम ही बोले थे। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी अति पिछड़ा समाज से आती हैं । आज मैं अति पिछड़ा समाज के बारे में आपको बता देना चाहता हूं जो

''भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह मानव पत्थर है जिसे अत्यंत पिछड़ा के लिए प्यार नहीं ।''

सुनिये, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, सुनिये बात को सुनिये । आज बिहार सरकार के लालू यादव जी और हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जिसे चिन्हित किया था और जिसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का काम अति पिछड़ा समाज को किया और आपकी पार्टी द्वारा और आपके सत्ता के द्वारा सिर्फ ठगने का काम किया गया ।

अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइये ।

श्री अनिल कुमार साहनी: अध्यक्ष महोदय, सुनिये । एक मिनट और बोलेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है बोलिये ।

श्री अनिल कुमार साहनी: हमारे अति पिछड़ा समाज के नोनिया, मल्लाह और अन्य 17 जाति को जो अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए भेजा गया, महोदया, आज उसको केन्द्र सरकार ने वापस कर दिया है, मैं चाहूंगा कि इसकी ओर आप पहल करें क्योंकि आप बिहार के डिप्टी सी0एम0 हैं । हम चाहेंगे कि इन वर्गों को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति में...

अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइये ।

श्री अनिल कुमार साहनी: अध्यक्ष महोदय, हमारे मेम्बर के बोलने का जो समय है उसमें से आप समय ले लीजियेगा । हम बोलना चाहते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, इनका दो मिनट का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अनिल कुमार साहनी: सर, मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुझको तो लगता है कि आप पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, सिर्फ झाल बजाने के लिए यह विभाग बना हुआ है क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपको क्या अभी जो आया है छात्रवृत्ति के लिए जो छात्रवृत्ति अति पिछड़ा और पिछड़ा को जो मिलेगा उसका टोटल उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति और प्राथमिक विद्यालय के छात्रवृत्ति के लिए 30 हजार लाख करोड़ रुपया का आप जो दिए हैं, ये आप अपने विभाग से नहीं बांट रहे हैं आप शिक्षा विभाग से बांट रहे हैं तो क्या घंटा और घंटी बजाने के लिए अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग आयोग है ? जवाब दीजिए । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग बांट रहा

है, आप अति पिछड़ा के होकर और अति पिछड़ा का पैसा शिक्षा विभाग बांटेगा जो अपने शिक्षकों को पैसा नहीं दे रहा है जो अपने काम करने वाले शिक्षकों को पैसा नहीं दे रहा है, क्या वह अपने बच्चों को पैसा देगा ? आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप अति पिछड़ा को छात्र क्रेडिट कार्ड नहीं दिए हैं, आप ये क्रेडिट कार्ड कब तक देते हैं ये बताइए, अति पिछड़ा आयोग कब तक गठन करते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग कब तक गठन करते हैं ये बताइए ? मैं अंत में पर्यटन विभाग पर भी कुछ बोलना चाहता हूं कि शोषित, उपेक्षित, दलित, पिछड़ा...

अध्यक्ष: आप बैठने की व्यवस्था कीजिए ।

श्री अनिल कुमार साहनी: हमारे पास समय है हमारे लोग नहीं बोलेंगे ।

अध्यक्ष: आपके बोलने के लिए और समय बढ़ा दें ?

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, थोड़ा-सा और समय बढ़ा दीजिए ।

अध्यक्ष: ठीक है, कितना समय और बढ़ा दें आप बोलिए ?

श्री ललित कुमार यादव: एक मिनट बढ़ा दीजिए ।

अध्यक्ष: पांच मिनट बढ़ चुका है, अभी तक । एक मिनट उनका बढ़ा है, दो मिनट इनका बढ़ा है अब फिर बढ़ेगा, पांच मिनट हो जाएगा ।

श्री अनिल कुमार साहनी: महोदय, पर्यटन विभाग, देश और विश्व में कई अनोखे स्थान हैं, जहां देखने और जाने का मन में आता है ध्यान, जहां देखने और जाने का मन में आता है ध्यान । महोदय, हमारे बिहार में भी कई स्थान ऐसे हैं जहां बिहार के पर्यटन विभाग का न है ध्यान, जहां बिहार के पर्यटन विभाग का न है ध्यान और मैं बता देना चाहता हूं कि कालांतर में बिहार के कई स्थानों में जहां मेलों में स्थानीय रूप से लाखों लोगों का जमावड़ा होता है और परंपरागत रूप से पूजा अर्चना होती है, लेकिन उस पर पर्यटन विभाग का ध्यान नहीं जा रहा है । हमारे अति पिछड़ा समाज के देवता अमरसिंह महाराज, बाबा केवन महाराज, इनवाड़ा समस्तीपुर चूहड़मल महाराज, भूईया बाबा, दयाराम, फेकूराम, मीरा साहब इत्यादि पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों और अकलियतों के देवता जिन्होंने उस समय के सामन्तशाहियों से लड़ने का काम किया, गरीब को अधिकार दिलाने का काम किया, उसको पर्यटन स्थल से नहीं जोड़ा जाता है । विजय बाबू यहां पर बैठे हुए हैं, इनके साथ और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेरी अध्यक्षता में बाबा केवल के मेले का सरकारीकरण किया गया था । मैं पर्यटन मंत्री से इस बात की मांग करता हूं कि जो शोषित, उपेक्षित के लिए लड़ने वाले थे उनको पर्यटन स्थल से जोड़ा जाय और अमर शहीद युवा सहनी के नाम पर जो उनकी जन्मस्थली है चैनपुर मीरा पुर

में, उसको भी पर्यटन स्थल से जोड़ा जाय तब जाकर पर्यटन का विकास होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समय-समय पर हमारा समय बढ़ाते रहे । जय हिन्द !

अध्यक्ष: श्री बिजय सिंह ।

श्री बिजय सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे उद्योग विभाग पर बोलने का अवसर दिया । पुन: मैं बरारी विधान सभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे लोकतंत्र के...

अध्यक्ष: शांति बनाए रखिए ।

श्री बिजय सिंह: मंदिर में भेजने का काम किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उद्योग विभाग हेतु 12 अरब 85 करोड़ 17 लाख 16 हजार रुपये की अनुदान मांग पर बोलने हेतु आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री उद्योग विभाग द्वारा जो अनुदान की मांग प्रस्तुत की गई है मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार तथा सदन अवगत है कि वर्तमान सरकार द्वारा उद्योग के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं जिसके तहत राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास हेतु एक नई उद्योग नीति वर्ष 2016 में लागू की गई है जिसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के रूप में भी हम सभी जानते हैं । बिहार में उद्योगों को आकर्षित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उक्त उद्योग नीति में संशोधन भी हुआ है जिसमें निम्न उद्योग प्रक्षेत्रों को प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्रों में जोड़ा गया है ।

क्रमश:

टर्न-17/यानपति-अंजली/05.03.2021

क्रमश:...

श्री बिजय सिंह: जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग कोल्ड चेन एंड वोटलिंग इकाइयों को रखा गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, लघु संयंत्र निर्माण वाले अंतर्गत कृषि और गैर कृषि संयंत्र को सम्मिलित किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में विनिवेश के अवसर पैदा किये गये हैं उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ई-वाहन, एथनॉल उत्पादन, दलहन आधारित एवं भारतीय रसोइयों को ध्यान में रखते हुए मसाला से जुड़े हुए उद्योग को भी जोड़ा गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को पुन: बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के निर्देश में कोरोना काल के बाद भी उस महामारी से

उत्पन्न संकट से निबटने हेतु रोजगार के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस महामारी संकट के दौरान बिहार प्रदेश में लौटे कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कई कार्य किये गये हैं । राज्य में युवाओं को उद्योग की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार स्टार्ट-अप नीति-2017 लागू किया गया है जो अभीतक लागू है । इसके लिये सरकार द्वारा लगभग 5 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अतिपिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजनाओं को प्रारंभ किया गया है । इसके तहत सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत 102 परियोजनाओं को रखा गया है । सरकार द्वारा इस उद्यमी योजना से जुड़नेवाले प्रत्येक युवक-युवतियों को योजना की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम पांच लाख रुपये तक का लगभग ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है । इस योजना से जुड़नेवाले राज्य के निवासी अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे तथा सरकार के आत्मनिर्भर बिहार का सपना भी पूरा हो सकेगा । साथ ही बिहार के उद्यमी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु समर्थ हो सकेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य विभाजन के फलस्वरूप राज्य में पूर्व से स्थापित अधिकांश औद्योगिक इकाइयां झारखंड के राज्य के हिस्से में चली गयीं । उस समय बिहार उद्योग विहीन राज्य के रूप में जाना जाने लगा लेकिन हमारी सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों एवं नियमों के द्वारा राज्य में फिर से उद्योग का माहौल कायम करने का प्रयास किया है जिसमें हम सफल भी हुए हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पहली बार कटिहार जिला में बरारी विधान सभा क्षेत्र से सदन में सदस्य बनने का अवसर मिला है । इस क्षेत्र की जनता एवं कटिहार की चिर-परिचित जो मांग है इसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा । माननीय महोदय, कटिहार जिला एक प्रसिद्ध औद्योगिक इकाई के रूप में जाना जाता था । कटिहार में दो-दो दियासलाई फैक्ट्री, दो-दो जूट मिल हुआ करते थे लेकिन आज वे बंद पड़ी हुई हैं । इन फैक्ट्रियों में काम करनेवाले मजदूर तकनीकी कर्मचारी बगल के बंगाल एवं नेपाल में काम करने जा रहे हैं मैं माननीय मंत्री उद्योग से आपके माध्यम से मांग रखना चाहूंगा कि इन बंद फैक्ट्रियों को चालू करने की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाकर पहल की जाय । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कटिहार से ये उप मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाकर तात्कालिक वहां के जो भारत सरकार की जो टेक्सटाइल मंत्री हैं स्मृति ईरानी से मिलकर के और हमारे पूर्व एम0एल0सी0 राजवंशी सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाकर के मिली भी थीं कि बिहार के जूट मिल चालू किये जायं । लेकिन अभीतक चालू नहीं हो पाया

है। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि उस जूट मिल को चालू किया जाय ताकि जो हजारों लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री प्रेम कुमार ने आसन ग्रहण किया)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन में यह भी बताना चाहूंगा कि पूरे बिहार में मखाना उत्पादन में कटिहार अव्वल रहा है । इस जिले में मखाना का कलस्टर बनाकर और इसका प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कराकर स्थानीय स्तर पर एक कटिहार को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पुरानी छवि को बहाल रखने एवं स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मुहैया कराने के क्षेत्र में बेहतर माहौल होगा । इसके अलावे कटिहार जिला की जो मुख्य फसलें हैं मक्का, जूट, केला प्रमुख हैं जिनकी अच्छी पैदावार इस जिले में होती है । कटिहार जिला के केले और मखाना की मांगें विदेशों में भी होती हैं । महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने बिहार राज्य में बेहतर औद्योगिक माहौल कायम करने की दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाये हैं । नयी उद्योग नीति, स्टार्ट-अप नीति बनाकर औद्योगिक क्षेत्रों एवं नव उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु...

सभापति(श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य बिजय बाबू, आपका मात्र एक मिनट समय बचा है ।

श्री बिजय सिंह: सर, हम नये सदस्य हैं आपके संरक्षण की आवश्यकता है । कारगर व्यवस्था की गयी है इसके अलावे सरकार के स्तर पर यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक जिले की जो प्रमुख फसलें हैं उसपर एक उद्योग निर्धारित किया जाय । सदन के माध्यम से हम चाहेंगे कि कटिहार में चूंकि मक्का बहुत ज्यादा होता है इसलिए मक्का पर आधारित स्टार्ज की एक फैक्ट्री लगायी जाय ताकि वहां पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके । पुनः मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सरकार की इन नीतियों से बिहार में उद्योगों का नया माहौल बनेगा तो राज्य जो है आत्मनिर्भर बनेगा । मुझे पुनः बोलने का अवसर दिया गया बहुत-बहुत धन्यवाद । जय बिहार-जय नीतीश कुमार ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, आपका 9 मिनट समय है ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता: माननीय सभापति महोदय और हमारी पार्टी के सदन के नेता महबूब आलम साहब, हमारी पार्टी भाकपा माले और सिकटा क्षेत्र की जो महान जनता है उसके द्वारा मुझे यहां जिता कर भेजा गया है और इस अवसर पर मैं सदन में बोल रहा हूं । मैं सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, आज यह पूरा सदन बिहार के औद्योगिक बजट पर चर्चा कर रहा है । हम समझते हैं चाहे वह पक्ष के लोग हों या सरकार के पक्ष के लोग हों पूरे सदन की चिंता इस बात पर जरूर है कि बिहार का

उद्योग धंधा कैसे फले-फूले । हम इस संबंध में समझते हैं महोदय कि बिहार में कोरोना काल में एक बड़ा सबक बिहार को दिया । बिहार के लाखों-लाख नौजवान जो थे, वह बिहार के दूसरे राज्यों में कोरोना बम कहकर के पीटे जा रहे थे, वह भूख के शिकार थे। बहुत सारे आफत को झेलकर के वह बिहार में आये । बिहार में सरकार ने उनको आने से रोकने की कोशिश की लेकिन फिर वह आये । अब बिहार में, बिहार के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको यह सोचने की बात थी कि बिहार में उद्योग धंधे कैसे लगें, बिहार से पलायन कैसे खत्म हों, जो मृतप्राय उद्योग हैं वह कैसे चालू हों इस पर सभी लोगों को सोचना है, इस सदन को भी सोचना है । हम समझते हैं कि गंगा में बहुत पानी बह चुका है और आरोप-प्रत्यारोप से इस समस्या का समाधान नहीं होगा कि 15 साल पहले क्या हुआ, हम सदन से कहना चाहते हैं महोदय कि बिहार में जूट मिल की जो बात आ रही थी अभी कि कटिहार की जूट मिल दो-दो हुआ करती थी वह बंद है । वहां के जूट किसान जो हैं करीब दो करोड़ जो लोग हैं, वह बंगाल में अपना जूट सप्लाई करते हैं । यहां वह जूट मिल नहीं चल सकीं । बिहार में 28 चीनी मिलें हुआ करती थीं आज मात्र 9 चल रही हैं । इस साल दो चीनी मिलें भी बंद हो गईं । रीगा की चीनी मिल बंद हो गई, लाखों एकड़ जो गन्ना की फसल है, खेतों में सूख रही है उन किसानों को मुआवजा देने की भी बात नहीं सोच रही है सरकार । सासामुसा की चीनी मिल बंद हो गई । करीब 2 सौ करोड़ रुपये पिछले साल का गन्ना किसानों का बकाया है । मझौलिया चीनी मिल का 40 करोड़ रुपया, रीगा चीनी मिल का सवा सौ करोड़ रुपया किसानों का बाकी है और इस तरीके से सासामुसा चीनी मिल का, गोपालगंज चीनी मिल का पूरे पिछले साल की हम बात कर रहे हैं महोदय, यह किसानों का पैसा बाकी है । फिर हम अब देखते हैं महोदय कि इस साल मझौलिया चीनी ने बस 30 दिसंबर तक का पेमेंट किया है । हमलोग मार्च में हैं तो इस साल के तो और करोड़ों-करोड़ रुपये बाकी हैं और ये बिहार की आर्थिक सर्वे जो रिपोर्ट है उसमें भी बात आई है कि बिहार का गन्ना उद्योग जो है वह मर रहा है । लेकिन इस बजट में यहां चीनी उत्पादन भी कम हो रहा है पिछले दो-तीन सालों से, गन्ने की खेती भी कम हो रही है लेकिन इस बजट में जो है वह गन्ना उद्योग को कैसे जिंदा किया जाय, उसको कैसे ताकत दी जाय तो इस बजट में मात्र 115 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । हम सदन से कहना चाहते हैं महोदय कि इस तरीके से तो गन्ना उद्योग पूरी तरह खत्म हो जायेगा । जो 9 चीनी मिलें बची हैं वह भी बंद हो जायेंगी । बिहार की चमड़ा फैक्ट्रियां एक-एक करके बंद हो गईं । फुलवारी यहां बगल में एक बड़ा औद्योगिक हब की तरह था, साइकिल फैक्ट्री थी, ये चमड़ा फैक्ट्री

थी, बिहटा की चीनी मिल उसके बगल में थी ये तमाम बंद हो गईं और आज हम देखते हैं कि पूरे बिहार की चमड़ा फैक्ट्रियां बंद हैं इक्का-दुक्का चल रही हैं और बिहार कृषि प्रधान जगह है । आप कह रहे हैं कि हम कृषि को बढ़ावा देंगे, बकरी पालन को बढ़ावा देंगे, मवेशी पालन को बढ़ावा देंगे, चमड़े की जरूरत है लेकिन आपका चमड़ा उद्योग का कोई कारखाना नहीं चाहिए आपको, इस पर आपका कोई बजट नहीं है ।

(क्रमशः)

टर्न-18/सत्येन्द्र/05-03-21

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता(क्रमशः): हम सदन से कहना चाहेंगे महोदय कि यहां जो स्थिति फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की है, ये आम का इलाका है, यहां आम का काफी उत्पादन होता है उसकी जेली बन सकती है, लीची की जेली बन सकती है, केले की जेली बन सकती है लेकिन कोई इसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है। महोदय, बात हो रही थी पिछले दिनों, हमलोगों के बीच उद्योग मंत्री जी बैठे हुए है और दिल्ली से आये हैं, बात हो रही थी उद्योग धंघों के विकास की तो कह रहे थे कि बिहार में जो है इथनॉल का उत्पादन किया जायेगा। महोदय, ये सरकार हम समझते हैं कि गांधी जी की बात करती है, गांधी जी की बातें आती है, गांधी जी ने तो नील की खेती का विरोध किया था चूंकि नील की खेती जो है वह अनाज की खेती को प्रभावित करती थी अनाज की खेती का रकवा जो है उसको छेक लिया था नील की खेती का रकवा और इस कारण भूखमरी और अकाल आ गया था, उस अंग्रेजी जमाने में पूरी तरह से अकाल की स्थिति हो गयी थी। चम्पारण का अकाल हो या बंगाल का अकाल हो उसमें नील की खेती भी एक बड़ी बात थी ...

सभापति(श्री प्रेम कुमार) अब आपका समय मात्र 2 मिनट बचा है।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ताः हम ये कहना चाहते हैं महोदय कि ये इथनॉल बनाने की जो बात हो रही है इससे बिहार में भूखमरी आयेगी, हिन्दुस्तान में भूखमरी आयेगी । हम यह कहना चाहेंगे जिस हिन्दुस्तान में 58 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, 53 प्रतिशत महिलाएं गर्भवती नहीं है, वह भी ऐनिमिया की शिकार हैं, भारत जो है ग्लोबल 100 Index में 10 देशों की सूची में 102 वें स्थान पर है। वह बंगला देश से भी पीछे है, नेपाल से भी पीछे हैं, इस प्रकार यहां इथनॉल बनाने की बात सोचना लोगों को भूख से मारने के अलावा कुछ नहीं है। महोदय, हम सदन में यह बात कहना चाहेंगे, बिहार में विगत 15 सालों में बहुत नाटक हुए, यहां एन0आर0आई0 का सम्मेलन कराकर भोज कराया गया उसमें तरह तरह के कम्पनियों के सी0ओ0 को बुलाकर भोज कराया गया लेकिन उस भोज भात से बिहार में कोई पूंजी नहीं आयी । आज बिहार की जो स्थिति है महोदय,

यहां मात्र 1.1 प्रतिशत कारखाना है और भारत के कारखानों की तुलना में बिहार में स्थिति 0.4 प्रतिशत है, बिहार में क्रियाशील पूंजी 0.5 प्रतिशत है और ...

सभापति(श्री प्रेम कुमार) आपका समय समाप्त हो गया । आप आसन ग्रहण करें।

माननीय सदस्य श्री ललन कुमार जी।

(व्यवधान)

श्री ललन कुमार: माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज सदन में बोलने का पहली बार मौका दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पीरपैंती की जनता मालिक का जिन्होंने मुझे भारी मतों से चुनाव जीताकर इस सदन में भेजा है। सभापति महोदय, मैं आज सरकार के तरफ से, माननीय मंत्री जी के द्वारा लाये गये मांग प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आज माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी का सदन में स्वागत करता हूँ और मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूँ कि आपको देश के लिए केन्द्र सरकार में काम करने का बहुत लम्बा अनुभव प्राप्त है, आपने केन्द्र में फुड प्रोसेसिंग, टेक्सटाईल्स, उद्योग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय सहित 6-6 विभागों को वखूबी संभाला है ओंर उसे आगे बढ़ाया है। हम सब के प्रेरणाश्रोत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के परम शिष्य ही नहीं वे उनके चेहते रहे हैं और आप माननीय बिहार के मुख्यमंत्री विकास एवं सुशासन के प्रतीक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के भी अच्छे मित्रों में से एक है, उनके नवरत्नों में एक हैं। अब आपको प्रधान मंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार भेजा है, आप से बिहार के 14 करोड़ बिहार वासियों को बहुत उम्मीद है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केन्द्र में रहकर बहुत ही अच्छा काम किये हैं, विपक्ष भी इसे मानती और स्वीकार भी करती है इसलिए हम बिहारवासियों को उम्मीद है आपसे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप लोग बिहारवासियों के उम्मीद पर खरे उतरेंगे, आपलोगों के कठिन परिश्रम, त्याग, सेवा भाव व नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। बिहार का गौरवशाली अतीत पुनर्स्थापित होगी। हमें याद है जब आप केन्द्र में मंत्री थे तो बुनकरों के लिए आर्टिजन क्रेडिट कार्ड देकर उनकी ऐतिहासिक मदद की थी जिसकी सराहना भारत के साथ साथ पूरे विश्व में हुई थी इसलिए बिहार की 14 करोड़ जनता आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। पार्टी के शीर्ष नेताओं में आज भी आपका शुमार है। केन्द्र राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से आप बिहार में जिलावार उद्योगों का जाल बिछाने का काम करेंगे, इसकी हमें काफी उम्मीद है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत केन्द्र बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के

लिए क्या क्या मदद कर रही है, यह आप आज सदन को बताने का काम करेंगे, यह हम सदन की ओर से आपसे निवेदन करते हैं माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, यह विडम्बना है कि जिस राज्य का अपना नाम शांत और निर्मल मठों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले बौद्ध शब्दावली बिहार से मिला था वही बिहार आजादी के बाद पतन के लम्बे दौर से गुजरा । वर्ष 1990 से 2005 के बीच 15 वर्षों में विकास में और तेजी से गिरावट आयी, विगत 15 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अतीत के दुर्भाग्यपूर्ण ढांचे को तोड़ते हुए भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्य के तौर पर उभरकर बिहार सामने आया है । बिहार पिछले दशक में 10 फीसदी से ज्यादा की सलाना वृद्धि दर से बढ़ा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कानून और व्यवस्था बहाल किये, वही विकास की वृद्धि का मुख्य वजह रहा है । महोदय, पिछले दशक के दौरान राजस्व संबंधी समझदारी इंफ्रास्ट्रक्चर और लक्ष्य आधारित खर्च और विकास की बेहतर मिसाल बनकर उभरा है, गरीबी कम करने और पलायन को रोकने के लिए राज्य को तेज औद्योगिकीकरण और कृषि आधारित उद्योग को प्रमुखता से स्थापित करने की जरूरत है। महोदय, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के विकास और सुशासन तथा आत्मनिर्भर बिहार के प्रति प्रतिवद्धता ने राज्य से पलायन को रोका है जो राज्य के उद्यमी बिहार से पलायन कर रहे थे और छतीसगढ़, मध्यप्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में जा रहे थे, सुशासन इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा ढांचा तैयार किया गया कि आज बिहारी प्रवासी उद्यमी राज्य में निवेश करने के लिए वापस आ रहे हैं। (क्रमशः)

टर्न-19/मधुप/05.03.2021

..क्रमशः..

श्री ललन कुमार : सभापति महोदय, सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम सभी यहाँ बिहार के विकास के लिए पक्ष और विपक्ष आपस में वाद-विवाद कर रहे हैं । सबका उद्देश्य है कि बिहार में उद्योग लगे, बिहार से पलायन रूके, बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उसकी उपज का अच्छा दाम मिले, बस उसी उद्देश्य से हमलोग यहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं । मेरा सौभाग्य है, जहाँ तक माननीय मंत्री जी को मैं जानता हूँ, मैं भागलपुर से हूँ पीरपैंती से, ये भागलपुर से दो बार सांसद रह चुके हैं, मैं पीरपैंती से विधायक चुनकर आया हूँ, आज मेरा परम सौभाग्य है, ईश्वर का वरदान है कि माननीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी के साथ सड़क से लेकर

सदन तक काम करने का मौका प्राप्त हुआ है । लोहिया जी हमेशा सड़क और सदन की बात करते रहते थे । सड़कों की बात अगर सदन में उठे, सड़कों की बातों की चर्चा अगर सदन में हो तो लोकतंत्र के जिन्दा होने की निशानी है जो आज यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है ।

महोदय, मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि देखिये, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे । महोदय, हमारे यहाँ जो रॉ-मेटेरियल्स हैं, अभी जरूरत है यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को लगाने की, कृषि आधारित उद्योगों को जिलावार लगाना चाहिए । हमारे बिहार में खास करके पीरपैंती में बाखरपुर का इलाका हो, खवासपुर का इलाका हो, अंतीचक का इलाका हो, पीरपैंती, कहलगाँव का इलाका हो, चाहे प्यारापुर का इलाका हो, बाराहाट रौशनपुर का इलाका हो, ये तमाम जगहों पर प्रचुर मात्रा में मक्के की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, धान की खेती होती है, आलू की खेती होती है । महोदय, प्रचुर मात्रा में भागलपुर जिले में केला होता है, पड़ोस के कटिहार, पूर्णिया में मखाना का भंडार छुपा हुआ है । पिछले दिनों कृषि मेला के उद्घाटन में माननीय मंत्री के साथ मैं गया था और हमने देखा कि जिस तरह से बिहार सरकार के कर्मचारी, जो कृषि विभाग के वैज्ञानिक-अधिकारी काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बिहार को बनाने के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, उससे लगता है कि हमलोग आत्मनिर्भर बिहार के सपना को साकार करेंगे, नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सफल हो पायेंगे । बस एक ठोस निर्णय लेने की जरूरत है कि हमें अपने रॉ-मेटेरियल्स को रोकना पड़ेगा ।

महोदय, आज जो बातें निकल कर आ रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है कि बिहार इथेनॉल का हब बनने जा रहा है । इथेनॉल के लिए जो रॉ-मेटेरियल्स की जरूरत है, खास करके मक्का, गन्ना, धान ये सब हमलोगों के पास पर्याप्त मात्रा में है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि एक ऐसा कानून भी बने इस सदन के अंदर कि हमारा जो मक्का है, हमारा जो धान है, हमारा जो गन्ना है, वह बिहार से बाहर नहीं जा सके । आज हमारे बिहार के नौजवान और बिहार के किसान सबसे पहले औने-पौने दाम में गन्ना, धान, गेहूँ और मक्के को बेचने के लिए विवश होते हैं । वही मक्के, धान और गेहूँ बाहर जाकर उससे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, अन्य राज्यों में....

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब आपका समय मात्र 2 मिनट बच रहा है ।

श्री ललन कुमार : फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, वहॉ पर जाकर हमारे नौजवान काम करते हैं । कोरोना के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प लिये हैं, हम चाहते हैं, आज मंत्री से हम कहना चाहते हैं कि आप मक्का को रोकिये, गन्ना को रोकिये, धान को रोकिये, केले को रोकिये, मखाना को रोकिये और यहीं पर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाइये जिससे यहॉ के किसानों को उसके अनाज का उचित दाम मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा । यहॉ पर जरूरत है केला को बढ़ावा देने की, मखाना को बढ़ावा देने की जरूरत है । माननीय मंत्री जी भागलपुर के सांसद रहे हैं, सौभाग्य है भागलपुर का, भागलपुर की इनकी पहचान है, आप जानते हैं कि हमारा भागलपुर विश्व विख्यात है, भागलपुर का सिल्क, भागलपुर का रेशम तसर, आज लीलेन के क्षेत्र में भी भागलपुर दुनिया में नाम कमा रहा है । इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, इसकी मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसके लिए हम चाहते हैं । आप सभी जानते हैं महोदय, यहॉ दिल्ली से लेकर पटना तक हमारा भागलपुर का जर्दालू आम कितना फेमस है, हमें गर्व है कि हमारे भागलपुर की मिट्टी, पीरपैंती, कहलगॉव की मिट्टी दुनिया का सबसे उत्तम किस्म का आम पैदा करती है । हम चाहते हैं, मंत्री जी इसपर ध्यान दें और हमारे आम का इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो ताकि पीरपैंती भागलपुर का बिहार के साथ-साथ भारत का नाम विश्व में गौरवमयी हो । हम चाहते हैं....

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री ललन कुमार : महोदय, हम चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर हम युवाओं को काम दें । हम चाहते हैं कि हमारे किसान अनाज पैदा करें और किसान के पढ़े-लिखे बेटे-बेटियॉ उसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में काम करें, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अपना फूड प्रोडक्ट तैयार करें ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें । आपका समय समाप्त हो गया है । माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

श्री ललन कुमार : आज हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हम जो आलू पैदा करते हैं, महज 5 रू0, 8 रू0 किलो बेचते हैं वही आलू अगर हमारे नौजवान फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से बाहर लायेंगे तो 300 रू0 किलो में बेचेंगे ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आप बैठ जाइये ।

श्री ललन कुमार : महोदय, आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हैं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी जी । आपका समय 4 मिनट है ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : महोदय, मैं उद्योग विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ । साथ-ही, बहादुरगंज के विधान सभा क्षेत्र की समस्त जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ ।

महोदय, आज के इस तकनीकी दौर में कृषि के अलावा अगर और कोई भी रोजगार प्रदान करने का क्षेत्र है तो वह है उद्योग का क्षेत्र । अगर उद्योग को बढ़ावा दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि आज जो रोजगार के लिए पलायन करते हैं इसमें कमी आयेगी। लेकिन सच तो यह है कि किसी भी देश और राज्य की तरक्की के लिए उसका दारोमदार उद्योग है लेकिन यहाँ वह नगण्य है । आज कोई भी सरकार की, चाहे पूर्व की हो या अभी वर्तमान सरकार हो, इसमें रूचि कम ही है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विशेष निवेदन करता हूँ कि बिहार के विकास और खुशहाली के लिए उद्योग को बढ़ावा दिया जाय । आज बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, मुँगेर जिले की राष्ट्रीय आय अधिक इसलिये है क्योंकि यहाँ कुछ उद्योग-धंधे लगे हुए हैं जिस कारण अन्य जिलों से यहाँ का राष्ट्रीय इनकम ज्यादा है ।

न जाने क्यों सीमांचल जैसे क्षेत्र में सरकार की रूचि कम ही रही है । सीमांचल क्षेत्र में पूर्व में दो उद्योग लगे हुये थे, एक कटिहार जूट मिल और दूसरा बनमंखी का सुगर मिल । हमारे उद्योग मंत्री शाहनवाज साहब जब एम0पी0 हुआ करते थे तो कटिहार जूट मिल को चालू करने की बात और प्रयास भी इन्होंने किया था । शायद क्यों नहीं चालू हो पाया, मैं नहीं बता सकता लेकिन इन्होंने किशनगंज में एक जूट मिल की भी स्थापना की बात कही थी और इसका शिलान्यास भी किया था लेकिन अबतक चालू नहीं हो सका ।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि आपका सीमांचल से विशेष रिश्ता रहा है । आपको अच्छा मौका मिला है कि आप सीमांचल का कर्ज उतारें खासकर किशनगंज जहाँ की जनता ने आपको पहली बार संसद में भेजने का काम किया । पूरे बिहार में दूसरे नम्बर पर मक्का, जूट, धान और इसके अलावा चाय, अनानास एवं केला की खेती होती है और पैदावार रेकर्ड स्तर पर होता है फिर भी सबसे अधिक पलायन दर हमारे सीमांचल क्षेत्र का ही है । किशनगंज में जूट, चाय, मक्का, अनानास का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की असीम संभावना है । अगर इसपर विचार किया जाय तो हमारे पलायन को रोका जा सकता है । इसके न होने के कारण किशनगंज आज पलायन का केन्द्र बन चुका है । जूट का पैदावार अगर आज

किशनगंज में कम हुआ है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी इससे संबंधित फैक्ट्री का नहीं लगना ।

महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सब्जियों का, जूट का, चाय का प्रोसेसिंग यूनिट अगर लगाया जाय तो मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके से पलायन को रोका जा सकता है । सीमांचल में उद्योग के लिए कई ठोस प्लान पर काम करने की जरूरत है । सब्सिडी के साथ-साथ एक निश्चित अवधि के लिए टैक्स से मुक्ति देनी होगी, उद्योग लगाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करना होगा । मैं आकलन करता हूँ कि अबतक बिहार उद्योग के क्षेत्र में महरूम रहा है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका समय मात्र 1 मिनट बचा है ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है । हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले वर्ष हमारे विधान सभा क्षेत्र के वेणुगढ़ में एक तालाब के जीर्णोद्धार के लिए, जल जीवन हरियाली के तहत उसके सौन्दर्यीकरण के लिए गये हुये थे, उन्होंने उसके विकास की बात कही थी लेकिन वह भी आज तक अधूरा पड़ा हुआ है । अगर इसका भी विकास होगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में पर्यटन के विकास की वजह से रोजगार भी उपलब्ध होगा । हमारा बिहार तरक्की की राह पर चले और हमारा बिहार खुशहाल हो, इन्हीं तमन्नाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ । शुक्रिया ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी । आपका समय 3 मिनट है।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : माननीय सभापति जी, आज 17वीं विधान सभा में उद्योग विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका मिला है । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, श्री जीतन राम मांझी और सिकंदरा विधान सभा क्षेत्र की महान जनता का सादर अभिनंदन और वंदन करता हूं । ...क्रमशः...

टर्न-20/आजाद/05.03.2021

..... क्रमशः ....

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : महोदय, आज उद्योग बजट पर बोलने का जो मुझे अवसर मिला है, मेरा मानना है कि बिहार में प्राकृतिक संसाधनों एवं श्रम संसाधनों की प्रचुरता है । युवाओं के लिए बिहार को त्वरित विकास के लिए सरकार कुटीर उद्योग के लिए कलस्तर एप्रोच की जो घोषणा की गई है, जिसमें सात कलस्तरों की शुरूआत की गई है, जिसमें राईस मिल, बटन उद्योग, सिलाव का खाजा, सीतामढ़ी का पीतल और तॉबे के बर्तन का उद्योग लगाया जा रहा है । चूँकि उद्योग-धंधे स्थापित करने के लिए राज्य में सड़क और बिजली-पानी

की आवश्यकता होती है । हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बिहार राज्य में सड़कों का जाल बिछाया है । आज हम जहां पर भी उद्योग लगायेंगे, जिस दिशा में भी जाने का प्रयास करेंगे, पूरे बिहार में 5-6 घंटे में हम दौरा कर सकते हैं, 7 घंटे में पूरब से पश्चिम जा सकते हैं । इसके लिए हम चाहेंगे कि माननीय बहुत परिपक्व और बहुत मेहनती बिहार के उद्योग मंत्री बनाये गये हैं सैयद शाहनवाज हुसैन जी । बिहार कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य होने के नाते यहां बहुत ज्यादा कृषि की उपज होती है, सब्जियों की उपज होती है और यहां फुड प्रोसेसिंग का जो .....

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : आपका समय मात्र एक मिनट बचा है ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में चाहेंगे कि बिहार पौराणिक दृष्टिकोण से भी अपना स्थान रखता है । यहां बुद्ध और महावीर की धरती, यहां रामायण की सर्किट हम चाहेंगे कि बिहार का जो अस्तित्व है, बिहार जो बौद्ध का स्थल रहा है, जगह-जगह उसके स्थल पाये जा रहे हैं, उसको बुद्ध सर्किट से जोड़ा जाय और हमारा जो जमुई जिला का क्षेत्र है, वहां भगवान महावीर की जन्मस्थली है और वहां बहुत से लाखों पर्यटक आते-जाते हैं । जिससे इस बिहार में आय की बढ़ोत्तरी होती है । हम माननीय पर्यटन मंत्री जी से निवदेन करेंगे कि उस महावीर जैन के जन्मस्थली को और सौंदर्यीकृत किया जाय, चूँकि वह पहाड़ों के बीच में है । अगर ऐसा किया जायेगा तो पूरे बिहार से यानी पूरे देश से और पूरे विश्व से हमारे देश में महावीर और बुद्ध को मानने वाले पर्यटक आयेंगे ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : कृपया आसन ग्रहण कर लें, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : चूँकि लखीसराय का जो जिला है, नये-नये स्थल पर भगवान बुद्ध का सर्किट मिला है, उसको बुद्ध सर्किट से जोड़ा जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय और हम इस बजट का समर्थन करते हैं ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री ऋषि कुमार, आपका समय है 10 मिनट ।

श्री ऋषि कुमार : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहां आने का अवसर दिया ।

महोदय, कई बार हमने देखा है और सुना भी है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार उस 15 साल पर चली जाती है, जो गुजर चुका है या इतिहास के पन्ने में खो चुका है । मैं आपके सामने कुछ आंकड़ें रखना चाहता हूँ

महोदय। हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है पिछले दो साल में 7.8 प्रतिशत ग्रौथ रेट से घटकर 2.9 प्रतिशत हो चुका है जो कि लगभग 5 प्रतिशत का डिकलाइन है । किसी भी औद्योगिक क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए महोदय सकल राजकीय मूल्यवर्द्धन किया जाता है जी0एस0वी0ए0 । जो हमारे देश का एवेरेज है महोदय जी0एस0वी0ए0 का मतलब यह है कि हमारी जो मैन्यूफैक्चरिंग और हमारे जो उद्योग हैं उनका कमाई में क्या हिस्सा है देश में या अपने राज्य में तो जो जी0एस0वी0ए0 का हमारा जो नेशनल एवरेज है वह 31 प्रतिशत का है यानी 31 प्रतिशत देश की कमाई में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है और वह बिहार के अन्दर 10 प्रतिशत उससे कम है, सिर्फ 20 प्रतिशत है, लगभग 11 प्रतिशत देश के एवरेज से कम है । महोदय, यह जो 20 प्रतिशत है, यह देश में सबसे ज्यादा कम है । किसी भी राज्य के तुलना में बिहार में सबसे ज्यादा कम है । छतीसगढ़ और उड़िसा जिसको हम बीमारू राज्य कहते हैं । छतीसगढ़ में यह 46.3 प्रतिशत है और उड़िसा में 45.6 प्रतिशत । महोदय, अपार श्रम शक्ति होते हुए भी हम जो है, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं । सरकार की उदासीन रवैया के कारण पलायन रूक नहीं रहा है । जो औद्योगिक क्षेत्र हमारे हैं, जो नियोजित औद्योगिक क्षेत्र है । एक फिगर ऐसा प्रजेंट कर रहा हूँ महोदय के सामने, जिसमें सरकार अपनी पीठ तो थपथपा सकती है कुछ सेकेंड के लिए, जो बिहार में फैक्ट्रियों की संख्या है नियोजित, जो चालू कारखाने हैं, वह 2881 हैं, जो कि झारखंड से 500 ज्यादा है और उड़िसा से 200 परंतु जो वार्षिक आय वकर्स की है, वह 136000/–रू0 है, जिसमें बोनस और सैलरी सबकुछ मिला हुआ है और झारखंड में जबकि 2366 फैक्ट्रियां हैं, वहां पर वार्षिक आय जो है मजदूरों की वह 393269/–रू0 है, वही उड़िसा में जहां 200 फैक्ट्रियां कम हैं बिहार से, वहां भी 331130/–रू0 है । महोदय, जो नम्बर्स ऑफ वकर्स है हमारे यहां प्रति फैक्ट्री, उसका भी अगर एवरेज देखें पिछले 4 सालों में तो वह 31 से 36 ही है । जबकि जो देश का एवरेज है फैक्ट्रियों का नम्बर्स ऑफ वकर्स का प्रति फैक्ट्री, वह लगभग 65.5 है । महोदय, अगर हम मिनिमम वेजेज की बात करें तो दिल्ली में जहां अनस्किल्ड लेबर के लिए 596/–रू0 प्रतिदिन तय किया गया है, यहां बिहार में अनस्किल्ड के लिए 292/–रू0 है । स्किल्ड लेबर दिल्ली में महोदय 723/–रू0 है और स्किल्ड लेबर बिहार में 451/–रू0 है और जो सेमी–स्किल्ड लेबर है दिल्ली में, उनका मिनिमम वेजेज है 657/–रू0 और बिहार में सेमी–स्किल्ड के लिए मात्र 304/– रू0 है । महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इथेनॉल लगाने के लिए अपनी पहल उठायी है । महोदय, एक समुचित विकास के लिए बिहार में हेवी इन्डस्ट्रीज की भी

बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अगर हेवी इन्डस्ट्रीज आती है तो हम ज्यादा से ज्यादा वकर्स को उसमें नौकरी दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दे सकते हैं । महोदय, जब यू0पी0ए0 की सरकार थी, केन्द्र में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तत्कालीन रेल मंत्री ने तीन फैक्ट्रियां दी थी बिहार को, एक बेला में व्हील की फैक्ट्री, दूसरा मधेपुरा में इलेक्ट्रीक इंजीन की फैक्ट्री और तीसरा मढ़ौरा में जी0 और इंडियन रेलवे का जो जे0वी0 हुआ, वह भी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दूरदर्शिता का नतीजा है । महोदय, एक और टर्म है हमारे इकोनॉमी में, जिसको सकल निर्गत मूल्य कहते हैं यानी जी0वी0ओ0 ग्रौस वैल्यू आऊटपुट और सकल मूल्यवर्द्धन कहते हैं जिसको जी0वी0ए0 कहते हैं ग्रौस वैल्यू एडिशन । महोदय, बिहार में पिछले तीन सालों में यह कॉनसेंट है । जो कि लगभग आधा प्रतिशत है, जो देश के इनकम में बिहार के उद्योग का कंट्रीब्यूशन है, वह कुल आधा प्रतिशत 0.5 प्रतिशत है और महोदय, वह भी पूरे देश के जितने भी राज्य है, उसमें सबसे कम है । महोदय, उड़िसा में यह लगभग 1.9 प्रतिशत था चार साल पहले, अब 2.8 प्रतिशत है और झारखंड में तीन साल पहले 1.4 प्रतिशत था, वह 2017-18 में 2.1 प्रतिशत है यानी यह हर जगह बढ़त हुई है इन सारे राज्यों में परंतु बिहार में बढ़त नहीं हो पा रही है । ..... क्रमशः ....

टर्न-21/शंभु/05.03.21

श्री ऋषि कुमार : क्रमशः हमारे उद्योग नहीं बढ़ पा रहे हैं और जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडीशन कहते हैं । यानी मान लीजिए कि हम सौ रूपये में मैटेरियल खरीदकर लाते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम उसमें जो वैल्यू एड करते हैं वह मात्र 12 रूपये आज के डेट में जो फीगर है और यह जो 12 रूपये होता है यह भी देश में सबसे कम है तो क्या कारण हो सकते हैं इसके- कारण है महोदय, एक तो पौलिसी हमारी सरकार की इंडस्ट्रीयल पौलिसी, दूसरा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें आनी चाहिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वह चीज हमारे पास नहीं है । महोदय, तीसरा क्रेडिट फैसेलिटी- इतने बैड डेट्स हुए हैं पूरे देश में और बिहार में भी कि बैंक कर्ज देने से डरती है, घबराती है कि पता नहीं उनके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे । महोदय, उड़ीसा और झारखण्ड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और यह याद रखनेवाली बात है कि बिहार से कम फैक्ट्रियां हैं दोनों राज्यों में तब उनका कंट्रीब्यूशन देश में ज्यादा है । यानी उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और वैल्यू एडीशन

भी ज्यादा है । महोदय, हमारी फैक्ट्रियां जो है वह अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर चल रही है । महोदय, एक जगह और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : अब आपका समय मात्र एक मिनट बचा है ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, अनौपचारिक उद्यम जो छोटे-छोटे उद्योग हैं जैसे कोई मोमबत्ती बना रहे हैं, कोई अगरबत्ती बना रहे हैं ऐसे छोटे-छोटे उद्योग अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर है इस सेक्टर को रेकॉगनाइज करने की सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है । इनके उपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्यूंकि ज्यादा महिलाएं ऐसे उद्योगों में हैं । ऐसे उद्योगों को अगर हम रेकॉगनाइज करते हैं उनको प्रोपर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको लोन की फैसेलिटी मिलेगी जो उनके एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है । इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इम्प्लाइड भी होंगे । महोदय, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय की कमी है । महोदय, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 में आयी थी जिसमें 1603 पिछले चार साल में आवेदन आये हैं यानी 2016 से लेकर दिसम्बर, 2020 तक यानी कुल आवेदन आये थे 19348 करोड़ के प्रस्ताव थे जिसमें चार साल में मात्र 1886 करोड़ रूपये का निवेश ही हो पाया बिहार में- आखिर ऐसा क्या कारण है कि पिछले चार साल में बिहार में सिर्फ 262 ईकाइयां ही लग पायी जबकि 1603 का आवेदन आया था । महोदय, कहीं न कहीं ये कहीं और चली गयी, यह हमारी फेल्योर है, हमने उनपर ध्यान नहीं दिया । इसीलिए वे दूसरे राज्य में चले गये । महोदय, 2018-19 में जहां 89 ईकाइयां कार्यान्वित हुई थी ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : कृपया अब समाप्त करें ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, वर्ष 2019-20 में मात्र 34 ईकाइयां ही कार्यान्वित हुई है जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 62 प्रतिशत कम है ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : कृपया, बैठ जायें ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, अर्थशास्त्री नहीं हूँ, पर लोगों का दुख दर्द समझता हूँ । इसीलिए अपनी बात रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव जी ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार नीरज जी, आपका समय 6 मिनट है, प्रारंभ करें ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : महोदय, 2021 में जीतने के बाद पहली बार मैं सदन में आया हूँ । कुछ बढ़ाया जाय 6 मिनट तो बोलेंगे ही ऐसे 5 मिनट में ही हम सलट लेंगे । हम हैं

बड़बोलिया बहुत बढ़चढ़ कर बोलते हैं, लेकिन सदन है सदन में बहुत लोग हैं विद्वान लोग हैं । हमारे पार्टी के नेता मुख्य सचेतक श्रवण बाबू बैठे हुए हैं ।

(व्यवधान)

अरे, बोलने न दीजिए ललित बाबू, हुज्जत मत कीजिए हमसे । विजय चौधरी जी बैठे हैं, हमारे विजेन्द्र बाबू बैठे हैं, हमारी अति पिछड़ा की बहन रेणु जी बैठी हुई हैं और उधर विपक्ष के मुख्य सचेतक बड़बोलिया हैं, बोलते रहते हैं वे बैठे हुए हैं, कम्युनिस्ट के लोग हैं और लोग चले गये, तेजस्वी भाई चले गये हैं और उधर पिछला बेंच पर मातृशक्ति बैठी हुई हैं, हमारी बड़ी बहन भागीरथी देवी जी बैठी हुई हैं । बंधुओं, मैं अति पिछड़ा और उद्योग और पर्यटन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । हम 2005 में सवाल उठाये थे, मेरा क्षेत्र भागलपुर केला में नामी है और मक्का फसल में नामी है इसलिए उद्योग लगाया जाय । माननीय प्रधानमंत्री जी जब एम0पी0 चुनाव के प्रचार में आये थे उन्होंने भागलपुर में यह कहा था कि केला और मक्का फसल का इलाका है यहां उद्योग लगेगा । हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : माननीय अमरेन्द्र बाबू आसन के बीच में आये हैं ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : मैं देख रहा था वे झुककर आये हैं । आप बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : अरे भाई, बोलने दीजिए न । इधर नन्दकिशोर बाबू भी बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन अमरेन्द्र बाबू भी हैं, सम्राट बाबू भी बैठे हुए हैं ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : बैठ जाइये, सत्यदेव जी ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : हम सभापति जी को देखकर बोल रहे हैं । हमसे हुज्जत मत कीजिए बोलने दीजिए, हम बहुत दिन के बाद आये हैं । हम बोले न कि पांच साल बीमार ही रहे हैं । इसलिए सबलोग यहां बैठे हुए हैं सबको दिल की गहराई से साधुवाद देता हूँ और क्रांतिकारी सलाम करता हूँ । तेजस्वी जी आ गये हैं मेरे छोटे भाई इनको भी मैं सलाम करता हूँ, लाल सलाम क्या ? हुज्जत मत कीजिए हमसे बोलने दीजिए । मैं अति पिछड़ा, पर्यटन और उद्योग पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । हमारा इलाका तो केला मक्का का है ही और हमारी बहन रेणु देवी- आ गये हमारे उप मुख्यमंत्री जी तारकिशोर बाबू उनको भी मैं क्रांतिकारी सलाम कहता हूँ । भाई, लाल सलाम एक बार बोल रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले क्रांतिकारी सलाम बोलते हैं आप कम्युनिस्ट हैं क्या ? हमने कहा कि

हमारे बाप दादा ही कम्युनिस्ट थे, हम कम्युनिस्ट नहीं हैं । हम जदयू के लोग हैं, लेकिन संघर्ष करते-करते मैं इस जगह पर आया हूँ इसलिए क्रांतिकारी सलाम करता हूँ । बंधुओं, विपक्ष के लोग सब बोल रहे थे कि केतारी विभाग का मिल सब बंद पड़ा हुआ है । मैं आग्रह करता हूँ ये शाहनवाज हुसैन जी हमारे छोटे भाई कहलाते हैं । इनसे मैं आग्रह करता हूँ कि जितना चीनी मिल है सबको खोल दिया जाय, सभी किसान को लाभ मिलेगा । अति पिछड़ा, पिछड़ा में मैं आपको बता देना चाहता हूँ । अति पिछड़ा का सब प्रयोग करता है, पिछड़ा का सब प्रयोग करता है । अति पिछड़ा, पिछड़ा की सरकार अब बनती रहेगी इसमें दो मत नहीं है, सबने अपना कोरम पूरा कर दिया है । अति पिछड़ा का सबमें प्रयोग जितना रैली होता है सबमें अति पिछड़ा को बुलाया जाता है । जब भगवान रामचन्द्र जी की पत्नी सीता मैय्या खो गयी थी तो जानकारी रहते हुए उन्होंने पता लगाने के लिए किसका सहारा लिया पिछड़ा का सहारा लिया, हम शुद्रों का सहारा लिया, अति पिछड़ा के लोग बानर, भालू जितना जंगली जानवर था सबने ये किया और सीता मैय्या को ढूढ़ निकाला । अति पिछड़ा का योगदान है इसमें दो मत नहीं है । जहां तक सवाल है माननीय सभापति महोदय, विकास में उद्योग क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण होता है और बिहार उद्योग क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा हुआ है । इस ऐतिहासिक पिछड़ापन को पलटने के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं जिनमें अनेक नीतिगत उपाय शामिल हैं और कई समर्पित संस्थाएं स्थापित की गयी है । सीमित संसाधनों के बीच अनौपचारिक उद्योगों की बढ़ती संख्या में राज्य में पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन में उत्साहवर्द्धक प्रगति दिखाया है । इस दिशा में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 तथा उद्योग विभाग द्वारा विशेष भूमि आवंटन एवं नियुक्ति नीति, 2020 प्रमुख सुधार है । बिहार में बहुत बड़ी उपभोक्ता आबादी उर्वरक भूमि, प्रचुर पानी विविध क्षेत्र के बावजूद उद्यम क्षेत्र में कार्य की प्रगति होना बाकी है जिसके लिए बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के सफल नेतृत्व में गंभीर प्रयास कर रही है । बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार प्रसंस्करण उद्योगों के मामले में प्रमुख राज्य बन गया है ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : अब समाप्त कर देते हैं । उद्योग में छोवा के फार्मेन्टेशन से इथेनॉल का उत्पादन होता है ।

टर्न–22/ज्योति/05–03–2021

क्रमशः

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : सरकार इथेनॉल के उत्पादन के लिए गंभीर प्रयास कर रही है । इथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से जैविक धन के रुप में जीवाश्म धन में मिलाकर जीवाश्म ईंधन की खपत कम की जा सकती है । इससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को कई तरह से मदद मिल सकती है । सभापति महोदय, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बिहार राज्य दुग्ध उत्पादक महा संघ लि0 कम्फेड के सदस्यों की संख्या 12 लाख से अधिक हो गयी है । सरकार ने कई दुग्धशाला संयंत्र एवं पशु आहार संयंत्र लगाए हैं । सेवा प्रदाता के रुप में कम्फेड के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है । सभापति महोदय, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंर्तगत दिसम्बर, 2020 तक राज्य सरकार को लगभग...

सभापति(श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : बैठते हैं सभापति महोदय, मुख्य सचेतक जी हमारे लिए भी समय दिलवाईये न । ललित बाबू दिलवाते हैं उधर । निवेश के लिए दो हजार तीन निवेशक प्राप्त हुए हैं जिसमें दो सौ बासठ इकाईयों ने काम करना शुरु भी कर दिया है । पर्यटन को उद्यम में शामिल किए जाने के बाद बिहार में पर्यटन को इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । जैन परिपथ, बौद्ध परिपथ, रामायण परिपथ, शिव शक्ति परिपथ की विकास योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हुआ है ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, माले का जितना समय है उसमें से माननीय सदस्य को समय दे दिया जाय ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : सभापति महोदय, गांधी परिपथ का निर्माण किया जा रहा है । साढ़े तीन हेक्टेयर के जंगल में, काराकाट रोहतास में दुर्घटना में और रानीगंज अररिया में अभूतपूर्व प्रयास किया गया है जो पर्यटन को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं । बिहार में लगभग 20 प्रतिशत अनगिनत उद्यम वस्त्रों के परिधानों का निर्माण हो रहा है।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): नरेन्द्र कुमार नीरज जी अपना आसन ग्रहण करें, आपका समय समाप्त हुआ । श्री आलोक कुमार मेहता ।

श्री आलोक कुमार मेहता : सभापति महोदय, उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, उद्योग का मतलब उत्पादन से है । उद्योग का संबंध सीधा पहले उत्पादन से है और उत्पादन का

संबंध रॉ मैटेरियल्स से है, लेबर से है और उसके विपणन से है । यह व्यवस्था उद्योग के अंदर आती है लेकिन उद्योग में उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है । जबतक उद्योग नहीं लगेंगे, उत्पादन नहीं होगा तबतक इंडस्ट्रीलाईजेशन उसका नहीं माना जायेगा । यहॉ पर कंसेप्ट उसका बिल्कुल उल्टा है । हमारे सत्ता पक्ष की तरफ से यह बयान दिया गया कि देखिये कितने बाजार बढ़ गए, कितनी दुकानें खुल गयीं और राज्य का औद्योगिक अभिकरण हो गया । पिछले वर्षों में उद्योग की परिभाषा बदली हुई है। यदि टोयटा का शोरुम खुल गया, होण्डा का शोरुम खुल गया तो औद्योगीकरण उसका माना जा रहा है जबकि मैं बताता हूँ कि उद्योग इसलिए लगाना जरुरी है चूंकि उत्पादन यहॉ से हो और उसकी मार्केट पूरे देश और दुनिया में हो तो बाहर का पैसा बिहार के अंदर आयेगा और तब बिहार समृद्ध होगा औद्योगीकरण के माध्यम से । यदि टोयटा का शोरुम यहॉ लग रहा है और टोयटा यहॉ के लोग खरीद रहे हें तो टोयटा का उत्पादन कहॉ होता है महोदय, टोयटा का उत्पादन बिहार से बाहर होता है तो उस तरह के जितने भी शोरुम खुल रहे हैं, दुकान खुल रही है, बाजार बढ़ रहा है चमक- दमक वाले बाजार बनाये जा रहे हैं तो यह सब के सब विपणन और बाजार के लिए है और यह सब ट्रेडिंग होता है और ट्रेडिंग इकोनॉमी को कमजोर करता है क्योंकि आपके पास उत्पादन नहीं है क्योंकि सारा पैसा आपके यहॉ एक तो मनीऑर्डर इकोनॉमी है यहां के लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं वहॉ से पैसा भेज रहे हैं उनके यहॉ पर रहने वाले लोग बाहर का सामान खरीद खरीद कर बिहार की बदहाल स्थिति तक पहुंचाने का काम किए हैं । 15 वर्षों का नाम लिया गया, आप 15 वर्षों का नाम क्यों लेते हैं ? आप 16 वर्ष इसमें और जोड़ दीजिये । बिहार की औद्योगिक नीति जब बनी थी 2017 में उस समय हमलोग भी सरकार में थे । माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उस समय उप मुख्यमंत्री थे और औद्योगिक नीति बनी लेकिन उसके बाद जब आप लोगों का शासन कंटीन्प्यू किया जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू का शासन रहा, पहले भी रहा, बाद में भी रहा तो जनता रिजल्ट देखना चाहती है। आपने इन 16 वर्षों में कितनी नीतियॉ बनायी कितने सारे कानून बनाये लेकिन अंतिम रिजल्ट क्या हुआ और जब रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि 15 वर्षों में क्या हुआ । महोदय, 15 वर्ष से 15 वर्ष बोल कर अपनी कमियों और गलतियों को ढकने का काम करना बंद कीजिये । जनता इन सभी बातों पर आप अभी क्या कर रहे हैं देश से राज्य तक ईस्ट इंडिया कंपनियों को इनवाईट कर रहे हैं कि कल होकर आपका स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी ले लें यानी कि वैसे ही पूंजीपतियों के हाथ में पूरा गवर्ननेंस आ जाय और आप उसके आगे जनहित में कुछ न

कर सके वैसे ही स्टेप केन्द्र से लेकर यहॉ तक कि जो औद्योगिक नीतियां बन रही है और जो डिसइनवेस्टमेंट पॉलिसी बनी है और मैं देख रहा हूँ कि जब से केन्द्र में सरकार आयी भारतीय जनता पार्टी की उसी समय से डिसइन्वेस्टमेंट का सिलसिला शुरु हुआ । नाल्को बिक गया, बाल्को बिक गया पॉच-पॉच हजार करोड़ के प्रॉफिट में चलती हुई इंडस्ट्री को बेच दिया गया और आज रेलवे, एयरपोर्ट और एयर इंडिया सब बिकने के कगार पर है । एल.आई.सी. का भी डिसइंन्वेस्टमेंट हो रहा है । क्या मतलब है सुरक्षा का। जन सुरक्षा का, सोशल सिक्यूरिटी का क्या मतलब क्या रह गया ? जब वेल्फेयर स्टेट में लाइफ इंसोरेंश जैसी कंपनी जो सरकार के द्वारा संरक्षित थी, जो आम जनता के बुरे दिन में काम आने वाली कंपनी थी कल तक और जब उसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा, यह सिलसिला जारी रहा तो शायद किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा की गारन्टी सरकार से फायनेन्शियल सिक्यूरिटी की गारन्टी नहीं मिल पायेगी इसलिए बिहार जो है सिल्क का उत्पादन करता है, बिहार कॉटन का उत्पादन करता है, मधु का उत्पादन करता है, अन्न में गेहूँ, मक्का और धान का उत्पादन करता है । ये सारे रॉ मैटेरियल्स है । इंडस्ट्री लगाने की जरुरत है, सरकार को सिंग्ल विन्डो सिस्टम को इनेबुल करने के लिए इज ऑफ डुईंग बिजिनेस की पॉलिसी को लागू करना होगा और इसको लागू करने का तरीका है कि हर क्षेत्र में एक एक इंडस्ट्री सरकार पब्लिक सेक्टर में लगावे ताकि उसको यह महसूस हो कि इस इंडस्ट्री को लगाने में क्या क्या परेशानियां आती है।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, आपका एक मिनट बचा है ।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, इंसपेक्टर राज को खत्म करने की घोषणा मात्र इंसपेक्टर राज को यह सरकार खत्म नहीं कर सकी । आपका सिंग्ल विन्डो सिस्टम, मल्टी विन्डो सिस्टम में काम कर रहा है और वह काम ही नहीं कर रहा है । वह हर जगह रोड ब्लॉक पैदा कर रहा है इसलिए माननीय मंत्री जी बहुत अनुभवी मंत्री हैं और हमें अपेक्षा है कि इन्होंने केन्द्र में काम किया है लेकिन दुख: इस बात का है कि इन्होंने उसी सरकार में काम किया है जिस सरकार ने अशोका होटल का डिसइन्वेस्टमेंट किया था और वह औने पौने दाम पर दे दिया गया । मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस बिहार को बचा कर रखिये, यह आपकी जन्मभूमि है और यहॉं की जो व्यवस्था है वह समाजवादियों की व्यवस्था रही है । जन नायक कर्पूरी ठाकुर के जो वैल्यू सिस्टम थे उन्हीं का यहॉ की मिट्टी में सुगंध है इसलिए पूरी सरकार से अनुरोध है कि जो औद्योगिक व्यवस्था है उसकी इंडिजिनियटी को जो यहॉ का संसाधन है, उसका उपयोग करके इंडिजिनियटी को बनाए रखने की जरुरत है । यहॉ के छोटे छोटे उद्योग जो कुटीर उद्योग हैं उसकी तरफ

भी पर्याप्त ध्यान देकर उनको बढ़ाने की जरुरत है । तब ही बिहार की औद्योगिक उत्पादकता और बिहार के संसाधनों की उत्पादकता बढ़ने की संभावना है । इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि समस्तीपुर में भी इंडस्ट्रीयलाईजेशन का भी बहुत स्कोप है उसपर भी ध्यान दिया जाय ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह जी आपका 1 मिनट समय है ।

टर्न-23/अभिनीत-पुलकित/05.03.2021

श्री राज कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस अवसर का प्रयोग भाई शाहनवाज जी को बधाई देने के लिए करना चाहता हूँ कि उनके युवा विजनरी और प्रगतिशील नेतृत्व में बिहार का औद्योगिक विकास होगा, ऐसी उम्मीद हम सब लोग करते हैं । राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने विभिन्न विभागों में कार्य कर अनुभव प्रप्त किया है और निश्चित रूप से हमारे जो इस सूबे के मुखिया हैं उनके प्रगतिशील विचारधारा का यह एक एक्सटेंशन है कि उन्होंने भाई शाहनवाज जी को उद्योग मंत्रालय का भार सौंपा है । औद्योगिक विकास ही बिहार के संपूर्ण विकास का और युवाओं के लिए रोजगार का एक आधार बन सकता है, ऐसी मेरी सोच है और हमारे सदन में बैठे हमारे तमाम साथियों की ऐसी ही सोच है । मैं बेगूसराय के मटिहानी विधान सभा से आता हूँ । बेगूसराय औद्योगिक रूप से यूं तो कुछ विकसित जरूर है लेकिन जिस तरह का विकास यहां होना चाहिये वह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है । मटिहानी लीची उत्पादन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है अगर वहां लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगायी जाय तो वहां के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है ।

अब मैं पर्यटन के क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । बेगूसराय का सिमरिया धाम पर्यटन का 'हरि की पौड़ी' के स्तर पर एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है यदि उसी की तर्ज पर उसका विकास किया जाय । जयमंगला गढ़ हो, कावर झील हो...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): कृपया आप अब स्थान ग्रहण करें । आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राज कुमार सिंह: महोदय, और भी जो अन्य पर्यटन स्थल हैं उनको भी औद्योगिक दर्जा देते हुए उनका विकास किया जाय तो बिहार के विकास की एक नई गाथा माननीय शाहनवाज जी जरूर लिख सकते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, पवन कुमार यादव ।

श्री पवन कुमार यादवः माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी एवं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे पूरे बिहार में सबसे अधिक मतों से जीताकर लोकतंत्र के मंदिर में आज आपके समक्ष सदन में उद्योग से संबंधित मामलों पर अपने विचार रखने का मौका दिया । सदन में बोलने के लिए अपार अवसर प्रदान करने हेतु मैं माननीय अध्यक्ष एवं उप मुख्य सचेतक माननीय महोदय का भी आभार प्रकट करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में खड़ा हूं और सरकार के बजट प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

बिहार स्टार्टअप नीति, 2017 - राज्य सरकार द्वारा राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए बिहार स्टार्टअप नीति, 2017 लागू किया गया है । इसके लिए बिहार सरकार द्वारा प्रारंभिक कॉरपस फंड के रूप में पांच सौ करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है ।

मुख्यमंत्री सूक्षम एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना- मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत कुल 8 कलस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार डी0पी0आर0 पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है । जिसके अन्तर्गत अबतक 7 कलस्टरों, राईस मिल कलस्टर- लखीसराय, मेनमेहसी सीप बटन कलस्टर- पूर्वी चम्पारण, बंथना सीप बटन कलस्टर- पूर्वी चम्पारण, सिलाव खाजा कलस्टर- नालन्दा, कन्हैयागंज झूला कलस्टर- नालन्दा, कांसा-पीतल कलस्टर- वैशाली, कांसा-पीतल कलस्टर- पश्चिमी चम्पारण । टेक्सटाइल अपैरल पार्क की स्थापना- टेक्सटाइल अपैरल पार्क की स्थापना बिहटा-पटना ।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के भौतिक लक्ष्य 2822 एवं वित्तीय लक्ष्य 8466 लाख के विरूद्ध अब तक 11829 आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति हेतु बैंक शाखाओं में भेजे गये हैं । बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या 1161 है । बैंक द्वारा अब 696 आवेदकों के बीच 2320 लाख मार्जिन मनी अनुदान के रूप में भुगतान किया गया है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

हस्तकरघा के प्रक्षेत्र के साथ ही साथ रेशम प्रक्षेत्र में तसर विकास परियोजना अन्तर्गत बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, कैमूर, रोहतास एवं बेतिया जिलों में 3416 हेक्टेयर निजी भूमि में एवं 6120 हेक्टेयर वन भूमि रेशम फार्म में तसर वृक्षारोपण कराया गया है । बांका, मुंगेर एवं जमुई जिलों में 1147 तसर कीटपालकों को कीटपालन सामग्री उपलब्ध करायी गयी है । जमुई जिले के अनुसूचित जाति के लोगों को तसर उद्योग के

माध्यम से सशक्तिकरण के लिए 98.7 लाख स्वीकृत किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में निवेश क्यों करें ? बिहार में बहुत बड़ा घरेलू बाजार है । बिहार पूर्वी राज्यों का द्वार है, यह बंगाल, यू0पी0, झारखंड, उड़ीसा को जोड़ता है । बिहार के माध्यम से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को निर्यात किया जा सकता है । बिहार में रेल रोड, एयर ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा उपलब्ध है । बिहार में सर्विस सेक्टर में भी निवेश के अच्छे अवसर अपलब्ध हैं जिसमें मुख्य रूप से हेल्थकेयर, तकनीकी संस्थान, आई.टी/आईटीज सेक्टर शामिल हैं । बिहार में उद्योगों को 22-24 घंटे ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली उपलब्ध करायी जा रही है । सभी औद्योगिक क्षेत्रों को पावर लाईन उपलब्ध कराया जा रहा है । विश्व प्रसिद्ध कंपनियां एम0एन0सी0जी0ई0 रेल इंजन बना रही है । बिहार में कोक, पेप्सी, आई0टी0सी0 ब्रिटानियां जैसी बड़ी कम्पनियां उत्पादन कार्य कर रही हैं । बिहार में डालमिया, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक जैसी बड़ी सीमेंट कम्पनियां उत्पादन कर रही हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में 'ईज ऑफ डूइंग' बिजनेस में भारत ने तेजी से प्रगति करते हुए 82 स्कोर किया है । कम अवधि में बिहार में निर्यात 900 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2 बिलियन डॉलर होने जा रहा है । एगजीम रैंक की रिपोर्ट में भी ऐसा दर्शाया गया है कि बिहार का मक्का के उत्पादन में देश में दूसरा, हनी में चौथा, सब्जी में सातवां, फल और डेयरी उत्पादन में आठवां स्थान है । फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में जापानी औद्योगिक एरिया का भी निर्माण होना है । इसमें निवेश करने का अच्छा अवसर है ।

अध्यक्ष महोदय, कहलगांव और आसपास के क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों की असीम संभावनाएं हैं । आम, हरी मिर्च, मक्का, केला, गन्ना तथा दलहन का बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में उत्पादन होता है । फूड पार्क बनने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे । गन्ना से इथनॉल, मक्का से कॉर्नफ्लैक सहित कई कृषि आधारित उद्योगों की संभावना है । कहलगांव एन.टी.पी.सी. से निकलने वाले फ्लॉयस से सीमेंट बनाने का कारखाना लगाया जाय, इससे भी रोजगार के अवसर बहुत से होंगे । सरकार बियाडा के लिए अधिगृहित जमीन पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उद्योग लगाने का कार्य प्रशस्त करे । वर्षों से बियाडा की 1100 एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। पीरपैंती के समीप पावर प्लांट के लिए अधिगृहित जमीन पर शीघ्र थर्मल पावर प्लांट लगाया जाय । बेरोजगारी की समस्या दूर करने में यह मील का पत्थर साबित होगा । केंद्र सरकार द्वारा विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए पांच सौ करोड़ रूपये दिये जाने की घोषणा के बावजूद अब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया हो । जमीन उपलब्ध

कराकर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाय । कहलगांव के गंगा नदी के बीच स्थित तीन पहाड़ियों को रोप-वे से जोड़ा जाय । बटेश्वर और विक्रमशिला में पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधा मुहैया कराया जाय । वर्षों से सूखी पड़ी गंगा पम्प नहर परियोजना के नहर में सालों भर पानी की व्यवस्था कर सालों भर सिंचाई की व्यवस्था की जाय ताकि किसानों के हालात बेहतर हों ।

मैं कहना चाहूंगा सदन से कि हमारी कई एक हजार बूढ़ी माताएं और बूढ़ी दादियां वर्षों से, आज 50 वर्षों के दरम्यान में आज हजारों-करोड़ रूपये खर्च हो गये हैं लेकिन आज भी उस नहर में एक बूंद पानी नहीं है । हमारे बूढ़े गार्जियन किसान बैठे हुए हैं और आत्मदाह कर रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 2 साल पहले उसका उद्घाटन करके आये हैं और आज एक भी बूंद उसमें पानी नहीं है । मैं सदन से कहना चाहता हूं अगर....

अध्यक्ष: अब बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार यादव: सुन लीजिये तब बोलियेगा, पहले मेरी सुन लीजिये, रूकिये अभी हम बोल लेते हैं तब आप लोग कहियेगा । महोदय, उस नहर को अविलंब चालू कराया जाय । माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि किसानों को सबसे अधिक लाभ होना चाहिए तो एक हजार करोड़ रूपया उसमें खर्च हुआ है और 50 साल से नहर बन रही है अगर किसी को कहलगांव की धरती पर, आप लोगों ने काला हाथी देखने का काम किया लेकिन मैंने अपनी उम्र में उजला हाथी देखने का काम किया है । अगर किसी को उजला हाथी देखने का मन होगा तो कहलगांव की धरती पर आइये मैं आपको उजला हाथी दिखाने का काम करूंगा । अगर आज वह नहर बनकर तैयार हो जाती है और बूढ़े किसान गार्जियन के खेतों में पानी जाता है तो उजला हाथी, काला हाथी का रूप धारण कर लेगा अन्यथा उस उजला हाथी के लिए, हर साल उसकी खुराक है कम-से-कम 10-20 करोड़ रूपया खर्च होते हैं लेकिन वह उजला हाथी, उजला हाथी ही रह गया । हम चाहते हैं कि वह काला हाथी हो और किसान के खेत में पानी देने का काम करे ।

अध्यक्ष: अब बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार यादव: महोदय, हमें दो मिनट का समय दीजिये हम ऐसी बात रखने जा रहे हैं जो पूरे सदन के लिए बिहार के लिए अच्छा रहेगा । दो मिनट का समय दिया जाय अगर समय नहीं है तो मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से कहूंगा कि हमको पांच मिनट का समय और दिया जाय, पूरे सदन के लोगों के लिए मैं इन बातों को रखना चाह रहा हूं ।

अध्यक्ष: आप एक मिनट के अंदर अपनी बात को रखकर बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार यादव: महोदय, बिहार में एक मात्र कोयला ब्लॉक है कहलगांव जो पीरपैंती, मेहरमा तक में फैला हुआ है । इसका नाम लुधिया कोलब्लॉक है जिसे जल्द से जल्द चालू कराया जाय, यहां बहुत अधिक मात्रा में कोयला है, 1300 मिलियन टन कोयला । प्रतिवर्ष अगर 15 मिलियन टन कोयला निकाला जायेगा तो 30 साल तक ये कोलवरी कायम रहेगी । साथ ही साथ इससे बिहार के राजस्व में भारी वृद्धि होगी और बिहार आत्मनिर्भर होगा । इसके साथ ही पीरपैंती में अधिगृहीत की गई जमीन बिहार सरकार के उपक्रम द्वारा निर्माण हो जिससे उत्पादित बिजली लगातार काम आयेगी । बगल में कोयला ब्लॉक होने के कारण इससे भी काफी लोगों को रोजगार मुहैया होगा ।

अध्यक्ष: श्री पवन कुमार जी बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय ....

टर्न-24/हेमन्त-धिरेन्द्र/05.03.2021

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये । फिर आगे मौका मिलेगा, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अब, बैठ जाइये । माननीय सदस्यगण, सोमवार, दिनांक-08 मार्च, 2021 को 10 बजे पूर्वाह्न में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मेरे कार्यालय कक्ष में होगी ।

माननीय सदस्यगण, आज हम लोग इस द्वितीय सत्र के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन में पहुंच गये हैं । इस पूरी अवधि में सदन में आपकी भागीदारी और लोक महत्व के मुद्दों पर आपकी संवेदनशीलता सराहनीय रही है परन्तु एक बात जो मैंने महसूस की है कि प्रतिदिन शून्यकाल के बाद ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान आपकी उपस्थिति प्राय: कम हो जाती है जबकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य निपटाये जाते हैं । ध्यानाकर्षण की सूचनाएं तो राज्यस्तरीय समस्याओं की रहती ही हैं, इसके अलावा सदन पटल पर नियमावली, प्रतिवेदन एवं अन्य कई कागजात रखे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं । इसके संबंध में आज दिनांक-05.03.2021 को अल्पसूचित प्रश्न संख्या-34 के उत्तर के दौरान यह देखने को मिला कि नियम में सामूहिक शब्द है, किसी व्यक्ति विशेष की दुर्घटना का संज्ञान नहीं लेती है । इसलिए सदन में जब नियमवाली पटल पर रखी जाती हैं, तो उन्हें ध्यान से देखें । इन सूचनाओं से अवगत होने एवं अधिक-से-अधिक सदन की कार्यवाही में आपकी भागीदारी होने से इस सर्वोच्च संस्था की गुणवत्ता बढ़ेगी और प्रजातंत्र के मंदिर का सम्मान बढ़ेगा साथ ही विधान सभा में विधान बनाये जाते हैं और इसी विधान

को बनाने के लिए जनता हमें चुनकर भेजती है । इस कार्य के लिए अगर हम लोग चार घंटे तक सदन में उपस्थित नहीं रह पायेंगे, तो जनता के बीच क्या संदेश जायेगा ? यह हम लोगों को विचारना चाहिए । इसलिए अति आवश्यक कार्य होने पर भी सदन के कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए । आसन आपसे सकारात्मक पहल की अपेक्षा करता है।

अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय उपमुख्यमंत्री-सह-मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, कृपया अपना पक्ष रखें ।

श्रीमती रेणु देवी, उपमुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी है । मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज मुझे पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण का जो वक्तव्य देने का मौका मिला, उन्होंने मुझे उप मुख्यमंत्री बनाकर प्रस्तुत किया । हमारी पार्टी, जो हमारे पिछड़ा और अति पिछड़े के लोग हैं, उनके संबंध में वह कितना सोचती है । महोदय, हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है तथा इन वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सतत प्रयत्नशील हैं । राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 से, दिनांक- 01.04.2007 से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा प्रदान किया गया । वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभाग का वार्षिक योजना बजट 4217.40 लाख रुपये (बयालीस करोड़ सत्रह लाख चालीस हजार) मात्र से प्रारंभ किया गया है । पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं । वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम मद में 167790 लाख रुपये (सोलह अरब सतत्तर करोड़ नब्बे लाख) मात्र, केंद्र प्रायोजित स्कीम मद में केंद्रांश के तहत 13563 लाख रुपये (एक अरब पैंतीस करोड़ तिरसठ लाख) मात्र, राज्यांश के तहत 1500 लाख रुपये (पन्द्रह करोड़) मात्र तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 2090.72 (बीस करोड़ नब्बे लाख बहत्तर हजार) मात्र का बजट उपबन्ध प्रस्तावित है । मैं कहना चाहती हूं कि इन उपलब्धियों में हमारी जो वर्ष 2020-21 की उपलब्धियाँ हैं, उसमें हमने अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वितरण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा

रही है और इस वर्ग में वर्ष 2019-20 में लाभुकों की संख्या 63,43,511 थी । इसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग में प्रवेशिकोत्तर छात्र की संख्या 2,47,162 हुई । इसी तरह मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति छात्र के लिए वितरण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में लाभुकों की संख्या 85,488 रही । इसी तरह पिछड़ा वर्ग मेधावी छात्र के वितरण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में लाभुकों की संख्या 51,873 रही । प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र योजना, वर्तमान में 34 जिलों में 34 केन्द्र स्थापित कर नामांकन की कार्रवाई की जा रही है । जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना में 29 जिलों मे छात्रावास भवन निर्मित हैं, जिनमें से 26 जिलों में संचालित है और 2 जिलों में निर्माणाधीन है । अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, जो कि बेटियों के लिये है और बेटियां जो हमारी पढ़ती हैं छठी से लेकर बारहवीं तक, उसमें 12 जिलों में 14 छात्रवास हमारे संचालित हैं । अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू के लिये 11 जिलों में 12 संचालित हैं । मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा, जो कभी सोच नहीं सकता था कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का बच्चा कि सिविल सेवा के लिये भी कोई हमारा उद्धार करेगा, हमारी सरकार पहले तो उन्हें 50 हजार रुपया और एक लाख रुपया सिविल सर्विस के लिए भी प्रोत्साहित योजना में दे रही है । इसी तरह, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना में औसत लगभग 3000 छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है । छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति के लिये औसतन लगभग 3000 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है, इसमें 15 किलो अनाज (9 किलो चावल एवं 6 किलो गेहूँ) और एक हजार रुपया दिया जाता है । छात्रावास के भीतर मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं.....

अध्यक्ष : संक्षिप्त कीजिये ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास के लिये अब तक कुल लाभुक हमारे 3636 हैं और इसी तरह 13वीं योजना है परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये, हम 25 लाख रुपया उन्हें छात्रवृति में देते हैं । अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ा जो है, हमारे सभी तरह के बच्चों की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उन्हें अनुदान देने की आवश्यकता हमलोग महसूस करते हैं, हमारे यहां बच्चों को, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा अगर वह चाहते हैं कि ई-रिक्शा हमें चाहिये, उन्हें अनुदान पर हम ई-रिक्शा भी उपलब्ध कराते हैं । इस तरह से बच्चों का विकास और पिछड़ा, अति-पिछड़ा के लिए हमेशा बिहार सरकार चिंतित है और आगे भी चिंतित हो रही है और भी हम क्या कर सकते हैं।

आगे भी करते रहेंगे । इसीलिए, मैं सब माननीय सदस्यों को कहूँगी कि आग्रह है मेरा अपना इस विभाग का भी और सभी विभागों का कटौती प्रस्ताव न काटे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

टर्न–25/सुरज–संगीता/05.03.2021

सरकार का उत्तर

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर और ये विषय रखने का अवसर दिया है । वैसे तो इस सदन में पहली बार प्रश्नकाल में तो मैं बोला हूं लेकिन ये मेरी तरफ से मेडेन स्पीच है जो मेरे विभाग के अनुदान के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय, काम कठिन है । इस विभाग का नाम उद्योग विभाग है लेकिन ये बिहार के 14 करोड़ लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ विभाग है । इस विभाग से अपेक्षाएं बहुत हैं । मैं अपनी पार्टी के नेताओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि मुझे एक महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है । पहले तो विभाग, जब कोई भी विभाग होता है उसके बारे में उसके बजट से, उसके आकार से उसके बारे में राय बनाई जाती है लेकिन मेरा सौभाग्य है कि जो विभाग मुझे दिया गया है इस पर बिहार के 9 मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्रालय का विभाग उन्होंने खुद संभाला है । उद्योग, जिस बारे में चर्चा होती थी, बिहार उद्योग की वजह से जाना जाता था और बिहार जो सोने की चिड़ियां कहलाता था तब भी 493 ई0पू0 में मगध साम्राज्य में ताकत की बुनियाद जो हमारी थी व्यापार और कारोबार पर टिकी थी । उस जमाने में भी आजादी से पहले मैं यह कह सकता हूं कि गुप्त साम्राज्य के दौरान भी, भारत को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, यही वजह थी कि पाटलिपुत्रा फलता–फूलता व्यापार था और कारोबार था । आप जानते हैं कि एक जमाना था जब मलेशिया में कहा जाता था कि हमारी सड़कें चेन्नई जैसी होंगी, आदर्श चेन्नई था और एक जमाना था जब जापान में भी आदर्श दिया जाता था कि हाजीपुर का जो बटन है, 1931 में लाहौर तक जाता था और पूरी दुनिया में जाता था, उसको देखकर कई देशों ने उसको आदर्श माना था । मैंने जब ये बातें आपको कही है क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे सब बातें बहुत जिम्मेदारी से कहनी है और मुझे बहुत कसौटी पर कसा जायेगा, मेरे से उम्मीद बहुत लगायी जायेगी और यह जो उद्योग विभाग है न मुझे मालूम था कि मुझे बिहार आना है, कई सदस्यों ने कहा कि मैं बिहार आ गया हूं, मैंने कहा मैं बिहार से बाहर कब गया था । हमारे कई मित्र हैं जो हमारे साथ सांसद रहे हैं आलोक जी संसद में रहे हैं, साहनी जी संसद में रहे हैं और

कई बहुत वरिष्ठ लोग हैं जिनका बचपन में मैं दूबे जी का और अपने विजय चौधरी जी का नाम सुना करता था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो ऐसा नहीं है कि काम बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा-छोटा नहीं होता है । हमें तो मेरे नेता अटल बिहारी बाजपेयी जी ने 32 साल की उम्र में भारत का सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, 6 विभाग का मंत्री का काम मिला और मैंने जब भी मंत्री के तौर पर काम किया तो मैंने यह मानकर काम किया कि मेरे सामने पार्टी का झंडा नहीं बल्कि भारत का तिरंगा रखा है । जो भी दल के विधायक आयेंगे या सांसद आयेंगे वे इस बात के गवाह हैं कि मेरे यहां मैं दलीय सीमा को मंत्री पद पर बैठने के बाद उस नजरिये से नहीं, हमारे नेता अटल बिहारी बाजपेयी जी और हमारे नेता नरेन्द्र मोदी जी, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास तो मैं मानता हूं, सबका साथ चाहिये, सबका सहयोग चाहिये तभी उद्योग चाहिए । अगर इसमें मैं सोचूंगा कि मैं आपको कोई डिस्क्रेडिट करूं, बहुत से सदस्यों ने जो बोला है उस पर मैं आऊंगा लेकिन मुझे यह सौभाग्य है कि श्री बाबू ने जिस औद्योगिक राज्य की स्थापना की थी और उसके बाद जो इन्फ्रास्ट्रक्चर में कमियां आईं उन कमियों को हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर में इतना अच्छा काम किया ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले चुनाव में मैं कोविड से पीड़ित हो गया था । माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहां प्रचार में गया था । उसके बाद से एक महीना पूरा चुनाव जो है, वह मैंने एम्स के एक रूम से देखा और वहीं से मैं चुनाव को देख रहा था क्योंकि जो पोलिटिकल व्यक्ति होता है, वह कहीं भी होगा तो उस पर बारीक नजर रखेगा और इसीलिए उस वक्त चुनाव में मैं देख रहा था कि मुद्दा क्या था ? चुनाव में मुद्दा रोजगार था, चुनाव में मुद्दा उद्योग था । हमारे जो आज विपक्षी दल के बेंच पर बैठे हुए साथी हैं, इनके भाषण को भी मैं वहां पर सुनने का काम करता था । मेरे पास सुनने के अलावा और दवा खाने के अलावा और कोई काम नहीं था तो मैं सबका भाषण बहुत ध्यान से सुनता था, मैं सबका नॉमिनेशन देखता था । हसनपुर में तेजप्रताप जी का नॉमिनेशन भी देखा था मैंने, वहां उनका वादा भी देखा था मैंने, वहां की भी चीनी मिल के बारे में जिक्र भी सुना था तो मैंने सबको सुना था और सबको सुनते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के नेतृत्व का कि मुझे अपनी जन्मभूमि की सेवा का अवसर दिया है और जिस सदन में इतने बड़े-बड़े लोग हों, जो मेरे स्कूल के वक्त के विधायक, आज मंत्री हैं और दुबे जी और चौधरी जी को, बिजेन्द्र भाई तो हमलोगों के साथ हैं । जब मैं सुपौल में पढ़ता था तो इनके जुलूस में जाकर कैसी फूल-माला होती है, वह पहली बार देखा था । तो मैं आज कह सकता हूं कि श्री बाबू ने जो शुरू किया, उसके

बाद मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी, डॉ0 जगन्नाथ मिश्रा जी, रामसुन्दर दास जी, बिंदेश्वरी दुबे जी, भगवत झा आजाद जी, सत्येन्द्र नारायण सिन्हा जी, लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी सबके पास उद्योग विभाग रहा है तो इतने महान जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहे, उनके पास उद्योग विभाग रहा । हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास भी यह विभाग रहा और हमारी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी के पास से यह विभाग मेरे पास चलकर आया है तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि बिहार में पिछले चुनाव में कोई रोड, बिजली, पानी यह मुद्दा मैंने कहीं पर, किसी विपक्षी दल के नेता के भी मुख से ये बातें नहीं सुनी क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे ज्यादा ध्यान से भाषण ही सुनता रहा । जो लोग भाषण देते हैं, दिया होगा जिन्होंने, उन्होंने जितना अपना भाषण नहीं सुना होगा, मेरे पास यही....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, आपने नहीं सुना?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अच्छा है कि माननीय विपक्ष के नेता इनसे भी मेरी पहली...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हर जगह सभा में हमलोगों ने बोला है ।

अध्यक्ष : अब आप सुन लीजिए, सुन लीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : यह तो मेन एजेंडा है, हम याद दिला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं बोले ।

अध्यक्ष : याद दिलाए तो अब सुनिएगा न । अब सुन लीजिए ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे सौभाग्य है कि जब मैं पहली बार वर्ष 1999 में जीता था तो मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के आवास पर गया था और तेजस्वी जी से वहीं मुलाकात मेरी हुई थी । रिश्ता बहुत पुराना है और इसलिए मैंने जब कहा कि मैंने आपका भाषण श्रोता के तौर पर सुना तो उसमें बहुत विस्तार से जाऊंगा तो समय काफी कम बचेगा और मुझे विषय पर आना है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड, बिजली, पानी, सड़क में इतना काम किया है कि किसी राजधानी में कहीं भी आप 5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं और सरकार उसमें निरंतर बहुत अच्छा काम कर रही है । जहां सबसे ज्यादा अपेक्षा है, वह अपेक्षा उद्योग और रोजगार से है । जहां तक पढ़ाई का कहा विजय चौधरी जी ने, बेहतरीन भाषण दिया है उसको हम सबने सुना है । उसपर बेहतरीन काम वह कर रहे हैं । दवाई पर हमारे मित्र मंगल पाण्डेय जी ने पूरा विस्तार से उस पर कई बार आपको जवाब दिया है तो पढ़ाई, दवाई, लिखाई और उद्योग और रोजगार । तो उद्योग और रोजगार एक बड़ा विषय है बिहार के लिए और उद्योग और रोजगार के विषय को मैं आज शेरो-शायरी से अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत

शेरो-शायरी करता हूं लेकिन आज मैंने सोचा, मेरे से श्रवण जी पूछ रहे थे कि आज कुछ शायरी पढ़ेंगे, मैंने कहा नहीं यह बड़ी जिम्मेदारी वाला विभाग है । उतना ही बोलना, जितना ही चलना, जितने में हम उसको करके दिखा सकें तो अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने और जिन सदस्यों ने इस पर चर्चा की है उनके बारे में मैं एक-एक पंक्ति में उसका जवाब जरूर दूंगा लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार सरकार उद्योग के प्रति बहुत गंभीर है । मैं यह नहीं कहता कि मैं पूरी तस्वीर को एकदम बदल दूंगा और ज्यादा बढ़कर दावा करूं ।

...क्रमशः...

टर्न-26/ मुकुल-राहुल/05.03.2021

क्रमशः

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: क्योंकि मैं एक अनुभव वाला व्यक्ति हूं वही सदन में कहा जाए जो किया जा सकता है और बहुत से उद्योग हैं जो बंद हैं जिसका जिक्र सारे सदस्यों ने किया है, करीब यहां पर 16 सदस्य बोले हैं और उन्होंने जो जिक्र किया है, मैं आप सबकी बात से अपने को संबद्ध करता हूं । आपकी जो फिक्र है वह सही है लेकिन

(व्यवधान)

अध्यक्ष: शांति बनाए रखें ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अगर मैं विस्तार से यह बात करूं तो हम लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, मैं आज कोई दावा नहीं करने वाला और मेरी आदत है कि मैं मर्यादा पार्टी का प्रवक्ता भी हूं लेकिन मैं कभी मर्यादा नहीं तोड़ता और कोई ऐसी बात नहीं कहता जो किसी के दिल पर लगे लेकिन मैं आज यह दावा नहीं करूंगा कि इधर से आलू डालोगे और उधर से सोना निकलेगा, यह दावा मैं नहीं करने वाला हूं । यह मैं इतना आपको उम्मीद दिलाता हूं कि बिहार के लोगों में टेलेंट है, बिहार के लोगों में दम है, बिहार के लोगों से अपेक्षा है, अगर देश तब तरक्की करेगा जब बिहार तरक्की करेगा । जब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा यह देश विकासशील राष्ट्र है लेकिन विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब बिहार तरक्की करेगा और बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए, आवाम के लिए आज मैं इतना कह सकता हूं कि हमने कई क्षेत्रों में नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसिज जो वर्ष 2016 से है उसमें कई सुधार हम कर रहे हैं 20 तक हैं । हमने यहां पर जो इथेनॉल के लिए, मैंने जो कहा यह बात सही है कि इसको कहीं मीडिया अलग मजाक में न ले लेकिन यह सही है कि जो इन्वेस्टर्स बिहार में आयेंगे इधर से मक्का

डालेगा, उधर से उसको डॉलर और पैसा मिलेगा, इधर से गन्ना डालेगा, उधर से इथेनॉल का बाई-बैक यानी जितना अब जो पहले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं । अध्यक्ष महोदय, मैंने उनके साथ, मैं पहले राज्य मंत्री बना था लेकिन मुझे सौभाग्य है कि मेरे प्रधानमंत्री मेरे मंत्री थे अटल जी ने मुझे अपने साथ ही विभाग में रखा था तब मैं फूड-प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री मिनिस्टर था । माननीय संजय झा जी को मालूम है कि अरूण जेटली जी उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करके मजाक उड़ाते थे डब्बा बंद खुराक मंत्री कहा जाता था । लेकिन वह मंत्रालय जब कृषि से जुड़ा तो वह नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ गया और मैंने उनके साथ यह नहीं है कि मैं पहली बार काम कर रहा हूं उनके साथ, मैंने कुछ दिन काम किया लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम ही शाहनवाज है तो मैं जैसे नीतीश कुमार जी के साथ विभाग से जुड़ा तो उनको तुरन्त ईश्वर ने मुख्यमंत्री का पद दिया और वे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने तो वे मुख्यमंत्री बने लेकिन फिर जब वे केन्द्र में लौटें तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है क्योंकि बिहार के बहुत वरिष्ठ लोग केन्द्र में मंत्री थे जॉर्ज साहब थे, शरद जी थे, नीतीश जी थे...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, विषय पर मंत्री जी को बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठ जाइये, बोलिये मंत्री जी ।

(व्यवधान जारी)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: एकदम आ रहा हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: बैठ जाइये, बैठ जाइये । शांति बनाए रखिये ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय जो नये...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: बैठे-बैठे मत बोलिये । फिर, इधर से मत बोलिये ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय जो सदस्य हैं बहुत से नये हैं लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि मैं तीन टर्म पार्लियामेंट में रहा हूं और विषय से भटकूंगा नहीं, मैं विषय पर ही आ रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो आज हमारी सरकार है जैसा मैंने कहा कि इधर से अब वर्ष 2006-07 में यह बात मैंने इसलिए कही कि यह विषय पर ही है, वर्ष 2006-07 में इसका जवाब जरूर तेजस्वी जी जरूर उधर से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा बाद में कि नीतीश कुमार जी ने जो सोचा वह 10 साल तक रोक दिया गया, बिहार की यह स्थिति नहीं होती, एक भी चीनी मिल बंद नहीं होती

जान-बूझकर यह साजिश की गई, बिहार के साथ अन्याय किया गया कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो गन्ना से, आपके समझ में नहीं आया तो मैं फिर डिटेल बता रहा हूं।

अध्यक्ष: मंत्री जी, आप बोलिये ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: गन्ना से इथेनॉल बनाने की भी इजाजत दी जाए क्योंकि चीनी का जो दाम है ऊपर-नीचे होता है, महाराष्ट्र में पूरी को-ऑपरेटिव लॉबी है, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लेकिन आज मुझे सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2006 और वर्ष 2007 में सोचा अभी चंद दिन पहले नरेन्द्र मोदीजी की सरकार ने उसको पारित किया है । अध्यक्ष महोदय, अब जो गन्ना उगाने वाले किसान हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप बैठिए । बिना इजाजत मत बोलिए ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई ऐसी बात कहां कह रहा हूं । मैंने 15 साल उद्योग क्यों नहीं चलाया सबकुछ बोला आप लोगों को नहीं बोला न, कोई दिल पर चोट लगे ऐसी कोई बात नहीं कही न, मैं तो मर्यादा में रहकर बोल रहा हूं तो थोड़ा बोलने दीजिए । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं डेढ़-दो मिनट में भी बात बोल देता हूं । मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं, मुझे पता है कितने मिनट में क्या कहना है तो मैं अपने समय से ज्यादा नहीं जाने वाला । मैं यह कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी अभी ये शुभ सूचना आई और पहली बार मैं असेंबली के फ्लोर पर यह कह रहा हूं कि अब चीनी बनाए बिना भी गन्ना से, मक्का से, टूटे हुए चावल से, एफ0सी0आई0 गोदाम में सड़े हुए चावल से भी इथेनॉल बनेगा, किसान का उपजा हुआ एक भी दाना बरबाद नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी बात है और बिहार में जो लोग कह रहे थे कि चीनी मिल पर ग्रहण है, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी बात को नोट रखिएगा, एक भी चीनी मिल की जमीन ऐसी नहीं बचेगी जो चालू नहीं होगी, वे चीनी भी बनाएंगे और वे इथेनॉल भी बनाएंगे । माननीय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप क्यों बार-बार उठते हैं, बैठिए । माननीय सदस्य बिना इजाजत के आप बार-बार न उठें । आप बैठें ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी बात है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई पॉवर मीटिंग की जिसमें ढाई-तीन घंटा समय हमने लगाया और इसके लिए हमें

इजाजत दी है मुख्यमंत्री जी ने उनका पूरा आशीर्वाद है मुझे । मेरा जितना परिचय है, जितना सामर्थ्य वह मेरा परिचय, मेरा सामर्थ्य 14 करोड़ बिहार के लोगों के लिए हित में काम करने का वह निर्देश है और मैं माननीय मुख्यमंत्री की उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा यह मैं आपको कहना चाहता हूं । हम बहुत सारी पॉलिसी बना रहे हैं, टॉय पॉलिसी बना रहे हैं, खादी पॉलिसी बना रहे हैं, इथेनॉल की बना रहे हैं, थर्मास्ट्रीकल की बना रहे हैं, टैक्सटाईल, आई0टी0, ई0एस0डी0एम0 की पॉलिसी बना रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, फूड प्रोसेसिंग के बारे में, बहुत मुश्किल से एक फूड पार्क पास हुआ था भागलपुर के अंदर वहां पर जो बियाडा की जमीन थी, वहां पर जमीन का कुछ विवाद था वह नहीं हो पाया, लेकिन खगड़िया में शुरू हुआ, हाजीपुर में शुरू हुआ और मैंने पूरा रिव्यू किया है एक भी फूड प्रोसेसिंग पार्क ऐसा नहीं होगा जो चालू नहीं होगा क्योंकि हम किसानों का ध्यान रख रहे हैं । यहां पर किसी साथी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आएगा, इथेनॉल बनाएगा तो उससे क्या हो जाएगा । महोदय, मैं जिम्मेदारी कहना चाहता हूं कि ये सारे निर्णय क्योंकि मुख्यमंत्री जी की हरदम एक जिद रहती है कि जमीन जिस मद में ली गई है उसी मद में उसका उपयोग हो तो फूड, ऐग्रो बेस इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसके साथ इथेनॉल बेस इंडस्ट्री यानी जो भी इंडस्ट्री लगाएंगे उससे किसानों को फायदा होगा इसलिए यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं । जो लाल, हां आपका भी अरे बोलिएगा तो कैसे चालू होगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: महबूब जी बैठ जाइए । माननीय सदस्य आप बार-बार, आप तीन बार उठ चुके हैं ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: अध्यक्ष जी, मेरे पास समय कम है तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बीरेन्द्र जी आप बैठ जाइए । आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं ?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया है हम कई सेक्टर में जा रहे हैं टेक्सटाइल पार्क, लेदर पार्क, फॉर्मेसिटिकल पार्क, फॉर्मेसी में बहुत आगे हैं, यानी बिहारी आगे है तो बिहार पीछे कैसे हो सकता है ? हम इस सदन का उपयोग करते हुए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरी दुनियां में बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप अपनी सरजमीं पर आइए, आपका जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य यहां लगाइए । नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे । जहां तक सिंगल विंडो का सिस्टम है जिनसे भी मैंने बात की है ।

टर्न-27/यानपति-अंजली/05.03.2021

(क्रमशः)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बहुत ही उत्साहवर्द्धक रिपोर्ट है । जो साथी मेरी आलोचना कर रहे हैं उनसे सदन के बाहर हमारे बड़े भाई अब्दुल बारी सिद्दिकी जी ने कहा था कि तीन महीने का वक्त शाहनवाज हुसैन को देता हूं तो मुझे वे नमाज में मिले थे मैंने कहा थोड़ा-सा बढ़ा कर दीजिए, अभी थोड़ा समझना होगा । ऐसी बहुत-सी चीजें मैं श्रवण जी से पूछता रहता हूं तो चीजों को समझना है मैं अध्यक्ष महोदय, पुरानी सिलेट मिटाकर नया सिलेट लेकर आया हूं उस पर नया आयाम लिखना है मुझे । मैं कोई इगो में नहीं रहता हूं, मैं सब का सम्मान करता हूं, मैं सब की इज्जत करता हूं और सब का साथ इस सदन का चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजना है जो बहुत सारी शुरू हुई है । मुख्यमंत्री युवा-युवती उद्यमी योजना के बारे में जो बात थी, उसमें हमलोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अतिपिछड़ा उद्यमी योजना है उसके दायरे को और बढ़ाया है अध्यक्ष महोदय, उसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी शामिल किया है और उसमें सब का साथ और सब का सहयोग उसमें लेने की कोशिश की है । उनको जो 5 लाख, लेकिन जो अनुसूचित जाति, जनजाति इन लोगों को ब्याज नहीं लगेगा लेकिन जो अन्य हमने शामिल किया है उनको एक परसेंट की मामूली ब्याज पर उस योजना में शामिल होंगे । इसमें सवर्ण समाज के लोग भी होंगे हमने यह काम किया है । अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने बहुत-सी चीजों के बारे में हमारे कई सदस्य हैं जो बाहर मिलकर जो उन्होंने कहा है उसको भी हमने एड्रेस करने का काम किया है। जो पहले बंद मिलें थीं, उनके जो मजदूर हैं उनके बारे में बहुत सवालात थे, हम अध्यक्ष महोदय, उनकी पूरी चिंता कर रहे हैं इतना आश्वस्त हम आपको करना चाहते हैं । एक बड़ी सूचना जो मुझे सदन को देनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछली कैबिनेट में एक बड़ा निर्णय हुआ, अखबार की सुर्खियां उसको नहीं छू सकीं लेकिन बड़ा निर्णय किया गया अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर जो है उसके अंदर हमलोगों को जमीन देनी थी, वह बिहार सरकार ने डोभी गया अंचल में डुमरिया के पास 1635 एकड़ भूमि तैयार होने के लिए आई0एम0सी0 के लिए 1149 एकड़ भूमि अधिग्रहित हेतु करीब पहले से हमारी जमीन वहां पर है । लेकिन पिछली कैबिनेट में जब मैं आज बता रहा हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपये दिये हैं और वहां पर जो कॉरिडोर जायेगा जितनी राशि जमीन की हम 400 करोड़ तो और है हमारी पहले से जमीन है वह राशि इसमें केंद्र सरकार भी उसमें जरूर मदद, जितनी राशि हम करेंगे उतना वह करने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने बहुत बड़े मन से बिहार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के इलाके में बहुत काम हुआ है । यहां गया एयरपोर्ट है, यहां पटना एयरपोर्ट है, अभी दरभंगा में एयरपोर्ट बना, हम कोसी के लोगों को वहां जाने में अब और आसानी हुई और जो बागडोगरा का भी एयरपोर्ट है वह एयरपोर्ट भी बहुत समझिए बिहार का ही एयरपोर्ट है यानी बॉडर है वह किशनगंज से आधे घंटे की दूरी पर है । जो इंवेस्टर आयेगा वह एयरपोर्ट भी आता है । इसलिए हर चीजों का मजाक उड़ाना सही नहीं होता है । अध्यक्ष महोदय, जब तक विषय समझ में नहीं आये उस पर बोलना सही नहीं होता है । मैं आपके माध्यम से बहुत बड़ी-बड़ी बातें मैं यहां पर...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, कई बातें जो हैं शाहनवाज जी ने बताया हमलोगों को और ये भारत सरकार में भी मंत्री रहे हालांकि जब ये मंत्री थे तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा । लालू जी के कार्यकाल में 1 लाख 44 हजार करोड़ रुपये का पैकेज मिला लेकिन अभी नहीं मिला । हम इतना जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को चाय कब पिलाइयेगा मोतिहारी के चीनी मिल का...

अध्यक्ष: चलिये माननीय मंत्री जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: दूसरी बात महोदय...

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: देखिए अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: अब समय कम है । पांच बजे ही समाप्त करना है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, हमलोग सोचे थे यहां बैठेंगे शाहनवाज भाई इतने मिलनसार हैं...

अध्यक्ष: अब संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद, नेता विरोधी दल: सभी समस्याओं का समाधान लेकर आये होंगे ये अपनी योजना बतायेंगे कि उद्योग बिहार में कैसे बढ़ायेंगे लेकिन उद्योग पर महोदय कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं, कोई विजन नहीं, कोई ब्लू प्रिंट नहीं...

अध्यक्ष: महबूब जी पीछे हो गए इस बार ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: कि हम कैसे जो है बिहार को आगे ले जाएंगे इसलिए हमलोग जो है वॉकआउट करते हैं महोदय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

अध्यक्ष: जाइये । माननीय मंत्री जी, आप बोलते रहें ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता विजय कुमार चौधरी जी के भाषण में वॉकआउट नहीं करते हैं और हमारे शाहनवाज हुसैन के ही जवाब में, अध्यक्ष

महोदय, मैं यह सोच रहा था कि मेरे विषय में ही वे इस तरह से वॉकआउट करके गए हैं क्योंकि ये जो बात है उद्योग शुरू होने वाला है, उद्योग बढ़ने वाला है ।

अध्यक्ष: अब एक शायरी के साथ समाप्त कर दीजिये ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जिद है कि हम यहां रोजगार लगाकर रहेंगे रोजगार पैदा करके रहेंगे दुनिया की कोई ताकत और कोई वॉकआउट भी उनके हजम-ए-इरादे को बदल नहीं सकता । अध्यक्ष महोदय, मैं एक शायरी के साथ कि

''लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे,
हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे,
गली-कूचे-दरोदीवार बाशिंदे यही होंगे
चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे।''

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जिम्मेदारी के साथ कि जो भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे कंधों पर किया है मैं उनके भरोसे पर शत-प्रतिशत खड़ा उतरूं इसका पूरा प्रयास करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने बिहार के लोगों को एक उम्मीद जो मुख्यमंत्री जी का संदेश है और पूरा मेन्डेट है, यह भी मेन्डेट है कि अगर वह कहीं भी इन्वेस्टर होगा तो दुनिया में कहीं भी जाना होगा वहां भी जायेंगे बिहार फाउन्डेशन के माध्यम से इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस करेंगे बिहार के लोगों का रेड कार्पेट वेलकम करेंगे अगर यहां बड़ी इंडस्ट्री हजार करोड़ से ऊपर लगायेगा खुद मंत्री के तौर पर एयरपोर्ट पर जाकर उसको रिसीव करेंगे और सभा के अंदर उद्योग लगाकर यहां दिखाने का प्रयत्न करेंगे । इसमें कोई शक नहीं कि अब अंधेरा छंटा है और अब उद्योग का उजाला दिखने लगेगा अब चिमनी से धुआं तेजी से निकलेगा और बहुत सी योजना है जो पाइपलाइन में है क्योंकि समय अध्यक्ष जी, इतना ही होता है और मैं समय की सीमा में रह कर ही आपसे मैं यहां वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्त विभाग के मद से जो यहां पर स्थापना के लिये प्रतिबद्ध मद में 105.8496 करोड़, कुल मूल प्राक्कलन 915.8496 करोड़, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये स्कीम मद से 1190 करोड़ और स्थापना प्रतिबद्ध व्यय से 95.176 करोड़ कुल प्राक्कलन 1285.1716 करोड़ (1 हजार 285 करोड़ 17 लाख 16 हजार रुपये) की अनुदान मांग का प्रस्ताव सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''उद्योग विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये 12,85,17,16,000/-(बारह अरब पचासी करोड़ सत्रह लाख सोलह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग स्वीकृत हुई ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-28/सत्येन्द्र/05-03-21

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 05 मार्च, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 39 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021 को 11 बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित की जाती है।